Vol. I
No. 17



Wednesday
17th March, 1954

HYDERABAD LEGISLATIVE ASSEMBLY DEBATES
Official Report

PART II—PROCEEDINGS OTHER THAN QUESTIONS AND ANSWERS

CONTENTS

	Pages
Business of the House	977
Resolution Re: Financial Aid to Handloom Weavers—Adopted as amended	978-987
L. A. Bill No. VI of 1954, the Hyderabad Shops and Establishments (Amendment) Bill, 1954-1st reading negatived ..	987-1000
Resolution Re: Pakistan U.S. Military Pact—Discussion not concluded	1000-1087

GOVERNMENT PRESS
HYDERABAD-DN.
1954

THE HYDERABAD LEGISLATIVE ASSEMBLY

Wednesday, the 17th March 1954

The House met at Half Past Tow of the Clock

[MR. DEPUTY SIEAKER IN THE CHAIR]

QUESTIONS AND ANSWERS

(*See Part* I)

BUSINESS OF THE HOUSE

شری کے - ایل - نرسمہا راؤ (یلندو - عام) - آج نان آفیشیل ڈے (Non Official day) ہے تو ایسی صورت میں آفیشیل بل (Official Bill) کیسے انٹروڈیوس (Introduce) کیا جارہا ہے -

مسٹر ڈپٹی اسپیکر - انٹروڈیوس (Introduce) کرنے میں کوئی ھرج نہیں ہے -

شری کے - ایل - نرسمہا راؤ - جب ایسا ہے تو آفیشیل (Official days) میں نان آفیشیل بلس کیوں انٹرڈیوس نہیں کئے جاتے ؟

Mr. Deputy Speaker : There is a convention to the effect that on non-official days, official motions can also be moved. It does not take much of the time of the House.

Shri K. Ananth Reddy (Balkonda) : According to the rule, when one kind of business is to be taken up, the House cannot take up any other type of business.

Mr. Deputy Speaker : the convention is to allow such official motions.

Shri K. Ananth Reddy : Rules prohibit it.

Mr. Deputy Speaker : Not in this instance.

L.A. BILL NO. IX OF 1954, THE HYDERABAD NURSES, MIDWIVES AND HEALTH VISITORS REGISTRATION AMENDING BILL 1954.

The Mi.ister for Publ'c Health, Medical & Rural Reconstruction (Shri Mehdi Nawaz Jung) : I beg to introduce :

L. A. Bill No. IX of 1954, the Hyderabad Nurses Midwives and Health Visitors Registration (Amending) Bill 1954

Mr. Deputy Speaker : The Bill is introduced.

Resolution Re: Financial Aid to Handloom Weavers.

مسٹر ڈپٹی اسپیکر - کیا بل پہلے لیا جائے یا زیر بحث ریزولیوشن (Resolution) کو پہلے لیا جائے ؟

श्री. व्ही. डी. देशपांडे (अिप्पागुडा) :—पहले रेजोल्यूशन लिया जाय तो बेहतर होगा।

वित्त तथा अुद्योग मंत्री (श्री. वि. के. कोरटकर) :—अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव बुनकरों के बारे में प्रस्तुत किया गया था, अुसके संबंध मे जो कुछ जवाब दिया जा सकता था, वह मै बहुत कुछ दे चुका हूं। अब सिर्फ अिसके बारे में गवर्नमेंट की पॉलिमी क्या हो सकती है अितनाही कहने के लिये मैं खडा हुआ हूं।

अिस प्रस्ताव का पहला क्लाज यह है कि हर अेक बुनकर को सौ सौ रुपये ग्रांट के तौर पर दिये जायें। अिस वक्त की हमारी आर्थिक स्थिति देखते हुअे यह असंभव मालूम होता है। दूसरा क्लाज यह है कि हर प्राथमिक शाखाके मूल धन का चार गुना शेअर कॅपिटल के तौरपर कर्ज दिया जाय। वह भी अिस वक्त की हालत में नामुमकिन है। तीसरा क्लाज यह हैं कि जो कुछ माल बुनकर तय्यार कर रहे हैं अुसका ६० प्रतिशत गवर्नमेंट ले ले। यह अेक नामुमकिन सी चीज है, क्योंकि आखिर यह साठ फीसद कपडा लेकर गवर्नमेंट अुसका क्या करेगी? वह कोअी बिजनेस (Business) तो शुरू नही कर सकती, कि अुसको लेकर बेचा जाय। चौथा क्लाज यह है कि यार्न (Yarn) के अूपर जो सेल्स टॅक्स है वह माफ किया जाय। अिस वक्त हैंडलूम (Handloom) के कपडे पर जो सेल्स टॅक्स है वह तीन रुपये फी गज की हद तक पहले से ही माफ है। यानी पहले से हीं यह टॅक्स अिस पर काफी कम हुआ है। पांचवा क्लाज यह है कि बुनकरों से जो मकानका टॅक्स पेशेकी बाबत टॅक्स वगैरा वगैरा जितने भी टॅक्सेस लिये जाते हैं अुनको भी माफ कर दिया जाय। यह जरा गैरमामूली सी चीज हो जाती है। मेरा जहां तक ख्याल है कि हैदराबाद में बुनकरों से भी ज्यादा गरीब बहुत से लोग हैं। वे भी कहने लगेंगे कि हमको भी यह जुमला टॅक्सेस माफ किये जायें। दूसरी चीज अिसमे यह है कि यह टॅक्स लोकल सेल्फ गवर्नमेंट लेती है। स्टेट गवर्नमेंट को अिसका अेख्तियार नहीं है कि अिन टॅक्सेस को अेकदम बंद कर दें, और यह भी नहीं हो सकता कि यह अिस्तसना अेक खास तबके के साथ रखा जा सके। छटवां क्लाज यह है कि सूत (यार्न) की किमत अेक तृतियांश

घटा दी जाय। आज तो सूत कातते हैं वे जिस तरह से चाहें बेच सकते हैं। गवर्नमेंट को अख्तियार नहीं है कि वह किसी से कह सके कि फलां चीज की किंमत कम करो और दूसरों को बेचो। असके बाद अेडव्हायजरी कमेटी में टेकनिकल परसोनेल याने माहेरेफन रखने के लिये कहा गया है। यह अेडव्हायजरी कमेटी सिर्फ स्किम्स वगैरा बनाने के लिये है, और टेकनिकल अेडवाअिस सिर्फ गवर्नमेंट या आर्ट सेक्शन को दिया जाता है, न कि वीवर्स को या प्रायमरी सोसायटीज को दिया जा सकता है। अिसलिये अेडव्हायजरी बोर्डस् में टेकनिकल मेंबर रखने की जरूरत नहीं है। आठवां क्लाज यह है। कि टेकनिकल ट्रेनिंग का अिन्तजाम किया जाय। अिस वक्त गवर्नमेंट की तरफ से आठ सेंटर्स में टेकनिकल ट्रेनिंग का अिन्तजाम किया जा रहा है, और अुसको जहां तक हो सके और बढाया जायगा। नौवे क्लाज में कहा गया है कि गवर्नमेंट आफ अिंडिया की तरफ से जो सेस फंड हमको मिल रहा है अुसको जहां तक हो सके बढाया जाय। अिसके लिये मैं पहले अेक वक्त सवाल के जवाब में कह चुका हूं कि खुद गवर्नमेंट अिसके लिये काफी कोशिश कर रही है, और कर चुकी है। मगर केंद्रीय सरकार ने अपना अेक खास फार्म्यूला बनाया है, और १९४३ और १९४५ के बीच में हर स्टेट में जो यार्न खर्च किया जाता था, अुसके लिहाज से सबको यह सेसफंड दिया जाता है। और भारत सरकारने यह फैसला किया है कि अिसमें रद्दोबदल नहीं कर सकते। मैं ने अुस वक्त हाअुस के सामने यह भी रख दिया था कि हमको जितने डिसअेडव्हान्टेजेस है अुससे ज्यादा दूसरे स्टेटों को हैं क्योंकि अुनके यहां बुनकर और करघे (लूम्स) ज्यादा होते हुअे भी अुनको हम से कम सेस दिया जा रहा है। बहरहाल अेक अुसूल अुन्होंने बना लिया है और अुसी के तहत यह बंटवारा किया जा रहा है। अुसमें ज्यादा रद्दोबदल करने की कोअी गुंजाअिश अिस वक्त नजर नहीं आती।

(*Mr. Speaker* in the Chair)

अिसी तरह से अिस रेजोल्यूशन में जो अेक तरमीम पेश हुअी है अुसमें भी करीब करीब अिन्हीं मांगों को कुछ फर्क करके रखा गया है। अुसमें पहली मांग यह है कि जहां तक हो सके वीवर्स सोसायटीज को लोन (Loan) दिया जाय। अिसके बारे में मुझे अितना ही कहना है कि गवर्नमेंट ने अिसी वक्त करीब १७ लाख रुपया सेंट्रल वीवर्स सोसायटी को अपनी गैरंटी पर, और रास्त लोन के तौर पर, दिया हुआ है। अिस तरमीम में दुसरा क्लाज यह है कि शेड्यूल्ड बँक्स और रिजर्व बँक की तरफ से कुछ लोन देने की कोशिश करे। अिसके बारे में अितना ही कहना है कि किसी भी सोसायटी को या आदमी को लोन दिया जाता है तो अुनकी कॅपेसिटी देखकर दिया जाता है। और मैंने जैसा कि अभी कहा अिस वक्त १७ लाख के अूपर लोन अपनी गैरंटी पर रास्त गवर्नमेंट ने दिया है। अिससे ज्यादा अपनी गैरंटी पर और लोन दिया जा सकता है या नहीं, अिस पर गौर किया जायगा। गौर नहीं किया जायगा अैसी बात नहीं है। और अिसके पहले जो गवर्नमेंट ऑफ अिंडिया का सेस फंड था अुसमें दूसरी अेक स्कीम निकाली गअी है, अुसके आने के बाद अिसमें कुछ और अिमदाद मिलेगी अैसी अुम्मीद है। अिसलिये अिस क्लाज के तहत आज कोअी कार्यवाही करने की जरूरत नहीं है। तीसरे क्लाज में यह कहा गया है कि जहां तक हो सके गवर्नमेंट अपनी खरीद का खाता हैंडलूम कपडे तक ही महदूद रखे। गवर्नमेंट ने अिसके बारे में पहले ही अेक रेजोल्यूशन कर लिया है, और अब तक दो बार हाअुस के सामने में अिसके बारे में कह चुका हूं। अिस साल से हुमने अिसके सिलसिले में प्रोवीजन भी ज्यादा किया है, और गवर्नमेंट की जरूरियात के लिये सब से पहले खादी को प्रिफरन्स दिया जायगा। अगर खादी न मिल सके तो हैंडलूम के कपडे को प्रिफरन्स

दया जायगा। और अगर दोनों में से कोअी कपडा मुहैया न हो सके, तो फिर मिल क्लाथ लिया जायगा। अिसमें अेक और तरमीम की गअी है कि गवर्नमेंट लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को यह सिफारिश करे कि वीवर्स का हाअुस टॅक्स और प्रोफेशन टॅक्स वगैरा माफ कर दिया जाय। बहरहाल मैंने पहले ही कहा कि यह अेक प्रिन्सिपल की मांग है। वह किसी तरह से अिक्वीटेबल्ल बेसिस पर नहीं ठहर सकती। अेक तबके के लिये कहना कि अुनसे प्रोफेशन टॅक्स न लो, और दूसरों से लेते जायेंगे, तो यह गैरसही मालूम होता है। लेकिन अगर हाअुस अिस तरमीम को पास करता है तो अुसको लोकल सेल्फ गवर्नमेंटस् की तरफ भेज दिया जा सकता है। अिससे ज्यादा मैं कुछ आश्वासन नहीं दे सकता। यार्न सप्लाय के बारे में यह कहा गया है कि वह सस्ता दिया जाय। मैंने पहले ही यह कहा था कि ये जो कन्सर्न्स हैं अुनका आपसी संबंध है। और जहां तक हो सके गवर्नमेंट अुसमें जब तक कोअी खास वजह पैदा न हो जाय अुस वक्त तक जानबूझकर दस्तंदाजी नहीं कर सकती। अिस तरमीम के क्लाज सात में कहा गया है कि टेकनिकल परसोनेल अेडव्हायजरी कमेटी में शरीक किये जायें। मेरा कहना है कि अगर अैसी ही मांग हो तो अेडव्हायजरी कमेटी में किसी टेकनिकल आदमी को रखना गवर्नमेंट कबाहत नहीं समझती। लेकिन कहना अितना ही है कि अेडव्हायजरी बोर्ड में, जैसा कि मैंने पहले कहा, किसी टेकनिकल अेडव्हाअिस की जरूरत नहीं होती। अेडव्हायजरी बोर्ड को कौनसी स्कीम में कितने फंड डालने चाहियें अितना ही देखना पडता है। टेकनिकल अेडव्हायजर्स की जहां जरूरत है, अुन आठ सेंटरों में वह हैं। वहां वे रखे गये हैं, और अुनसे अिमदाद ली जा सकती है। अिसके बाद आठवें क्लाज में यह है कि ट्रेनिंग के लिये अिन्तजाम किया जाय। अिसके बारे में मैंने कहा कि जितना अिन्तजाम हो सकता है अुतना किया गया है। नौवें क्लाज में यह है कि गवर्नमेंट ऑफ अिंडिया के सेसफंड में से जो कुछ ज्यादा हिस्सा मिल सकता है, अुसके लिये कोशिश की जाय। मैंने बताया कि कोशिश की गअी है लेकिन अब तक अुन्होंने नहीं माना है। लेकिन कोशिश बराबर जारी रहेगी। दसवीं मांग अिसमें बढाअी गअी है। अिसके बारे में मुझे शुब्हा है कि यह तरमीम के तौर पर यहां कैसे आ सकती है। क्योंकि असली रेजोल्यूशन में यह मांग नहीं थी। अिसलिये अुसको अमेंड करने का यह तरीका नहीं हो सकता। लेकिन यह मसला वीवर्स कॉन्फरन्स की तरफ से पहले कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के पास गया हुआ है, और अुस पर गौर हो रहा है। अिन चंद चीजों को कहने के बाद मैं अैवान की तवज्जे और अेक चीज की तरफ ले जाना चाहता हूं कि सेसफंड के जरिये से बुनकरों को बहुत काफी मदद अिस वक्त दी जा रही है। साढे बारा लाख रुपये के करीब जुदा जुदा स्कीम्स में ये खर्च किये जा रहे हैं। यह मदद १९५३-५४ में दी गअी है, और अुसी तरह से सेसफंड से अिस साल भी मदद अुनको मिलेगी। यह जो मदद अुनको मिल रही है अुसको देखते हुअे और कोअी खास ज्यादा लोन या ग्रांट वगैरा की जरूरत पडेगी अैसा मैं नहीं समझता। यह मदद किस तरह से दी गअी है अुसका ब्यौरा मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। प्रोडक्शन-कम-सेल्स अेकटीविटीज के लिये ६ लाख ५० हजार, मार्केटिंग स्कीम्स के लिये ९१ हजार, लूम्स को बदलने के लिये १ लाख २५ हजार, मोबाअिल व्हॅन्स के लिये ५२ हजार, पब्लिसिटी के लिये १० हजार, अिस तरह से दिये गये हैं। अितना देने के बाद कपडे के दामों को घटाने के लिये सबसिडी के तौर पर ३ लाख रुपये और दिये गये हैं। अिस तरह से जुमला साढेबारा लाख होते हैं। अिसी तरह से १२ लाख २८ हजार रुपये अिन स्कीमों के लिये अिस साल के लिये मंजूर हो चुके हैं। और अगले साल भी अिसी तरह की अिमदाद दी जाने की पूरी पूरी अुम्मीद है। गवर्नमेंट का जो दृष्टिकोण था वह मैंने हाअुस के सामने रख दिया है।

శ్రీ పెండెం వాసుదేవ్—(గజ్వేల్) :

అధ్యక్ష మహాశయా,

నేను ఈ తీర్మానం ప్రవేశపెట్టినప్పుడు, ప్రభుత్వం కొంతవరకైనా చేనేత పారిశ్రామికుల యొక్క సమస్యలను పరిష్కరించేందుకు ముందుకు వస్తుందని కొండంత ఆశతో ఈ తీర్మానం తీసుకు వచ్చాను. చివరికి 'డబ్బులేదనే' పాత పాటనే ఆర్థికశాఖా మంత్రిగారు పాడారు ఈమోస్తరు ప్రభుత్వ ధోరణి చాలా విచారాన్ని కలిగిస్తోంది. ఈ రోజున కరువు కాటకాల లో పారిశ్రామికులు చిక్కుకొని నానా యిక్కట్లు పడుచున్నారు. తోటి రాష్ట్రాలలోని ప్రభుత్వ ఆదరణ చూస్తున్నాం. చేనేత పారిశ్రామికులను అన్ని విధాలా రక్షించడానికి వారివద్దనుంచి వృత్తిపన్ను, ఇంటిపన్ను తీసుకొనకుండా వుండడానికి నూతనంగా ఏర్పడ్డ ఆంధ్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిశ్చయించింది. ఆ సంగతులన్నీ మన ఆర్థికమంత్రిగారికి విన్నవించినప్పటికీ ఇక్కడ సాధ్యపడదని సెలవిచ్చారు. అయితే నేను ప్రవేశ పెట్టిన తీర్మానంలోని ఒక్కొక్క కోర్కెను తీసుకొని, వాటిని ఎందుకు ప్రవేశపెట్టానో ఎక్కువ టైము తీసుకొనకుండా చెబుతాను. చేనేత పారిశ్రామికులకు ప్రతి ఒక్కరికి నూరు రుపాయలు చొప్పున వడ్డీలేకుండా దీర్ఘకాల వాయిదాలమీద అప్పు యివ్వాలని కోరాను. దీనికి సవరణగా, ఆ నూరురూపాయల అప్పు పారిశ్రామికునికి కాకుండా ప్రాథమిక సంఘాలలో పారిశ్రామికునిపేర వాటాధనంగా జమకట్టించాలని సవరణ వచ్చింది. ఈ నాడు మన సంస్థానంలో వున్న ప్రాథమిక సంఘాలు పూర్తి అధ్వాన్న పరిస్థితిలోకి రావడం జరిగింది. దానికి రెండు కారణాలున్నాయి. ఒకటి ఈనాటి ఆర్థిక సంక్షోభం అది ప్రధానమైన కారణం. రెండవది, ఆ ప్రాథమిక సంఘాలు స్వార్థపరుల చేతుల్లో యిరుక్కుపోయాయి. ఈ నాడు ప్రాథమిక సంఘాల్లో పారిశ్రామికునకు తన వాటాధనం రూ. 30 లు తన కళ్ళకు కనపడకుండా హరించిపోయే పరిస్థితి ఏర్పడింది. ఈ పరిస్థితుల్లో పారిశ్రామికునికి అప్పుగా యివ్వాలన్న నూరు రూపాయలు, వాటాధనం క్రింద ప్రాథమిక సంఘాల్లో జమకట్టడంవలన, దానిని స్వార్థపరులు దిగమ్రింగి చివరకు పారిశ్రామికునికి ఏమాత్రం లాభం కలగకుండా పోతుంది. కాబట్టి ఆ సవరణను పూర్తిగా వ్యతిరేకిస్తున్నాను. ఆ నూరు రూపాయలు పారిశ్రామికునికే అప్పుగా యిచ్చేందుకు ప్రభుత్వం ప్రయత్నిస్తే ఏదోవిధంగా పారిశ్రామికుడు గిట్టుబాటుగాకపోయినా ఎక్కువధరైనా పెట్టి నూలునుకొని గుడ్డ తయారు చేసి అంగట్లో అమ్ముకొని కొంతవరకైనా యీ కరువు నుంచి బయటపడేందుకు అతనికి అవకాశం వుంటుంది. పారిశ్రామికుని చేతులో డబ్బు పడితే, దానిని చెడగొట్టుకునే ప్రమాదం వుందని అంటున్నారు. ప్రభుత్వంవద్దనుంచి పూచీపడి తీసుకొన్న డబ్బును చేనేత పారిశ్రామికుడు దిగమ్రింగేస్తాడని మనం భయపడవలసిన పనిలేదు. కాబట్టి ఆ సవరణ తెచ్చిన వారిని ప్రార్థిస్తున్నాను. మనం అందరం కలసి ఏకాభిప్రాయంతో మంత్రిగారిపై వత్తిడి తీసుకువచ్చి, పారిశ్రామికునికే ఆ నూరు రూపాయలు, వడ్డీలేకుండా దీర్ఘవాయిదాలమీద తీర్చుకునే పద్ధతిని అప్పు యిప్పించేందుకు ప్రయత్నించాలని, ఆ సవరణను ఉప సంహరించుకోవాలని, కోరుతున్నాను.

వారు తెచ్చిన రెండవ సవరణలో వీవర్సు కోఆపరేటివ్ సొసైటీలకు ప్రభుత్వం అప్పులు యిప్పించాలని కోరారు. అసలు ప్రజల సమస్యలు ప్రభుత్వం తీర్చవలసిన ఆవసరం కలిగినప్పుడు

డబ్బులేదని చెప్పి తప్పించుకోవడం ఈ ప్రభుత్వానికి అలవాటైపోయింది. కాబట్టి ప్రాథమిక సంఘాలకు అప్పులిప్పించేందుకు యీ ప్రభుత్వం ప్రయత్నం చేస్తుందా ? ముఖ్యంగా పారిశ్రామికులను దృష్టిలో పెట్టుకొని, ప్రాథమిక సంఘాలకు కూడా అప్పులు యిప్పించేందుకు యీ ప్రభుత్వం ప్రయత్నం చేయాలని కోరుతున్నాను. కేంద్ర సంఘానికి ౧౩ లక్షల ౹౦ వేలు అప్పు యిచ్చామని చెప్పారు. నిజమే. ఆ డబ్బు కేవలం కేంద్ర సంఘానికి అప్పుగా యిచ్చినంత మాత్రాన ౧౮౦ ప్రాథమిక సంఘాలయొక్క ౧ లక్ష 30వేల పారిశ్రామికుల యొక్క సమస్య పరిష్కారం అయిందని అనుకోవడం సరైనదీ కాదు. ఈ ప్రాథమిక సంఘాల్లో డబ్బులేకుండా మూలధనానికే ముప్పు వాటిల్లే పరిస్థితి దాపురించింది. కాబట్టి ప్రాథమిక సంఘాలకు డబ్బు అప్పు యిప్పించాలని కోరుతూ, నా తీర్మానంలో ఏదైతే రెండవ కోరిక వున్నదో దానిని అంగీకరించాలని కోరుతున్నాను. దీనికి తేబడిన సవరణ, పోటీగా తెచ్చారని అననుగాని, వేరే స్వరూపంలో తేబడిన సవరణను ఉపసంహరించుకోవాలని కోరుతున్నాను.

నా తీర్మానంలో మూడవ కోరికలో ప్రభుత్వానికి అవసరమయ్యే గుడ్డలో సగభాగం చేనేత గుడ్డను కొనాలని పెట్టాను. మద్రాసు, ఆంధ్ర రాష్ట్రాలలో కూడా ఈ విషయాన్ని దాదాపు అక్కడ ప్రభుత్వాలు అంగీకరించి అమలులో పెడుతున్నాయి. కాబట్టి నేను కోరేది ప్రభుత్వావసరాలకు కావలసిన గుడ్డలో సగభాగం చేనేత గుడ్డను కొని వాడాలని కోరుతున్నాను. నేను మంత్రిగారితో మాట్లాడినప్పుడు, చప్రాసీల డ్రెస్సుకు, రుమాళ్లకు దానికి, కొంత గుడ్డ అవసరంవస్తుంది, దానికి చేనేత గుడ్డను కొనాలని కోరాను. ప్రభుత్వానికి కావలసినటువంటి రకాలుచేనేత వారు తయారు చేయజాలరనే దిగులు, సంశయంపెట్టు కోనవసరం లేదు. ఏ రకం గుడ్డ నయినా, మీ ముఖం కూడా కనపడే గుడ్డను, తయారు చేసే నిపుణత్వం, నేర్పరితనంగల నేతవారున్నారు కాబట్టి ఎటువంటి గుడ్డ కావాలో అటువంటి డిజైను ప్రైమరీ సొసైటీల (Primary Societies) కిచ్చి నేయించుకొని, ప్రభుత్వావసరాలలో సగభాగం నేతగుడ్డ కొని తీర్చు కోనేందుకు ప్రయత్నం చేయాలని మనవి చేస్తున్నాను. చేనేత పారిశ్రామికులు మిలిటరీ డ్రెస్‌ను తయారు చేస్తారా ? పోలీసు డ్రెస్‌ను తయారు చేయగలరా అని అనుమానంపెట్టుకోకండి. ఎటువంటి రకం గుడ్డనయినా తయారు చేసి యివ్వగల నేర్పరితనం చేనేత పారిశ్రామికులకున్నది. ముఖ్యంగా యిటువంటి జాతీయ పరిశ్రమలను ప్రోత్సహించి ప్రభుత్వావసరాలను తీర్చుకొనవలసిన బాధ్యత ప్రభుత్వం మీద వున్నది. కాబట్టి ప్రభుత్వానికి కావలసిన గుడ్డలో కనీసం సగంభాగమైనా నేత గుడ్డనుకొని వాడాలని కోరుతున్నాను. దీనికి కూడా ఒక సవరణ వచ్చింది. ఆ సవరణ తెచ్చినవారుకూడా నేత గుడ్డను ప్రభుత్వంవారు కొనాలని అంగీకరించారు. నేను కోరినది సగభాగం కొనాలని, కాని వారు తెచ్చిన సవరణలో పూర్తిగా చేనేత గుడ్డను, ఆలిండియా ఖాదీ సంఘం సర్టిఫై చేసిన గుడ్డను కొనాలన్నారు. ప్రభుత్వానికి కావలసిన గుడ్డనంతా చేనేత గుడ్డనే కొనాలని కోరడం నాకూ సంతోషమే. కాని వారి సవరణలో యింకొక విషయమేమంటే ఆలిండియా ఖాదీ సంఘం సర్టిఫై (Certify) చేసిన గుడ్డను కొనాలన్నారు. అటువంటి సర్టిఫైడ్ గుడ్డనూ, సహకార సంఘాలద్వారా తయారైయిన చేనేత గుడ్డనూ ప్రభుత్వావసరాలకు పూర్తిగా కొనాలని సవరణ పెట్టారు. కాని అటువంటి [illegible] పారిశ్రామికులు వెలుపల కూడా

వున్నారు. చేనేత పారిశ్రామికులందరూ సహకార సంఘాలలో లేరు. వారందరినీ సంఘటిత పరచి సహకార సంఘాలలోకి తీసుకురావలసినదే. కాని మన పైనకూడా కొంత కర్తవ్యమున్నది. మన ప్రవర్తన పైన, మన కార్యకలాపాల పైనా ఎంతో మంది వెలుపల వున్న పారిశ్రామికులు అనుమానం పడుతున్నారు. వారికి ఆ విధంగా అనుమానం లేకుండా చేయాలంటే వారికి అన్నివిధాలా తోడ్పడే విషయంలో మనం కృషి చేస్తున్నామని వారికి నమ్మకం కలగాలంటే మన విధానాల్లో, ప్రవర్తనలో మార్పు రావాలి. ఈనాడు సహకార సంఘాలలో నున్న విధానాలు, అక్కడి పద్ధతులు చాలా అవకతవకగా వుండుటవలన పారిశ్రామికులకు సహకార సంఘాలు ధ్యెయ్యంలా గంత కట్టుకొన్నట్లు కనబడుతున్నాయి. ఈ సహకార సంఘాలు వచ్చిననాటినుండి పారిశ్రామికులకు రవ్వంతైనా లాభం కలిగించే పరిస్థితులు ఏర్పడలేదు. పారిశ్రామికుడు సహకార సంఘాన్ని అది 'నాది' అని అనుకొనేందుకు వీలు లేకుండా, స్వార్థపరులు చేరి ఆ విధంగా చేయడం జరిగింది. కాబట్టి వీటిల్లో ఎంతోమార్పు రావలసివుంది. కేవలం సహకార సంఘాలలో తయారయిన గుడ్డనే ప్రభుత్వం కొనాలనే నిర్బంధం పెట్టవద్దు. పారిశ్రామికుల నందరినీ క్రమేపి సహకార సంఘాల్లోకి తీసుకురావడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం. సహకార సంఘాల్లో చేరనంత మాత్రాన్న మీగుడ్డ కొనం అని అనడం సబబు కాదు. ఈ విధంగా నిర్బంధం పెట్టడం సరైనది కాదు. కాబట్టి ఆ సవరణ ఉపసంహరించుకోవాలని సవరణ తెచ్చినవారిని కోరుతున్నాను.

తరువాత సేల్సుటాక్సు మినహాయింపు విషయంలో మొన్ననే మార్చి ౭వ తేదీన పార్లమెంటులో ఒక ప్రశ్న వేసినప్పుడు కేంద్ర పరిశ్రమల మంత్రి కృష్ణమాచారిగారు అంగీకరించారు. సేల్సుటాక్సునుంచి చేనేత గుడ్డను మినహాయించ వలసినదిగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు సలహా లిస్తున్నామన్నారు. తరువాత నూలుగుడ్డపైన, నూలుపైన సేల్సు టాక్సు రద్దుకాకుండా వున్న రాష్ట్రాలపేర్లు కృష్ణమాచారిగారు ఆ ప్రశ్నకు జవాబులో చదివారు. ఆ లిస్టులో హైదరాబాదు పేరు లేదు. అనగా హైదరాబాదులో సేల్సు టాక్సు నేత గుడ్డపైన రద్దు చేశారని ఆ జవాబు వలన అర్థమౌతోంది. ఇక్కడ నూరు రూపాయలపైనుండే అమ్మకాలకు తీసుకుంటున్నా మంటున్నారు. సేల్సు టాక్సు పూర్తిగా నూలుపై నుండి, నేతగుడ్డపై నుండి రద్దు చేసేందుకు ఆంధ్రరాష్ట్ర ప్రభుత్వం అంగీకరించినట్లు పత్రికల్లో వార్త వచ్చింది. మన ప్రభుత్వం ఆ ఒక్క కోరికనైనా అంగీకరించేటట్లు కనపడదు. కాని హైదరాబాదు సంస్థానంలో వున్నటువంటి ప్రజానీకాన్ని అణగద్రొక్కేందుకు వారిపైన ఎక్కువ పన్నులు వేసి ఖజానా నింపి ఉన్నతోద్యోగులను పోషించేందుకు మాత్రం ఈ ప్రభుత్వం హైదరాబాదు వెలుపలనున్న అన్ని రాష్ట్రాలలోని అధ్వాన్న పరిస్థితిని వెదికి వెదికి యిక్కడపెట్టే ప్రయత్నం చేయడం అలవాటైపోయింది. వెలుపల రాష్ట్రాలలో ప్రజలయొక్క అవసరాలు తీర్చేందుకు ఎటువంటి అభివృద్ధికర చర్యలు ఏ ప్రభుత్వాలు తీసుకుంటున్నాయో వాటిని మాత్రం గ్రహించి తీసుకొనేందుకు ఈ ప్రభుత్వానికి అలవాటు లేకుండా పోయింది. ప్రక్కనున్న ఆంధ్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పూర్తిగా చేనేత పారిశ్రామికులను ఇంటి పన్నునుండి, వృత్తి పన్నునుంచి మినహాయించింది. ఆ ప్రకారం మన ప్రభుత్వంకూడా చేనేత పారిశ్రామికులకు ఇంటి పన్ను వృత్తిపన్ను మిన

హాయించాలని కోరుతున్నాను. అంతేగాక ఆంధ్రరాష్ట్ర ప్రభుత్వం ౨౫ లక్షల రూపాయలు చేనేత గుడ్డను కొనేందుకు అంగీకరించారు. అక్కడ కోటి రూపాయల నేత గుడ్డ మిగిలి పోయివున్నది. చేనేత కాంగ్రెసు అధ్యక్షులు ప్రగడ కోటయ్యగారి కోర్కెప్రకారం, ఆంధ్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, ఆ గుడ్డ క్రయ విక్రయాలకు సహాయం చేయాలని కోరితే ౨౫ లక్షల సహాయం చేసింది. కాని ఈ ప్రభుత్వం మాత్రం, ఇక్కడ చేనేతగుడ్డ విడుదల కాకుండా పడిపోయివున్నప్పటికీ, ఎటువంటి సహాయం చేసేందుకు ప్రయత్నించడం లేదు. నేను ముఖ్యంగా కోరేది సేల్సు టాక్సునుంచి పూర్తిగా నేతగుడ్డను, నూలును మినహాయించాలని కోరుతున్నాను. సింగిల్ పాయింటుటాక్సు, నూరురూపాయలపైన అమ్మకాలకు తీసుకుంటున్నామంటే పరిపోదు. పూర్తిగా నేతకు ఉపయోగించేనూలు పైన, నేతగుడ్డపైనా సేల్సుటాక్సు రద్దుచేయాలని కోరుతున్నాను. దీనికి ఒక సవరణ వచ్చింది. సహకార సంఘాలలో వుంటున్న వారు తయారు చేసిన గుడ్డకు మాత్రమే ఆ సంఘాలలోని నూలుకు మాత్రమే సేల్సుటాక్సు (Sales Tax) రద్దు చేయాలని సవరణ తెచ్చారు. వెలుపలవున్న చేనేత పారిశ్రామికుల నందరినీ సహకార సంఘాలలోకి తేవాలనే సూత్రం నేనుకూడా పూర్తిగా అంగీకరిస్తాను. వాళ్ళ నందరనూ సంఘటితపరచి వాళ్ళ కోర్కెలను సాధించడానికి బలవత్తరమైన సంఘం ఏర్పాటు చేయవలసినదే. మనమందరం కలసి ప్రభుత్వంపైన వత్తిడి తెచ్చేందుకు ప్రయత్నించవలసినదే కాని వెలుపలవున్న పారిశ్రామికులను మనం నిర్బంధ పెట్టవద్దు. వారికి ముందరే బెదురుగా చెప్పవద్దు. మనం అవలంబించే విధానాలవలన సత్ప్రవర్తన వలన వారు సహకార సంఘాల లోకి రావడం జరుగుతుంది. కాబట్టి వారు తెచ్చిన మొదటి నాలుగు సవరణలూ ఉపసంహ రించుకోవాలని నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. అయితే ఆ నాలుగు సవరణలతరువాత వున్న సవరణల నన్నింటినీ అనగా ౫, ౬, ౭, ౮, ౯, ౧౦ సవరణలను నేను పూర్తిగా అంగీకరిస్తున్నాను. ఆ నాలుగు సవరణలు మాత్రం నేను అంగీకరించలేదనే దిగులుపెట్టుకొని వేరే అభిప్రాయం కలిగించు కోవద్దని కోరుతున్నాను. వారి అయిదవ సవరణనుంచి క్రింది వరకు పూర్తిగా అంగీకరించాను కాబట్టి వారు పైవాటిని ఉపసంహరించుకొని తీర్మానాన్ని ఏకగ్రీవంగా సర్వసమ్మతంగా వుండే టట్లు అంగీకరించి సహకార సంఘాల వెలుపల వున్నవారికి కూడా సహాయంచేసేందుకు ప్రభుత్వం వారిని కోరుతున్నాను. ఇవ్వాళ ఏదో సమాధానం చెప్పి తప్పించుకొనేందుకు ప్రయత్నించడం మంచిదికాదు. పారిశ్రామికులను అధ్వాన్న పరిస్థితులనుండి బయటకు తేవాలంటే వారికి ఆర్థిక సహాయం చేయడం అత్యావసరం. ప్రభుత్వం డబ్బులేదనే సాకుచెప్పి తప్పించుకోడానికి వీల్లేదు. మేము ఇక్కడ అనేక సార్లు చెప్పాము. కోటానుకోట్లు వ్యయపరుస్తున్న అనవసర ఖర్చులు తగ్గించుకోండి; నైజాంకిచ్చే కోటిరూపాయలు ఒక సంవత్సరం ఆపండి, జాగీర్దార్లకు ఇనాందార్లకిచ్చే నష్టపరిహారం ఆపి చేనేత పారిశ్రామికులకు సహాయంచేసి ప్రస్తుత దుస్థితినుండి బయటకు తెండని, పదే పదే చెప్పాం. పైగా మంత్రిగారేమి చెబుతున్నారంటే వారికిస్తే వీరికివ్వ వద్దా, వీరికిస్తే వారికివ్వవద్దా, ఈ చేనేత పారిశ్రామికులకు సహాయంచేస్తే యింకొక పరిశ్రమ వారికి సహాయం చేయవద్దా? అని అంటున్నారు. అందరికీ సహాయం చేయవలసినదే. హైదరాబాదులో వున్నటువంటి ప్రజానీకంలో ఈ నాడు ఎవరూ నిరుద్యోగులుగా వుండవద్దు. రెండు పూటలా తిండి లేకపోయినా, కనీసం ఒకపూటైనా కడుపునిండా తిండి లభించేందుకు మనం [illegible] చేయాలి. కొన్నికోట్ల [illegible] అనవసరంగా [illegible]వారి ఖర్చులు, తగ్గించండి,

నైజాంవద్దవున్న కోటానుకోట్లు అప్పు తీసుకోండి. దానిని మన రాష్ట్రములోని పరిశ్రమలపై ఖర్చు పెట్టండి. ఎప్పుడు చూసినా, డబ్బు లేదు, డబ్బులేదు, అనే దివాళాకోరుతనం చూపెట్టడం అలవాటైపోయింది. ఈ విధంగా చులకనగా తప్పించుకొనే పద్ధతి సరైనది కాదు. కాబట్టి పారిశ్రామికులకు అన్ని విధాలా సహాయం చేసేందుకు ప్రభుత్వం ముందుకురావాలని కోరుతున్నాను. ఈ సవరణలలో ఒకటిమొదలు నాలుగువరకు ఉన్న సవరణలు ఉపసంహరించుకొని మిగతా సవరణలతో ఈ తీర్మానాన్ని ఏకగ్రీవంగా అందరు గౌరవ సభ్యులూ అంగీకరించాలని కోరుతూ యింతటితో నా ఉపన్యాసం ముగిస్తున్నాను.

Mr. Speaker: I shall first put the amendment of Shri L. B. Konda to vote.

شری پنڈم واسدیو ۔ امنڈمنٹ کلاز بائی کلاز ووٹ پر رکھئیے کیوں کہ چند امنڈمنٹس کو میں نے قبول کیا ھے ۔

Mr. Speaker: I shall put it to vote paragraph-by-paragraph. The question is:

"For para 1 of the Resolution, substitute the following, namely—

'1. Financial aid in the form of loans be granted to member weavers of Weavers' Co-operative for increasing their share capital to promote production activities;'"

The motion was adopted.

Mr. Speaker: The question is:

"For para 2 of the Resolution, substitute the following, namely—

'2. The Government should arrange for loans to the Weavers' Co-operatives—

(*i*) by giving guarantees to Scheduled Banks;

(*ii*) from Reserve Bank

for yarn dealings and marketing of handloom products;'"

The motion was adopted.

Mr. Speaker: The question is:

"For para 3 of the resolution, substitute the following namely—

'3. The Government should purchase handloom products from Weavers' Co-operatives and Khadi from certified producing concerns only to meet all its requiries ;' "

The motion was adopted.

Mr. Speaker : The question is :

"For para 4 of the resolution, substitute the following, namely—

' 4. Yarn and handloom products handled by the Weavers' Co-operatives be exempted from Sales-tax and arrears be waived ; ' "

The motion was adopted.

شری پنڈم واسدیو- ۵ سے لیکر ۱۰ تک امنڈمنٹس میں قبول کرلیا ہوں-

Mr. Speaker : The remaining paragraphs of the amendment, *viz*—

"For paras 5 to 9 of the resolution, substitute the following :—

' 5. The Government should advise the Local Self Government bodies to exempt the weavers from the imposition of taxes such as House Tax, Profession Tax, etc ;

6. The State Government should arrange yarn supplies to the Weavers' Co-operatives at concessional rates, from local mills as well as from the mills outside the State by approaching the Central Government ;

7. The present Advisory Committee may suitably be expanded by associating more technical personnel with it ;

8. Preference for training should be given in the Technical Training Centres of Commerce & Industries Department to the nominees of Weavers' Co-operatives as well as training in dyeing, bleaching and finishing be extended in the Centres ;

9. (*a*) The Central Government be requested to revise the formula applied in determining the quota of each State from the Cess Fund and allot full amount due to the Hyderabad State,

(*b*) Since Hyderabad is an undeveloped area in the Handloom Industry the Central Government be requested to allot amounts from the Special Reserve Cess Fund earmarked for backward areas ;

10. Audit fees payable by Weavers' Co-operatives be waived and the Weavers' Co-operatives be exempted from payment of Audit fees till the end of June 1957."

have been accepted by the Mover of the resolution himself as such they need not be put to vote.

The question is :

" That the resolution as amended be passed. "

The motion was adopted.

L. A. Bill No. VI of 1954, the Hyderabad Shops and Establishments (Amendment) Bill, 1954.

Mr. Speaker: I would like to know whether the House would like to take up first the Hyderabad Shops and Establishments (Amendment) Bill, 1954, introduced by Shri V. D. Deshpande or the next non-official resolution.

Shri V. D. Deshpande : I think we should take up the Bill first because we can finish it earlier and then we can take up, the other resolution.

The Minister for Public Works and Labour (*Dr. G. S. Melkote*) : I have no objection to the Bill being taken up first.

Shri V. D. Deshpande : I beg to move :

"That L.A. Bill No. VI of 1954, the Hyderabad Shops and Establishments (Amendmet) Bill, 1954, be read a first time."

Mr. Speaker : Motion moved.

*श्री. व्ही. डी. देशपांडे :–अध्यक्ष माहोदय, यह जो अमेंडमेंट बिल है अुसके लिये लेबर मिनिस्टर का मुझे सब से पहले शुक्रिया अदा करना चाहिये, क्यों कि अुन्होंने कम से कम फर्स्ट रीडिंग तक अिस बिल को हाअुस के सामने आने के लिये मौका दिया है।

I think it will be convenient for the Minister to reply if I speak in English.

This Bill seeks to amend section 36 of the Shops & Establishments Act. I shall first place before the House the object with which the Shops & Establishments Act had been enacted. The workers in factories received protection under the Trade Union Act of 1926 under which they were allowed to organise themselves and certain facilities were given to them. But the employees in shops and establishments, cinemas and other places of employment did not come under the purview of the Factories Act and also had not got the benefit of the provisions of the Act of 1926. So, it was thought necessary that there should be some Act to regulate the conditions of the employees in Shops and other Establishments and with this view the Government of Hyderabad and other State Governments in India promoted legislation under the name of the Shops & Establishments Act. As the preamble of this Act states, it was thought expedient to provide for the regulation of conditions of work in shops, commercial establishments, restaurants, theatres and other Establishments. After seeing the working of this Act in the last two years, we are feeling that certain sections of this particular Act should be amended. I had brought up a Bill similar to the present one sometime back before the House, but unfortunately, the Members on the Treasury Benches at that time did not allow it to come even to the stage of first reading.

I should like to point out to the House that unless we are of the opinion that the objectives with which this legislation was enacted should be done away with, we should have absolutely no objection to remove certain lacuna in that particular legislation. The question is, do we want that certain facilities which were intended to be given under this particular Act should be available to the employees or not? Under the Act we have provided certain restrictions

regarding the hours of work, that no employee should be made to work for more than 8 hours. Similarly, certain provisions regarding holidays are there. Recently, *i. e.*, about an year or so back, this House had passed an amendment to section 36 of the Act whereby a gratuity has to be given to workers who are removed from service without sufficient cause and it should be our purpose and duty to remove any lacuna that may be found in the Act. The Amending Bill which I have moved for first reading in this House incorporates this view. In the course of our experience during the last year and a half in organizing the employees in hotels, we have found that there is no protection in any section of this Act against dismissal or discharge of the workers for reasons other than misconduct, and we find that invariably the employers are resorting to dismissal of the workers after paying some gratuity. I can point out three such cases—one in Hyderabad and two in Secunderabad—where active workers of the Hotel Workers Union were removed by the employers, just because they felt that their presence in the hotel would be detrimental to their interests and feared that if an organised union existed the employers might be compelled to enforce the conditions of work of 8 hours a day and would have to provide other facilities.

Therefore, under the plea that they did not require the services of a particular employee and without giving any reason for his removal, taking shelter under the particular section that if they paid gratuity of 15 days wages per year of service they could dispense with the services of an employee, these employers removed them from service. The instances which I refer to are the cases of the Modern Cafe, Secunderabad and another Cafe—probably City Cafe. I have brought these cases to the notice of the former Labour Minister and even to the present Labour Minister and also to the Deputy Labour Minister. I have pleaded with them that unless certain facilities are given to the workers to organise themselves and unless they are given some protection—there is no protection for them at present as the Trade Union Act of 1926 does not apply to them—it is practically impossible for the small employees to get themselves organised. Let me point out that whether it is in the Rural areas or in the urban areas, howsoever good a legislation may be, unless it is enforced by the organised section of the people, the benefit of

such legislation cannot be derived by the people. For example in the Tenancy Act we have various provisions against eviction, but it has been our experience throughout the Hyderabad State that where there is an organised Kisan Sabha (Peasants' organisation) there alone we have been able to enforce the provisions of the Tenancy Act. Similarly, unless there is an organised union of workers, it is not possible to see that the provisions of various sections of the Shops & Establishments Act are enforced and see that the workers get the privileges or the facilities provided for under the particular legislation. In Nanded, when I was trying to organise hotel workers along with the peasants and other workers, it had been my experience that the managements and employers had various means at their disposal to thwart all my efforts to organise them. They could just pay 15 days wages as gratuity and say they did not want the services of a particular employee any more. I went to the Proprietor of a particular Hotel and asked him whether he was going to retrench the workers or whether he was going to close down the establishment. He was going to do neither; and he employed certain other people next day. The trade was flourishing, but still the active Union workers were removed. From this particular experience, it is evident that unless we provide in this legislation certain safeguards against these unwarranted removal of the employees, it will not be possible to implement the Act and afford the facilities provided for under its provisions. I am, therefore, pleading in this House that this particular Section 36 should be amended.

The other day, one of the dignatories of this House complained to me saying: "Well, an employee may come and slap me on my cheek; you may perhaps like me to go to Court and plead there! Do you want to help an employee in this way and encourage such behaviour ?". My reply to him was, and in this House is, that if a particular employee misbehaves, then there are provisions in the Act which go under the name of 'misconduct' whereby certain action can be taken. If we amend the particular section in the way I desire it, it does not mean that the employee will be encouraged to misbehave as such, because there is already provision in the Act to safeguard the employer against it. It is in the interest of the employee that this particular section should be amended, but at the same time it does not go against the interests of the employer as such.

The amended section 36 of the Act seeks to provide that no employee should be removed or no employer shall dispense with the services of an employee except for a misconduct supported by satisfactory evidence recorded at an enquiry held for the purpose. An employee can be removed for misconduct, but what is the safeguard for the employee against the misuse of this provision; the only thing is that there should be satisfactory evidence to this effect. There should be a regular enquiry and the whole proceedings should be recorded. What I am suggesting is not something new. For example, in Nanded, where I had occasion to be the President of the Union—and I still continue as such—in all cases of misconduct, the worker concerned is called by the management, evidence is taken and recorded, and only after that the services of the employee are dispensed with. What I am asking for is not something which is not provided for the factory workers and I only want that the same benefits should be provided for the employees of the Shops and Establishments. That is why I want section 36 of the Act to be amended thus :—

"No employer shall dispense with the services of an employee except for a misconduct supported by satisfactory evidence, recorded at an enquiry held for the purpose......"

and secondly,

"......or, without a reasonable cause, and without giving such person one month's notice or wages in lieu of such notice and without giving such a person a gratuity amounting to 15 days' average wages for each year of continuous service, subject to a maximum of average wages of 15 months".

The reason for the removal of the employee should be reasonable. As the Act stands at present, we find that without giving any reason whatsoever an employee can be removed. As I have explained earlier, if there is no necessity for the employer to give any reason, then the active workers of the Union can be removed without any difficulty and in this way victimisation can take place and all possibilities of an organised union in this particular sector will become practically impossible. Therefore, I have provided that without giving a reasonable cause no employee should be removed, and secondly there should be a notice of one month. It

is rather peculiar that in the Act, the section says that the employee shall not leave the service unless he gives one month's notice, and this very obligation is not cast on the employer; it is only the employee who is made to give one month's notice and not the employer. The present Bill seeks to make it compulsory on the part of both the employer and the employee to give one month's notice, whether the employer wants to dispense with the service of an employee or the employee wants to leave the service of an employer. Secondly, it should be proved that there is a reasonable cause for the employer to dispense with the service of an employee. Thirdly, if the employee has been in service for a long time, gratuity should be given to him at the rate of 15 days' wages for each year of service of the employee in that particular establishment. The last one is not a new provision; it has been already provided by the Government.

I know I may be replied to by the hon. Minister for Labour or the Deputy Minister that the Government themselves are going to bring this amendment—as has been the practice of Governments in other States, and probably the Government of Hyderabad will follow their footsteps. Such promises have been held out to us not in respect of one amending Bill, but at least half a dozen.

Dr. G. S. Melkote: Can the hon. Member mention any?

Shri V. D. Deshpande: I can mention the Money-lenders Act, the Criminal Procedure Code and one or two more. I am not referring to the Labour Department, but to the Government as a whole. As in other cases, probably the reply may be given that the Government themselves are going to amend the Act in the way they feel proper. But I wish to point out to Government that justice delayed is justice denied. I must say that unless such protection is given to the employees, it is not possible to get over the intransigence of the employers. Not only is this affecting the employees, but it is affecting the law and order position also. The Home Minister, sitting here, himself will be glad, I am sure, to testify how the non-affording of this facility to employees has affected the law and order situation in the City. Yesterday, there was a lathi-charge on the workers of Modern Cafe. About 4 or 6 months back, a similar situation developed in the City Cafe.

These things are occurring in the City of Hyderabad. The cases have gone to the Industrial Court. When the situation is deteriorating, Government will not be losing anything by accepting the particular Bill which has been brought up before the House, except probably that they might feel that the credit should go to the Treasury Benches and not a Member of the Opposition. I can understand if the hon. Minister for Labour gives a categorical assurance that the Government will issue an ordinance in this respect or they would introduce a similar Bill within a week. But if it is going to be delayed for months together then I will plead with them that it does not matter if a particular amendment is accepted, even if it comes from the opposition.

Yesterday, I was glad to hear an appeal of the hon. Home Minister that our country is going through a crisis and it is necessary for all those who stand for democracy to come and rally together. To create a good situation in India, it is necessary that the working class which occupies a strategic position in the whole order of things should be satisfied and given due protection. I feel that though this particular Bill is coming on behalf of the Opposition the Government should have, in the circumstances, no objection to accept it. I may assure the hon. Members that if any changes or amendments are to be introduced after the first reading and they are proper, absolutely I will have no objection. Even if I should have any objection, the majority is on the other side and they can carry them through. My only appeal is justice should not be delayed because it might amount to justice denied. Lastly, I shall plead with the hon. Minister that I am not putting anything new. There is nothing new under the sun, as the saying goes. In this particular regard, I am just reproducing, probably with a little change here and there or a phrase here and a phrase there, the same provision in the Madras Act. To refresh the memory of this House, I will just read out the relevant section again, *i.e.*, section 41 of the Madras Act.

"Notice of dismissal :—No employer shall dispense with the services of a person employed continuously for a period of not less than six months except for a reasonable cause and without giving such person at least one month's notice or wages in lieu of such notice, provided, however that such

notice shall not be necessary where the services of such person are dispensed with on the charge of misconduct, supported by satisfactory evidence, recorded at an enquiry held for the purpose."

So if anybody goes through this particular wording, he would find that I have more or less reproduced the same in my amendment. If a Government which is on a border of ours—probably it is not on the border, but one State removed—can enact such legislation, I fail to see any reason why our Government too should not accept it. The other two sub-sections of section 41 of the Madras Act read thus :

"2. The person employed shall have a right to appeal to such authorities and within such time as may be prescribed either on the ground that there was no reasonable cause for dispensing with the services or on the ground that he had not been guilty of misconduct as held by the employer.

3. The decision of the appellate authority shall be final and binding on both the employer and the person employed."

As may be seen, the second sub-section was reproduced in verbatim in my amendment. The third sub-section also was physically taken and put in my particular amendment.

Having explained all these points I hope that I shall not have to hear that the hon. Member may kindly withdraw the Bill as the Government itself is thinking to introduce a similar legislation. Before concluding, I will just point out to the House that there have been some printing mistakes and some omissions. In the sub-section which I want to replace, these words have not been printed there:

"No employer shall dispense with the services of a person employed." These words are not there and they may kindly be added there. Further in sub-section (4), in line 4, for the word 'or', the word 'for' is printed. It may be accordingly corrected.

I hope that this amending Bill will receive the consideration of the hon. Minister concerned. I also appeal to the House to think over the whole matter, and allow the Bill to have a passage in the House.

* *Dr. G. S. Melkote:* Sir, I was extremely pleased to find a peculiarly good effect that the speech of the Home Minister had made on the Members of the Opposition, particularly the Leader of the Opposition himself.

At the outset, he said it was very good that the Treasury Benches permitted him to go through the first reading of the amendment Bill. I thank him for the good sentiments he had expressed. I should also say that to a certain extent he had anticipated possibly what I was going to say.

I wish to remind him a few factors based on actual facts. The situation as it obtains in Hyderabad is different from that obtaining in Madras; where the Madras Act which he has just now read out is administered. Here in Hyderabad, the worker is entitled to a gratuity of 15 days. This is not to be found in Madras. The Leader of the Opposition did not mention this. The other advantages to which he referred were: (1) an enquiry or to cause an enquiry to be made with regard to the dismissal of the employee, and (2) setting up a machinery for adjudication, and (3) to make it obligatory on the part of the employer to give a month's notice or wages in lieu thereof. These were the three things. These were particularly considered in the 1951 Act.

During his speech, the Leader of the Opposition has also mentioned that the Trade Union Act applied only to the factories and not to the Shops and Establishments. I would like to correct him there and tell him that the Trade Union Act applies to both the factories as well as shops and establishments. With regard to dismissals and discharges, even as the Madras Act stands, these are being referred for adjudication and as such, there is absolutely no difficulty. So the only two points that are left for consideration are: (1) month's notice or a month's pay in lieu thereof; This matter is engaging the active consideration of the Government. It is very easy for Members of the Opposition to say that if the Government accepts it and pass an ordinance within a week the members of the Opposition would have no objection to the same. When I was one of the Presidents of a Labour Union I had similar occasions to complain to the then Government. With regard to the Shops & Establishments Act, I had felt that the Government should move very quickly. That

is why when the Leader of the Opposition brought this amendment I thought it should be gone through because I too experienced similar difficulties. But seated as I am on the Treasury Benches. I have got to consider various other aspects about which possibly he is not aware. He did not place........

Shri V. D. Deshpande: The hon. Minister may explain those things.

Dr. G. S. Melkote: Yes, I am doing that. He is possibly not aware that in Madras when such an enactment was ma^de these administrative provisions made there. The Madras Shops & Establishments Act of 1947 extended to the City of Madras, to the municipalities constituted under the Madras District Boards and Municipalities Act of 1920, and all the major Panchayats as classified by the Government. The admin'stration of the Act is enforced by 199 whole-time Inspectors designated as Asst. Inspectors of Labour assisted by a lower division clerk and a peon for each Asst. Inspector. These Asst. Inspectors should work under the control of Gazetted Inspecto s. That shows the amount of establ shment that would be necessary; and if the Government has got to accept any legislation, it has got to consider the administrative aspect of enforcing such a legislation. That is one of our difficulties. The second is before the Government makes up its mind in favour of a Bill of this type, it has got to give sufficient latitude to the proprietors of hotels themselves to ma .e representations to the Government. Such time has not been allowed to those people. Government certainly considers this amendment bill very sympathetically, but in order that the Government may consider setting up the necessary administrative machinery and the consequential financial and other implications as well as in view of the time-lag that would be necessary in order to enable the proprietors to place their point of view before the Government, we consider that this Bill as brought before the House should not be pressed for. That is my only objection. With the principle itself, I agree entirely. I myself and my colleague, the Deputy Labour Minister, have been thinking on these lines. What exact shape it would take I am not in a position to foresee at present; but we are certainly considering this amendment Bill and very shortly—we do not desire to take very long time as

we also experience such difficulty--we would like to bring before the House the necessary legislation. I therefore request the Leader of the Opposition to withdraw this Bill and help me to bring in a comprehensive legislation as early as possible.

**Shri V. D. Deshpande*: Sir, Whether I have misunderstood the hon. Minister or he has misunderstood me, the point is this: The workers are fighting not mainly for gratuity but mainly for security of service. He feels that if he should get 15 days' wages.........

Dr. G. S. Melkote: I accept all those conditions.

Shri V. D. Deshpande: But my point is this. I have come to know that the advice given by the Labour Department on this point has been.......

Dr. G. S. Melkote: Whatever that advice might be, I said that the matter would be sympathetically considered.

Shri V. D. Deshpande: Anyway, I will express my views before I express what I want to do in this particular regard. I want that the Madras Act should be amended to provide a gratuity there also; but that should not become a plea for not providing security of service. I have great objection to the Labour Department. I will come to that when we deal with the demands relating to it. The Labour Department has been putting spokes to get this Act amended for the last one year. Previously also, the Minister for Labour, probably without giving any thought to this, refused to amend this Bill, when I had brought in the amending Bill. Today I have got evidence that it is the Labour Department that is coming in the way of putting this amendment through.

Dr. G.S. Melkote: I am sorry, the hon. Leader of the Opposition is entirely wrong.

Shri V. D. Deshpande: I may be corrected. My impression won't go. Today I have got evidence with me that the Inspector for Shops & Establishments in Secunderabad is

moving in the cars of employers, is attending the meetings of hotel owners, is advising them how to dispense with the services of the employees and is trying in every way to help the employers. It is on the advice and guidance of such employees that the hon. Minister is feeling that in Madras gratuity is not given while in Hyderabad something very big has been given to the workers. It is the security of service that the worker wants and not the gratuity. I do not say that the 15 days' gratuity should be removed. Regarding the establishment that may be necessary we on this Side will vote for such establishment if it is in the interests of the workers. When we criticise the Government expenditure it is in that particular aspect where it is not in the interests of the public but where certain machinery is necessary to give facilities to the workers, nobody from this side can have any objection. That should not come as a plea from the Government.

Dr. G. S. Melkote: That is not a plea. What I said is that the financial aspects have got to be considered. What type of officers are necessary, whether we are having such officers or whether they have got to be trained to suit this particular suit—these are the considerations for which the hon. Leader of the Opposion has to give us time.

Shri V.D. Deshpande: Today some workers of Modern Cafe, City Cafe, etc., are removed. They are being victimised. Even if they go to the Industrial Court, the most that they can get is some gratuity for the period of years they have worked. We want their reinstatement. How is the Labour Department going to help? The Industrial Tribunal could not help unless the Act is amended. It can be proved in an Industrial Court that the worker was removed by the employer illegally. But what is the relief? His relief is only gratuity, not reinstatement. Therefore, I say that if nothing is done by the Government immediately in this respect, this fight of the employees in the city of Hyderabad, Secunderabad and in the district places which is there since this Act has come into vogue will continue without any relief. I want in the circumstances a categorical reply from the hon. Minister for Labour that at least during the course of this Session this particular Bill would be amended and the Bill introduced in this House during this Session. I think it

should be possible. If the Government could have an ordinance exempting the Deputy Ministers for holding offices of profit overnight—or with a delay of one week,—then why is it not possible that during the course of this Session, say before 10th April such a small piece of legislation can be brought into this House, especially when there was a conference of Labour Officers recently, when specially this matter was discussed and when the hon. Minister for Labour was a Trade Union Worker for a long time and President of INTUC and when, as he himself said, he had experienced all these things. In these circumstances, I see no reason why a promise should not be forthcoming from him that during the course of this Session itself he will be in a position to amend this particular Act so as to remove the difficulties the workers are experiencing.

I see no reason why a promise that during the course of this Session he will be in a position to amend the Shops and Establishments Act should not be forthcoming from the Labour Minister. This would remove the difficulties which the workers are experiencing now. If an assurance is made that during the course of this Session say about 10th April, a legislation of this type will be introduced, I will have no hesitation to withdraw the bill I now propose. Let me state very clearly that the next Session of the House may be called only after six months and in the meanwhile the sufferings of the workers cannot be remedied and the struggle between the employers and employees would continue. In view of this, I will once again plead with the Minister that it should be possible for the Government to take this matter up within the course of this Session and I request him to give such an assurance. In that case I have no objection to withdraw it.

Dr. G. S. Melkote : There seems to be certain amount of misunderstandings in the mind of the Leader of the Opposition. He referred to the Madras Act, wherein a provision is made for adjudication. I said that the same type of adjudication is taking place in Hyderabad today and once it is there, it is for the Judge to declare whether the dismissal is legal or not. Once he says that it is legal naturally Government cannot interfere; if it is not legal, naturally the proprietor of the shop or establishment has to take the employee back. What other measures the Leader of the Opposition

envisages in the Act, is not clear. The provision is there, as it is.

With regard to his other point that I should categorically mention that I would bring such a legislation before the end of this Session, I will certainly not be able to do this.

The Government has its duty to perform to everyone and it will necessarily see that the conditions of the labour improve. I have seen their difficulties and know them. Such legislation should be brought about as early as possible. Even then, I have to give everybody a chance to represent their point of view. The time is too short and I will definitely not be able to come before the House with a legislation of the type needed. I said that Government is viewing the whole matter very sympathetically and a legislation of an almost similar type will be brought as early as possible.

Mr. Speaker : The Question is :

"That L.A. Bill No. VI of 1954, the Hyderabad Shops and Establishments (Amending) Bill 1953 be read a first time."

The motion was negatived.

Resolution : Re : Pakistan—U. S. Military Pact.

Mr. Speaker : A resolution is to be moved by Shri V. D. Deshpande. He may move the resolution.

श्री. व्ही. डी. देशपांडे :—अध्यक्ष महोदय, मैं अेक प्रस्ताव यू. अेस.-पाक पॅक्ट के सिलसिले में हाअुस के सामने मुव्ह करना चाहता हूं। यह प्रस्ताव जब भेजा गया था अुस वक्त के हालात और आज के हालात में तबदीलियां वाक्या होने की वजह से मैंने अिस रेजोल्यूशन में कुछ तबदीलियां की हैं। अुन तबदीलियों के लिये अगर मुझे अिजाजत मिलें तो मैं अिसको अिस तरह मुव्ह करना चाहता हूं।

مسٹر اسپیکر- بات یہ ہے کہ یہ رزولیوشن پہلے آیا تھا - اس میں آفس کی جانب سے کرکشنس کئے گئے تھے - اسے چھاپنے کے بعد آنریبل ممبرس کو ریزولیوشن کی کاپیاں دی گئیں - پھر اس سے متعلق آنریبل ممبرس کی جانب سے ترمیمات پیش کی گئیں - آپ اصل رزولیوشن میں جو تبدیلی کرنا چاہتے ہیں مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن ممکن ہے کہ ترمیمات پیش کرنے والے آنریبل

ممبرس کو اوس پر کچھ اعتراض ھو ۔ میری رائے میں یہ امنڈمنٹس کچھ ایسے زیادہ اھم تو نہیں ھیں ۔ لیکن ھوسکتا ھے کہ آنریبل ممبرس اس پر کچھ کہیں ۔ اگر موجودہ پرنٹڈ ریزولیوشن کو موو کیاجائے تو اس کے بعد معزز رکن امنڈمنٹ کے طور پر اس میں تبدیلی فرماسکتے ھیں ۔ اوریجنل پرنٹڈ ریزولیوشن (original printed resolution) میں دس آنریبل ممبرس نے امنڈ منٹس پیش کئے ھیں ۔ آپ پرنٹڈ ریزولیوشن میں جو تبدیلیاں کرنا چاھتے ھیں کیا وہ ان دس آنریبل ممبرس کو منظور ھیں ؟

شری عبدالرحمن (ملک پیٹھ) ۔ ھاں ھمیں منظور ھیں ۔

Shri V. D. Deshpande: I beg to move :

"That this Assembly expresses grave concern at the pact of military alliance and aid between America and Pakistan by virtue of which the American armed forces are expected to build their war bases in Pakistan under the plea of strengthening them. This pact while endangering the freedom and independence of Pakistan, brings the danger of war on the border of India and attempts to coerce India into war camp. It will further involve the whole of South East Asia in the preparation for acts of aggression and brings near the out-break of Third World War.

This Assembly, while expressing solidarity and friendship between the people of India and Pakistan calls upon the Government of India to raise a powerful campaign against this pact and develop Indo-Pakistan friendship, As'an solidarity and World Peace.

This Assembly pledges its full support to the Government of India in this respect."

Mr. Speaker: Resolution moved.

Shri L. B. Konda (Asifabad-General): I beg to move :

(1) That for para 1 subtitute the following :

"This Assembly expresses its grave concern at the Military Aid Pact between the United States of America and Pakistan leading to consequences endangering the freedom

and peace of India including South-East Asia and even precipitation of third world war."

(*ii*) For para 2, substitute the following :—

"This Assembly recommends to the Government of India to take strong security measures to encounter the impending danger to freedom and peace of India ; and further recommends to launch effective campaign for Indo-Pakistan friendship, Asian solidarity and world peace."

(*iii*) In line (1) of para 3, *omit* the word "also."

Mr. Speaker: Amendment moved.

Shri Ankushrao Ghare (Partur): I beg to move:

(*i*) That in line 12 of the Resolution, delete the following words, namely :—

"revere all connections with the United States of America"

(*ii*) Add the following at the end of the Resolution :

"and emphasises the need of extending compulsory military training to all students of high schools and colleges above the age of 18 years."

Shri V. B. Raju (Secunderabad-General) : The first portion of the amendment is not necessary, because it has been accepted by the mover himself in his own amendment.

Mr. Speaker : Part 2 of the amendment moved.

Shri V. D. Deshpande : The discussion may take place after interval. I do not want to be interrupted after two or three minutes by an interval.

Mr. Speaker: I expected the hon. Member would begin his speech immediately. All right we will adjourn, now.

The House then adjourned for recess till Half Past Five of the Clock.

The House re-assembled after recess at Half Past Five of the Clock.

[MR. DEPUTY. SPEAKER IN THE CHAIR].

श्री. व्ही. डी. देशपांडे:—अध्यक्ष महोदय, जो बादल अब तक हिंदुस्तान के मशरीक में और मगरीब में मंडरा रहे थे वे आज रास्त हिंदुस्तान पर आना चाह रहे हैं। जो खतरा हमारे आसपास के मुल्कों को अमेरिकन कार्यवाहियों की वजह से पिछले पांच साल से पैदा हुआ है, वह आज रास्त तौर पर हिंदूस्तान पर आ रहा है। और अमेरिका के अुस जारहाना अेकदाम के खिलाफ हमें सोचने का मौका आ गया है। कल ही पंतप्रधान नेहरू ने पार्लिमेंट में यह कहा है कि अब हम अमेरिकन फौजी अफसरों को गैरजानिबदार नहीं समझ सकते अुनके अल्फाज ये है।

"We think a situation has arisen when no officer of the U. S. Army can be considered as neutral."

यह भी सुना गया है कि पंडित नेहरूने चेंबर ऑफ कामर्स, कलकत्ता, की मीटिंग में यह कहा है कि अेक खास हालत में किस हद तक मआशी अिमदाद हम बाहर से ले सकते हैं, और कितनी लेनी चाहिये अिसको भी हमें सोचना पडेगा। यह जो खियालात पंडित नेहरू ने जाहीर किये हैं अुससे हमें पता चलेगा कि कुछ खास दौर से गुजर रहे हैं। अेक जमाना था कि अमेरिका के गुणगान से हमारा मुल्क भरा हुआ था। हम अमेरिका को अपना सबसे बडा दोस्त समझते हुअे अुनका स्वागत किया करते थे। लेकिन पिछले अेक साल में जो वाक्यात हमारे सामने आये हैं अुससे जिस गहरी नींद में हम पडे हुअे थे अुससे हम आज जाग रहे हैं। हमें जो पहला तजरुबा हुआ वह कश्मीर के अंदर हुआ। शेख अब्दुल्ला पर भरोसा रखते हुअे आज तक अपनी कौमी जद्दोजहद की कोशिश के तौर पर हम अुनकी अिमदाद करते रहे और वहां की अव्वाम जो वहां की जमीनदारी के खिलाफ और वहां के महाराजा के खिलाफ लड रही थी अुसका साथ देते रहे। हम यह समझ रहे थे कि जिस जमहूरियत को हम कायम करना चाहते हैं अुसी रास्ते पर हिंदुस्तान के अेक हिस्से के तौर पर कशमीर आगे बढेगा। लेकिन हमारा यह सुख-सपना अेक दिन टूट गया। हमने देखा कि अमेरिका ने वहां अपनी कार्यवाही शुरू की और यह कोशिश की कि वहां अपने जंगी मनसूबों के लिये अड्डे कायम कर सकें, और अिस हिस्से को हिंदुस्तान से अलग करें। वे चीजें खतम हुअीं न हुअीं कि हमने सुना कि पाकिस्तान के साथ अमेरिका का मुआहदा हो रहा है। बहुत से लोगों को अुस वक्त अैसा मालूम हुआ कि अैसा नहीं हो सकता, क्योंकि अमेरिका को हम अपना सबसे बडा दोस्त मानते हैं और अमेरिका भी समझती है कि अेशिया में हिंदुस्तान अेक अैसा मुल्क है जिसको दोस्ताना तौर पर रखना चाहिये और हमेशा दोस्ताना ताल्लुकात अुसके साथ बढाने चाहियें। लेकिन पाकिस्तान के साथ जो मुआहदा होने की खबर हमने सुनी और आज जो कुछ हो चुका है अुससे अब हम अपनी गहरी नींद से जाग अुठे हैं और सोच रहे कि यह जो तरीका अमेरिका की तरफ से अखितयार किया जा रहा है अुसके सिलसिले में क्या किया जाय। मैं हाअुस से बताना चाहता हूं कि अमेरिका की कार्यवाहियां आज हमें नये तौर पर महसूस हो रही हैं लेकिन अुसका आगाज १९४५ में जब दूसरा महायुद्ध समाप्त हुआ अुसी वक्त से हुआ है। और जिस हिटलर को दुनिया की अव्वाम ने शिकस्त दी थी अुसी हिटलर का विरसा लेकर अमेरिका दुनिया के अंदर सब दुनिया पर हावी

होनेकी ओीर्षासे आगे कदम अुठाती गओी। आप अगर अिस अमेरिका की कार्यवाहियों को जंगे अजीम नंबर दो के खतम होने के बादसे देखेंगे तो पता चलेगा कि अुनकी कार्यवाही हमेशा दो तरह की रही है। अेक तरफ दुनिया में जो सोशलिस्ट मुल्क है या जहां जहां अव्वाम की जमहूरियत पसंद हुकूमतें कायम हुओीं हैं, मसलन् सोवियट रूस और पीपल्स चायना और दीगर मुमालिक, अुनके खिलाफ अेक महाज खडा किया जाय। अिसके साथ साथ अपने बेपार को बढाने के लिये, ज्यादा मंडियों को हासिल करना, अपने सरमायेदारों के अेक्सप्लॉयटेशन को आगे बढाने के लिये दुनिया में जितने पिछडे हुये मुल्क हैं अुनको अपने काबू में लाने की कोशिश करना, यह भी दूसरी कोशिश अमेरिका की तरफ से हुओी है। यानी १९४५ से ही हिटलर का विरसा लेकर अमेरिका आगे बढ रही है। हिटलर ने यही किया था कि अेक तरफ दुनिया में सोवियट रूसके खिलाफ नारा देते हुअे दूसरी तरफ यह अैलान किया कि हमें कॉलनीज नहीं है, हमारी बढती हुओी आबादी के लिये जगह नहीं है लिहाजा हमें अेक नया मुल्क मिलना चाहिये। अिस तरीके पर हिटलर आगे बढा। आज अमेरिकन सांम्राज्यवादी भी बिल्कुल अुसी तरीके से दुनिया के अंदर आगे बढ रहे हैं। आज पाकिस्तान और अमेरिका का जो मुआहदा हुआ है अुसे हम अपने लिये अेक गाअिड के तौर पर न देखें तो आयंदा जो कुछ होनेवाला है अुसके बारे में हमें आगे जो कदम अुठाना चाहिये वह ठीक तरह से नहीं अुठा सकेंगे अमेरिका की तरफ से दूसरे जंग के बाद मिलीटरी मुआहदा हर जगह करने की कोशिश की गओी। यूरप के अंदर अेक यूरप अमेरिका पैक्ट बनाया गया। अुसके बाद मिडिल ओीस्ट में मेडो के नाम से अेक पैक्ट बनाने की कोशिश की गओी। अुसके बाद जापान, आस्ट्रेलीया और न्यूजीलंड के अुस हिस्से में पैसिफिक पैक्ट बनाने के बारें में कोशिश की गओी। लेकिन छोटीसी कामयाबी से 'अेन्झज' नाम से अेक पैक्ट बनाया गया। अिसके आगे वे वहां नहीं बढ सके। यह कोशिश अिसलिये थी कि यूरप से लेकर जापान तक अेक अैसी पूरी संकल तैयार की जाय जो कि मौका आने पर अेशिया के अुन तमाम मुल्कों के खिलाफ अिस्तेमाल की जा सके जो अभी पिछडे हैं जिन में से कुछ अभी अभी आजाद हुअे हैं या जो अभी आजाद नहीं हुअे हैं और आजादी के लिये लड रहे हैं और जो मुल्क अेशिया के मुल्कों को आगे जाने में मदद दे रहे हैं। अेशिया के तमाम मुल्कों को धोखा देने के लिये अुनको आजाद न होने देने के लिये, जो आजाद हुअे हैं अुनकी आजादी खतम करने के लिये अमेरिका ने यह कोशिश की। अिसका मकसद अेकतरफ सोवियट रूस और पिपल्स चायनाके खिलाफ अेक कार्डन (cordon) तैयार करने का भी था। लेकिन मैं हाअुस को बताना चाहता हूं कि अेक जमाने में हिटलर ने भी अपने दावे के साथ दुनिया के तमाम मुल्कों को अपने पंजे में लाने की कोशिश की थी। लेकिन दुनिया को अव्वाम ने अुसको पहचाना। आज वही चीज हमारे सामने फिर से आ रही है। अमेरिका अपने कदम हर जगह बढाते जा रहा है। अिस वक्त हाअुस के सामने अिस चीज को रखना गैरमुनासिब न होगा कि अेक तरफ रूस और चायना के खिलाफ कोशिश की जा रही है और दूसरी तरफ खुद अमेरिका और अिंग्लेंड में आपस में जद्दोजहद जारी है। और अुसके फलस्वरूप अंग्रेजों के लिये मंडियां हासिल करनेके लिये अमेरिकाकी तरफसे जो कोशिश हो रहीहै अुसको भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। अिन दो तरीकों से आज अमेरिका दुनिया में आगे बढ रहा है। अिस पसमंजर में नअपनी आजादी के लिहाज से और अपने मुल्क की कूव्वतों को बढाने के लिहाज से अमेरिका कि कोशिशों की तरफ देखना चाहिये। हमने १५ अगस्त १९४७ में अपनी अव्वाम की जद्दोजहद से और दुनिया के अंदर जो जमहूरी ताकत पैदा हुओी थी अुसकी वजह से जो कुछ सियासी हुकूक हासिल

किये अुनको ज्यादा मजबूत करने के लिये और जो हमारी पस्त मआशी हालत है अुसको खतम करने के लिये आगे कदम अुठाना शुरू किया। हमारे सामने यह सवाल था कि हमारे मुल्क की आयंदा हम तरक्की कैसे कर सकेंगे, जो बर्तानिया के मआशी बंधन हमारे अूपर है अुनको कैसे तोड सकेंगे और मुल्क के अंदर जो हमारी अव्वाम का स्टैंडर्ड आफ लिविंग है अुसको कैसे बढा सकेंगे। हमने आगे बढने की कोशिश की लेकिन हम कामयाब न हो सके। अिसी वक्त हिंदुस्तान अेक बहुत बडा सनअती और ताकतवर मुल्क न बने अिस लिये अमेरिका की तरफ से, साम्राज्यवादी अमेरिका की तरफ से, कोशिशें जारी थी। हिंदुस्तान ताकतवर न हो सके अिसलिये अेक जमाने मे अंग्रेजोंने भी कोशिश की थी। अुन्हों ने हिंदुस्तान की तकसीम की और हर जगह अपने सियासी और मआशी तसल्लुत को कायम रखते हुअे पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों को कमजोर रखने की कोशिश की। लेकिन हिंदुस्तान मे जो जमहूरी कूव्वतें हैं, हिंदुस्तान की अव्वाम ने अेक जमाने में साम्राज्यावादियों के खिलाफ लड कर जो ताकत हासिलकी है, अुसकी वजह से अमेरिका का अैसा तसल्लुत हिंदुस्तान के अूपर कायम नहीं हो सका जिस तरह वे पाकिस्तान में कायम कर सके हैं। जो अमेरिका पिछले तीन साल में हिंदुस्तान पर अप नी पकड कायम करने में कामयाब न हो सका, अुसने यह अेक नया रास्ता आज ढूंढा है और पाकिस्तान अमेरिका का मुआहदा अुसीका नतीजा है। अिस मिलीटरी मुआहदे का मकसद जहां अेक तरफ यह है कि दुनिया की अव्वामी जमहूरियतों के खिलफ अेक कॉर्डन तैयार किया जाय, वहांयह भी मकसद है कि अमेरिका के जो जंगी मनसूबे हैं अुनके अंदर हिंदुस्तान को खींचा जाय। आयसेनहोवर से जो पत्र पंडित नेहरु को आया है अुसमें अुन्होंने कहा है कि जिस तरह पाकिस्तान को हमने अिमदाद दी है अुसी तरह आपको भी देने के लिये हम तैयार है लेकिन अिस सिलसिले में पंडित नेहरु का जवाब बिल्कुल साफ साफ है कि किसी भी मुल्क की आजादी बाहरी फौजी अिमदाद पर कायम नहीं रह सकती। हम किसी की अिमदाद लेकर आगे नही बढ़ना चाहते हैं हम अैसी अिमदाद नहीं ले सकते और आज अमेरिका से पाकिस्तान को जो मदद दी जा रही है अुसको भी ठीक नहीं समझते। बहुत से लोग समझते हैं कि जवाब देने की हमें क्या जरूरत थी? अगर हम अुनसे फौजी मदद लें तो क्या हर्ज है? मुमकिन है पाकिस्तान के अंदर भी अिसी तरह नमहसूस करनेवाले लोग हों। वे समझते होंगे कि हम अमेरिका से अिमदाद लें तो हम ताकतवर बनेंगे और कशमीर का मसला हम हल कर सकेंगे। लेकिन मुझे अिस वक्त वह कहानी याद आ रही है जिसमें बताया गया है कि किस तरह घोडे ने अेक जंगली जानवर को खतम करने के लिये अिनसान की मदद मांगी और हमेशा के लियेअिनसान को अपनी पीठ पर सवार कर लिया। मसले के तमाम पहलुओं को मैं हाअुस के सामने नहीं रखना चाह रहा हूं। दूसरी भी अेक मिसाल मैं दे सकता हूं। अेक जमाने में फिलिपिन्स ने स्पेन के खिलाफ अपनी आजादी की रक्षा के लिये अमेरिका की अिमदाद मांगी और बाद में फिलिपिन्स अमेरिका की अेक नौआबादी बन गया। आज पाकिस्तान समझ रहा है कि अमेरिका की अिमदाद लेकर वह कामयाबी हासिल कर सकेगा। मुझे पाकिस्तान की अव्वाम से अपील करनी है कि अिससे पाकिस्तान आगे बढनेवाला नहीं है, बल्कि पाकिस्तान दुनिया के सब से बडे ताकतवर और साम्राज्यवादी हुकूमत अमेरिका के हाथ का अेक खिलौना बन जायगा, बल्कि मैं कहूंगा कि करीब करीब वह आजही अैसा खिलौना बन गया है। अिससें पाकिस्तान कीअव्वाम की बहबूदी होनेवाली नही है बल्कि हिंदुस्तान के साथ रहते हुअे हिंदुस्तान की अव्वाम की जद्दोजहद के कारण पाकिस्तान को जो आजादी मिलसकी है वह भी खतम हो जायगी। शायद यह चीज पाकिस्तान की अव्वाम को भी

पसंद नहीं है। अीस्ट बंगाल के अिलेक्शन के नतायज यही बता रहे है। पाकिस्तान का हुक्मरान तबका समझ रहा है कि अमेरिका की अिमदाद से पाकिस्तान की बहबूदी होगी। लेकिन अीस्ट बंगाल ने यह बतलाया है कि पाक-यू. अेस.अे. पैक्ट के पीछे वह खडा नहीं है। मुस्लिम लीग वहां हारी है और मुत्तहादी पार्टी है अुसने अबतक की खबर के मुताबिक ५१ सीटें हासिल की हैं। अिससे जाहीर होता है कि पाकिस्तान की अव्वाम समझती है कि अमेरिका की अिमदाद जो पाकिस्तान ले रहा है वह अुसकी आजादी के खिलाफ जानेवाली चीज है। वहां की अव्वाम भी यह महसूस करती है कि अिससे पाकिस्तान की बहबूदी नहीं होगी, बल्कि अुनकी आजादी खतम हो जायगी, और अंग्रेजों के पंजेसे निकल कर अमेरिका के पंजे में पाकिस्तान जा रहा है। अिसीलिये पंडित नेहरूने अमेरिका की अिमदाद को लेने से अिनकार किया। अिस असेंब्ली में भी अिस ख्याल का अिजहार करता हूं कि जो साम्राज्यवादी अमेरिका अपनी अिमदाद देकर हिंदुस्तान को अपने सियासी कामों की अेक संकल बनाना चाहता है और हमारी आजादी पर जरब लगाना चाहता है अुसकी अिमदाद हम हरगिज नहीं ले सकते और न लेंगे। किसी साहब ने कहा कि हमारा मुल्क गरीब है और हमारे पास सरमांया नहीं है। बगैर सरमाया लिये हम कैसे आगे बढ सकते है ? अिस प्रश्न के लिये मेरा जवाब यह है कि अगर किसी अिमदाद की वजह से हमारी आजादी पर असर होता है, हमारी आजादी पर जरब लगता है, तो अैसी अिमदाद न लेने के नतीजे में अगर हमको भूखा भी मरना पडे तो हम भूखे मरेंगे लेकिन आजादी पर असर करनेवालों का डटकर मुकाबला करेंगे। अिसी ख्याल से हम सब को आज आगे बढना है। पंडित नेहरूने अिस सिलसिले में जो पॉलिसी जाहीर की है अुसको, अपनी ताअीद जाहीर करने के लिये आज हाअुस के सामने मैंने अिस रेजोल्यूशन को लाया है।

दूसरी अेक चीज मैं हाअुस के सामने रखना चाहता हूं। बहुत से लोग यह समझे कि पाक-अमेरिका के अिस पॅक्ट से हमको धोखा नहीं है बल्कि रूस और चायना को है। हमें अिससे क्या करना है ? जैसा मैंने दूसरी अेक तकरीर के सिलसिले में कहा था कि अिन्सान के खून का अेक दफा शेर को चस्का लग जाय तो वह यह नहीं देखता कि अिस गांव का आदमी अच्छा है या अुस गांव का। वह किसी को भी अुडाता है। मुझे बहुत बडा शक होता है कि कोरिया की लडाअी में पस्त होने के बाद आज अमेरिका में जो बेरोजगारी बढ रही है, चीजों की कीमतें गिर रही हैं, जंग का सामान पडा है अुसको मुनाफे से बेचने के लिये शायद दुनिया के अंदर और कहीं छोटी मोटी जंग शुरू करदी जाय अिस ख्याल से अमेरिका की कोशिश आगे बढती जा रही है। अैसी हालत में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान आज जो ताल्लुकात हैं अुनको देखते हुअे अमेरिका के लिये अिन दो देशों के सिवा दूसरी कौनसी जगह अच्छी हो सकती है जहां वह लडाअी शुरू कर दे ? जिस साम्राजियत की यह ट्रेडीशन है कि वह दुनिया के लोगों को आपस में लडायें और खुद मुनाफा कमा लें अुसके लिये क्या यह संभव नहीं है कि वह हिंदुस्तान और पाकिस्तान को लडाकर अपने जंगी सामान के लिये अेक खासा मार्केट खुला करे ? किसीने कहा है कि मौत के बेपारी अमेरिकन साम्रज्यवादी यह चाह रहे हैं कि अपने माल को बेचने के लिये हर जगह दुनिया के अंदर जंग को चलाया जाय। अिस चीज को अगर हम नजरअंदाज करें और सिर्फ अिसी ख्याल में रहें कि अिससे चीन और रूस को ही धोखा है तो हम बडी भारी गलती करेंगे। आज जो अीरान में हुआ है वही कल हिंदुस्तान में होने के अिमकानात पैदा हो सकते हैं। अीरान के अंदर मुसाद्दिक की हुकूमत ने आजाद अीरान के कअी मसले हल

किये । ओरान की आजादी पर कओ साल से हावी होनेवाले अंग्रेजों को वहां से खतम किया, अपनी मुल्क की तरक्की के लिये अुसने तमाम जरायों को अपने हाथ में लिया और अेक जमहूरी दौर वहां कायम कराया । लेकिन हम देखतें है कि वहां भी अमेरिका ने मुसाद्दिक को अुखाड ने के लिये वहां कि अेक विरोधी सियासी पार्टी को मिलीटरी अिमदाद दी और जिस मुसाद्दिक को वहां की अव्वाम कि मेजारिटी ने मुल्क का कारोबार जिस तरह से वह चाहे अुस तरह से चलाने के लिये अधिकार दिया था, अुसको अुखाड फेंका गया और पूरे मुल्की के खियालात के खिलाफ जाकर अमेरिका के तहत अेक दूसरी हुकूमत वहां कायम की जा रही है । आज हिंदुस्तान के अंदर जो हालत है अुसमें वहां जो हुआ वह होना अुतना मुमकिन नही है । हमारी अेक जमहूरी कूव्वत है, जद्दोजहद है, अेंटी अिम्पेरिअेलिस्ट ट्रेडीशन्स है, अिन तमाम का ख्याल करते हुअे अमेरिका के लिये हिंदुस्तान का ओरान बनाना आसान नहीं है । लेकिन जिस तेज रफ्तार से अमेरिका हर जगह आगे बढ रहा है और जो आसपास के हालात बदलते हुअे नजर आ रहे हैं अुससे यह मालूम हो रहा है कि पूरे हिंदुस्तान को अेक तरह से घेरा डालते हुअे अमेरिका जा रहा है । पाकिस्तान के अंदर अुनके हवाओ अड्डे हैं। हमारे मुल्क के अंदर गोवा का भी अिस्तेमाल किया जा रहा है । अुधर जापान के अंदर अिडोचायना में और आसपास में अमेरिका के अड्डे आज भी कायम हैं । अिस तरह से पूरे हिंदुस्तान के अतराफ अमेरिका का घेरा पडा हुआ है और अगर आंतरराष्ट्रीय हालात अिसी तरह से खतरनाक होते चले जायें तो अमेरिका के लिये हिंदुस्तान पर दबाव लाना मुश्किल नहीं है । अिस तरह से अमेरिका की पकड हमारी आजादी को न सिर्फ बैरूनी तरीके से बल्कि अंदरूनी तरीके से भी खतरा पैदा करती है। अिसीलिये पंडित नेहरू ने कहा है कि कश्मीर के अंदर जो अमेरिकन न्यूट्रल्स हैं अुनको हम न्यूट्रल्स नहीं समझ सकते । वे यहां रहकर हमारे तमाम फौजी कारोबार को देख सकते हैं, हमारे यहां के स्ट्रेटेजिक पोस्टस् को देख सकते हैं, हमारी फौजी कॉन्फीडेन्शिअल चीजों को जान सकते हैं और पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात रख सकते हैं । अुनको हम अपने दोस्त कैसे समझें ? अुनसे हमे धोखा नहीं है अिस चीज का भी यकीन हम कैसे रख सकते हैं ? आयसेनहोवर, वजीरे आजम अमेरिका और मोहम्मद अली वजीरे आजम पाकिस्तान, दोनों ने कहा है कि हम जो अिमदाद दे रहे हैं और ले रहे हैं, वह किसी मुल्क के खिलाफ लडाओ करने के लिये नही है । अगर अैसा नहीं तो क्या वजह है कि अिस तरह से जब पूरा हिंदुस्तान कह रहा है कि कश्मीर का मसला तय करने के लिये हमने दुनिया के सामने, यूनो के सामने, खुलेआम रख दिया है, अुसके बावजूद हिंदुस्तान पर दबाव लाने के लिये अिस तरह से फौजी अिमदाद ली और दी जा रही है ? दो साल पहले हिंदुस्तान ने अिस चीज को साफ कर दिया है कि यूनों पर भरोसा रखते हुअे वह अिस मसले का हल पा सकेगा । लेकिन हम देखते हैं कि दो साल से अमेरिकन साम्राज्यवादी कश्मीर के मसले को हल करने के रास्ते में मुसलसिल रोडे अटका रहे हैं । अेक साल पहले हिंदुस्तान खुश था । पाकिस्तान के प्रधान मंत्री मोहमद अली देहली आये और पंडित नेहरू भी कराची गये थे और अैसा मौका पैदा हुआ था कि हम आपस मे बातचीत करके अपने सवालात हल कर सकें लेकिन अैसा होना अमेरिका के लिये ठीक नहीं था । अमेरिकाने पाकिस्तान से जो दोस्ताना ताल्लुकात रखे अुनकी वजह से और अमेरिका की जारहाना पालिसी की वजह से यह चीज न हो सकी और तब से दिन ब दिन हालात खराब होते जा रहे । अिन चीजों को हाअुस के सामने रखते हुअे मुझे यह कहना है कि हम अिनडिफरन्ट हो कर सुस्ती से आज के बदलते हुअे हालात की तरफ नहीं देख सकते । हमें अिस सवाल की तरफ तवज्जेह देनी

पडेगी और अुसकी तरफ देखने का जो हमारा तरीका है अुसको भी साफ करना पडेगा। मैं यह बताअूंगा कि आज मुल्क के अूपर सिर्फ बाहर से ही खतरा नहीं है, बल्कि अंदर से भी खतरा है और वह है अुन तमाम फिरकेवाराना अिदारों से जो अिन तमाम हालात में हिंदुस्तान का जो सेक्यूलर स्टेट है अुसके अंदर रहनेवाले मुख्तलिफ मजहब के लोगों में झगडे पैदा कराना चाहते है। हिंदुस्तान का अेक रिपब्लिक कायम हुआ है और जो हमारी कौमी ट्रॅडीशन है अुसने हमको सिखाया है की मजहब के लिहाज से हम किसी में फर्क नहीं करते। जाति और मजहब को ख्याल में रखते हुअे हमने कभी हिंदुस्तान की कौमी जद्दोजहद में नही सोचा, बल्कि हमेशा यह सोचा है कि जो चूसनेवाले हैं अुनके खिलाफ तमाम अव्वाम का अेक महाज खडा होना चाहिये। लेकिन आज के हालात का फायदा अुठाते हुये कुछ फिरकेवाराना अनासिर आगे बढना चाहते हैं। अिन फिरकेवाराना अनासिर से हमें तजरूबा है कि वे पाकिस्तान की अव्वाम के खिलाफ हिंदुस्तान की अव्वाम को मजहब के नाम पर अुठाना चाहते हैं और अिसी बिना पर अन्ग्रेजों के जमाने में अुन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था और हमारे कौमी जद्दोजहद के खिलाफ नारे लगाये थे। अिसलिये अेक तरफ हमारे मुल्क के बाहर से जो खतरा है अुसके खिलाफ भी हमें तैयारी करना है और दूसरी तरफ मुल्क के अंदर जातीयतावादी और मजहबी खियालात के लोगों के खिलाफ अेक बहुत बडा मुत्तहिदा महाज खडा करना है। अिसीलिये मैंने अपने रेजोल्यूशन में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दोस्ताना ताल्लुकात पर जोर दिया है। हिंदुस्तान को सिर्फ हिंदुस्तान की हद तक ही खतरा नहीं है, बल्कि साअुथ ओस्ट अेशिया में जो अमेरिका तेजीसे बढता जा रहा है अुसकी वजह से पूरे साअुथ अीस्ट अेशिया को धोखा हो गया है। सिर्फ हिंदुस्तान का ख्याल रखकर अगर हम अिस पाक-यू.अेस.अे. पॅक्ट के खिलाफ आवाज अुठायेंगे तो आनेवाली परिस्थिति का मुकाबला हम नहीं कर सकेंगे। अेशिया के सब मुल्कों को जिन्होंने पिछले पचास साल से कौमी जद्दोजहद में हिस्सा लिया है और आजाद हो गये हैं, और आज भी आजादी के लिये लड रहे हैं अुन सब को—बर्मा, अिंडोनेशिया अिंडो चायना और दीगर मुमालिक को अेक जगह लाना पडेगा, क्योंकि अिस साम्राजियत का हमें मुकाबला करना है वह दुनिया के दो सबसे बडी ताकतों में से अेक है। अकेले हिंदूस्तान को अुसका मुकाबिला करना मुश्किल है। अमेरिका की तरफ से जो कदम आज अुठ रहा है अुसको रोकने की ताकत आज किसी अेक मुल्क में नहीं है, बल्कि अुसके लिये दुनिया की आजाद पसंद अव्वाम का अेक बहुत बडा महाज हमें खडा करना पडेगा। अिसीलिये मैंने अिस रेजोल्यूशन के अंदर (.........develop Indo-Pakistan friendship, Asian solidarity and World Peace.) के अल्फाज रखे हैं।

दूसरी चीज मुझे यह रखना है कि दुनिया के अंदर आज जो अमन कायम करने की तहरीक है अुसको आगे बढाना चाहिये। हम चाहते हैं कि हमें अपने मुल्क के अंदर आजादी हो ताकि हम अपने दिल के मुताबिक चाहे जैसी हुकूमत कायम कर सकें। दूसरे मुल्कों को अिसमें मदाखलत करने का अेख्तियार नहीं होना चाहिये और यहां दूसरे मुल्कों को अपना तसल्लुत कायम करने का मोका भी नहीं होना चाहिये। लेकिन साम्राज्यवादी राष्ट्र अपनी मंडियों को कायम रखने के लिये, दुनिया के मुल्कों की आजादीपर जरब रखने के लिये, अुनके अंदरूनी मामलात में हस्तक्षेप कर रहे हैं और अुनको अपने पंजे में लाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि हममें से हर अेक, फिर वह चाहे किसी भी पार्टी का हो, अपने मुल्क की आजादी को सब से बडी चीज समझता है।

और जब कभी मुल्क की आजादी पर हमला होने के अिमकानात पैदा होंगे तो बिना किसी पार्टी बाजी या मजहब के खियाल से हम सब को अेक होकर अुसका मुकाबला करना चाहिये। अिसी चीज को जाहीर करने के लिये यह रेजोल्यूशन हाअुस के सामने रख रहा हूं। हाअुस का ज्यादा वक्त न लेते हुअे अिस रेजोल्यूशन का जो आखरी ऑपरेटिव पार्ट है अुसकी तरफ हाअुस को तवज्जेह दिलाना चाहता हूं। आज सिर्फ असेंबली में बैठकर अिस तरह के करारदाद पर बहस करने से, या बाहर मीटिंग्ज लेनेसे, अिस मसले को हम हल नहीं कर सकते। पंडित नेहरु ने और दूसरी जमहूरी पार्टियोंने पिछले छ: महीनों से अिसके खिलाफ पुरजोर आवाज अुठाअी है। लेकिन अफसोस की बात है कि जो अमेरिकन साम्राज्यवादी अपना जारहाना कदम अुठा रहे हैं वे अब तक हमारी आवाज को नही सुने हैं। जब हमने आवाज अुठाअी तो हम यह अुम्मीद कर रहे थे कि हमारी दोस्ती का अेहतराम किया जायगा और अिस तरह का फॅक्ट जो बनाया जा रहा है अुसको रोका जायगा। लेकिन हम देखते हैं कि जब साम्राजियत के सामने अपने फायदे का सवाल आता है तो वह लोगों की दोस्ती को ठुकरा सकता है। अैसी हालत में हमको अेक मुत्तहिदा तौर पर कदम अुठाना पडेगा। आज हमारे मुल्क पर किस तरह का संकट आयेगा अिसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता। लेकिन मैं यह हाअुस को यकीन दिलाना चाहता हूं कि जब हमारे मुल्क पर किसी भी किस्म का संकट आ जाता है तब हम सब को अेक होकर आगे बढना होगा और अपने मुल्क का रक्षण करना पडेगा। अिस काम में हम सब को साथ रहना चाहिये।

आखिर मे मैं हाअुस से अपील करूंगा कि अिस चीज को हुकूमते हिंद पर वाजे करना चाहिये कि अपने मुल्क को और मुल्क की आजादी को बरकरार रखने के लिये अुसको ज्यादा मजबूत करने के लिये, हमें जल्द से जल्द कदम अुठाना चाहिये। आज जो हमारे मुल्क में अमेरिकन निरीक्षक हैं वे अब यहां नहीं रह सकते। मैं ने अिस रेजोल्यूशनमें अमेरिका के साथ जो ताल्लुकात है अुनको तोडना चाहिये अिसके बारे में जो जुमला था अुसको निकाल दिया है, लेकिन अिसके पीछे जो सेंटीमेंट है अुसको मैं अिस वक्त हाअुस के सामने रखे बगैर नहीं रह सकता। अगर अमेरिकन निरीक्षक हमारे देहातों के अंदर हैं, फोज के अंदर हैं, सनअतों के अंदर हैं, और सनअतों को जानते है, अगर अुनके टेकनिशियन्स हर जगह घूमते हैं, अगर अुनके अिनफरमेशन ब्यूरोज शहरों में खोले गये हैं, मुल्क के अखबारात में अपने नुमाअिंदों को रखकर हमारे मुल्क की सेक्यूलर पॉलिसी के खिलाफ और हमारी जमहूरी पॉलिसी के खिलाफ लिख सकते हैं तो अैसी हालत मे हम अमेरीका का भरोसा कैसे कर सकते हैं? हिंदुस्तान के खिलाफ आज अमेरिका और दुनिया की अव्वाम में सब से ज्यादा प्रचार जो करते है वे अुनके यहां के अेजंट ही करते हैं. पंडित नेहरु की होम पॉलिसी के खिलाफ दुनिया की अव्वाम को तैयार करने के लिये रोजाना अखबारात के स्तंभ के स्तंभ लिखे जाते हैं और अव्वाम को बताया जाता है कि पंडित नेहरू कम्युनिस्ट हैं। हम तो कम्युनिस्ट हैं, लेकिन पंडित नेहरू कम्युनिस्ट हैं या नहीं यह तमाम लोग जानते हैं। लेकिन पंडित नेहरू और हम दोनों चाहते हैं कि हम अपनी आजादी बरकरार रखें और अुसके खिलाफ कोअी हमला करने की हिम्मत करे तो अुसके खिलाफ मुत्तहिदा तौर पर खडे होकर लडें। अैसी हालत में मैं हाअुस से कहूंगा कि हमें बहुत ही सोंच समझ कर और सुचेत रह कर आगे कदम बढाना पडेगा। हम मुल्क के अंदर यह कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते कि हमारी अमन की पॉलिसी के खिलाफ कोअी यहां प्रचार करे और हमारे अखबारात को सबसीडी देकर

हमारे ही खिलाफ लिखने के लिये अुनको मजबूर करें। अिस चीज पर अगर आप गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि पूरे मुल्क के अंदर अमेरिकन प्रचार जारी है और अिसके लिये यहां अमेरिकन अेजंटस भेजे हुअे हैं। यही बात हिटलर ने सन १९३७ में की थी। आपको मालूम है कि दूसरा महायुद्ध शुरु होते ही किस तरह से यूरप के देश अेक के बाद अेक गिरते गये। अिस की वजह सिर्फ यह नहीं थी कि हिटलर के पास बहुत अच्छी फौज थी। अच्छी फौज तो थी लेकिन वह बहुत कम थी। लेकिन सब से बडी वजह यह थी कि हर मुल्क को अंदरूनी तौर पर, नैतिक तौर पर, अुसने अपने हाथ में लिया था। अुसने मुल्क के अंदर मुख्तफिल सियासी पार्टियोंको करप्ट किया था, और अपने अेजंटस हर जगह रखे थे और अक पंचमस्तंभ कायम किया था। अिस वजह से वह यूरप के अंदर जल्दी कामयाबी हासिल कर सका। अिस चीज को हमें आज ही सोंचना पडेगा। मुल्क के सामने जो खतरा है अुसका सामना करना है तो पहले फिरकेवाराना जहनियत के लोगों के खिलाफ कदम अुठाना चाहिये और अुनका मुकाबला करने के लिये अव्वाम को तैयार करना चाहिये।

आखिर में अेक बात कहते हुअे मैं अपनी तकरीर खतम करूंगा। अगर कोअीसाम्राज्यवादी मुल्क हमारी तरफ अेक गीदड दृष्टि से देखने की जो जुर्रत करता है अुसकी वजह क्या है? यही है कि हमारी माशियत पिछडी हुअी है, हमारे मुल्क के सनअतों की तरक्की नहीं हुअी है, अिसलिय बाहरी मुल्क हमें यह टेम्पटेशन देते हैं कि आप हमारी मदद लीजिये ताकि आप तरक्की कर सकेंगे। अिस बहाने से वे हमारे मुल्क के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। नव आबादियों को अंग्रेजों को यह विरसा है कि वह मआशी तौर पर अुनके कब्जे में रहें। हम सोचते है कि अगर बर्तानिया हमारे सवाल हल नहीं कर सकता तो हम और किसी देशके पास जायें और अुसकी मदद लें। यह जो हमारा बॅकवर्डनेस है, वही साम्राज्यवादियों को हमारे मुल्क पर नजर डालने के लिये और अुसको अपने कबजे में करने के लिये अच्छा कारण हो जाता है। अेक तरफ पाक यू. अेसए. पॅक्ट के खिलाफ आवाज अुठाते हुअे मुल्क के अंदर जो फिरकेवारीना अिदारे है अुनके खिलाफ हमें लडना है और साथ ही साथ अमेरिकन पेनिट्रेशन का भी मुकाबला करना है। लेकिन अुसके साथ साथ में यह भी अपील करूंगा कि जिस बुनियादी बॅक्वर्डनेस की वजह से साम्राज्यवादी लोग हिंदुस्तान को अपना अड्डा बना सकते ह, अुसके खिलाफ हम सब को मुत्तहद हो कर लडना पडेगा और आगे कदम बढाना होगा। मुझे अिसकी अुम्मीद है। मै मायूस नही हूं। मैं हिंदुस्तान में देख रहा हूं कि बावजूद अिसके कि हिंदुस्तान के अंदरूनी पॉलिसी के बारे में मतभेद है फिर भी जब मुल्क का कौमी सवाल सामने आता है तो मुल्क की तमाम जमहूरियत पसंद पार्टियां अेक जगह [illegible]ने के लिये तैयार होती हैं। अेक जमाने में अंग्रेजों के खिलाफ लडने के लिये अेक मुतहृदा महाज बनाते हुअे तमाम पार्टियां और तमाम तबके जिस तरह से अेक जगह आया करते थे अुसीकी कुछ झलक हम आज भी हिंदुस्तान के कोने कोने में पा रहें हैं। देहली में पार्लिमेंट के अंदर जब यह मसला आया तो तमाम पार्टियों ने पंडित नेहरु की अिस सिलसिले में जो पॉलियसी है अुसका खैरमकदम किया और अुसकी पुरजोर ताअीद की। अिसी तरीके से हम हदराबाद और दूसरी रियासतों में भी कदम अुठायें तो मुझे यकीन है कि अिस तरह से जो हमारी बढती हुअी ताकत है वह

सामने आती जायगी, तो अमेरिका को अपने कारस्थानों के बारे में फिर सोचना पडेगा, और अगर वह न भी सोचे तो हम अपनी पूरी ताकत लगाकर अमेरिका के कारस्थानों को खतम कर सकते हु। अिस यकीन के साथ में अिस रेजोल्यूशन को हाअुस के सामने रखता हूं, और विनंती करता हूं कि हाअुस अिसको पास करें।

* شری لکشمن کرنڈا (آصف آباد - عام) - مسٹر اسپیکر سر - جو ریزولیوشن هاوز کے سامنے پیش کیا گیا ھے اس میں میں نے بھی ترمیم پیش کی ھے - جس طرح سے آنریبل لیڈر آف دی اپوزیشن نے کھلے شبدوں (शब्दों) میں پرستھتی (परिस्थिती) کاورنن (वर्णन) کیا ھے اسی طرح میں بھی اپنا نکته نظر ایوان کےسامنے رکھوں گا اور وشواس (विश्वास) کروں گا؟ که آنریبل ممبرس اس کو شانتی (शांती) کے ساتھ سنیں گے - اس لئے که جب میں پچھلے زمانے کو یاد کرتا هوں تو محسوس کرتا هوں که جب میں تقریر کرنے کے لئے کھڑا هوتا هوں تو اس طرف کےآنریبل ممبرس انٹرپٹ (Interrupt) کرنے کی کوشش کرتے رهتے هیں - مجھے امید ھے که اس مرتبه ایسا نہیں کیا جائیگا -

پاک امریکی معاهده کا مسئله بہت گہری جڑیں لئے هوئے آگے بڑھ رها ھے - شمال اور مشرق کی طرف سے کچھ فیسیزم (Fascism) بہتا هوا آگے بڑھ رها ھے جس کو دیکھکر اس کےمقابله کے لئےایک سامراجیت کی لہر شمال و مغرب کی جانب سے بڑھ رهی ھے - یه دو قوتیں هیں جو متحده محاذ قائم کرنے کے لئے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کررهی هیں - میں کسی ملک کی سیاست کےبارے میں کچھ کہنا نہیں چاهتالیکن پاك امریکی پیکٹ(Pact) کے پیچھے ایک گہری سازش تھی - چنانچه اگر یه کہا جائے یا یه شبه کیا جائے تو غلط نہیں هوگا که پاکستان کے ایک وزیر اعظم کو برخواست کرنا اور امریکه میں جو پاکستان کا نمائنده ھے اس کو لاکر وزیر اعظم بنانا اور اس کےبعد گورنر جنرل کا امریکه جانا اور وهاں پاک امریکی پیکٹ (Pact) کا افشاء هونا اور اس کےچنددن بعد اس کا حقیقت بن جانا یه سارےواقعات درشٹی میں لائے جائیں تو معلوم هوگا که یه ساری باتیں پری پلانڈ (Pre-planned) کےتحت هوئی هیں اور پاکستان کو وهاں کےعوام کی مرضی کا خیال کئے بغیر اور ان کےخیالات کو پیش نظر نه رکھتے هوئے امریکه کی جھولی میں ڈالدیا گیا ھے -

چنانچه ایسا هوا - جو کچھ هوا اس کی ساری ذمه داری محض امریکه یا پاکستان پر ھے میں یه ماننے کے لئے تیار نہیں هوں - اس کی ذمهداری اگر مساوی نہیں توکم از کم بڑی حدتک رشیا پر اور رشیا کےڈھنگ سے سوچنے والوں پر بھی ھے - چنانچه اس کے بڑے دور رس اثرات هونے کی صورت نظر آتی ھے - هندوستان جو کسی بلاك كےساتھ

ہونا نہیں چاہتا اور اپنی ایک آزاد پالیسی رکھتا ہے دنیا کے حقیقی امن کا اگر کوئی علمبردار ہے تو وہ صرف ہندوستان ہی ہے ۔ نہ تو رشیا ہے نہ امریکہ ۔ چنانچہ جس بڑی قوت کو دونوں ممالک بھی پسند نہیں کرتے ۔ اور نتیجتاً جہاں تک ہوسکے اس کو کمزور کرنے کی کوشش کی جاتی رہی ۔ اگر ٹھنڈے دل سے سوچا جائے تو اس طرح امریکہ کی جانب سے جنگ کے لئے مختلف ممالک میں بلاکس قائم کئے جارہے ہیں ویسے ہی اس کے مد مقابل پولٹیکل فلاسفی (Political Philosophy) کو لیکر آگے بڑھنے والوں کے محاذ بھی قائم ہوتے جارہے ہیں ۔ ایسٹ جرمنی سے لیکر چیکوسلواکیہ یا اس کے بعد ترکی ۔ افغانستان یا گلگت کے جو امپارٹنٹ سنٹرس ہیں اس پر کس کا قبضہ ہونا چاہیئے ۔ اس کے بعد چائینا تبت کے بڑے دعویدار کھڑے ہورہے ہیں ۔ یہاں یہ بہت بڑا سیاسی مسئلہ سامنے آجاتا ہے ۔ اس کے لئے امریکہ نے یہ بہتر سمجھا کہ پاکستان کو مہرا بنائے ۔ مجھے بڑی خوشی ہے کہ کم از کم ہندوستان کے سارے لوگ اس کی مخالفت کررہے ہیں ۔ مجھے اس پیکٹ سے ہندستان کی آزادی اور امن کو جو خطرہ نظر آتا ہے وہ محض اس لئے نہیں کہ آئندہ آنے والی جنگ کی خاطر امریکہ پاکستان کو استعمال کریگا ۔ بلکہ یہ بھی ممکن ہے کہ پاکستان بھی جنگ کی آگ میں مبتلا ہو جائے ۔ کئی آئیزن ہاور آسکتے ہیں جاسکتے ہیں ان کے وعدہ کاغذ پر رہ سکتے ہیں ۔ لیکن نہ تو وہ کوریا میں کچھ کرسکے نہ یہاں کچھ کرسکتے ہیں بلکہ ممکن ہے کہ محض جنگ کو ہوا دے سکیں ۔ میں کہوں گا کہ اس معاملہ میں پاکستان انوسنٹ (Innocent) نہیں ہے بلکہ اس نے بالارادہ اس اگریمنٹ کو اپنایا ہے ۔ اور ہوسکتا ہے کہ نہ صرف کشمیر بلکہ کسی اور طور پر ہندوستان کو جنگ زمانے میں آئیلنڈ کی شکل بنادے ۔ میں یہ محسوس کررہا ہوں کہ اس پیکٹ سے جو ایک ایسے ملک پاکستان سے ہورہا ہے جو ہندوستان کی بارڈر پر ہے ہماری آزادی خطرہ میں نظر آرہی ہے ۔ لیکن جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ جس اصول پر نہروجی نے پاکستان کے امریکی فوجی امداد کو لینے سے اتفاق نہیں کیا اسی اصول پر مجھے یقین ہے کہ اگر برما یا رشیا میں بھی کوئی ایسا معاہدہ ہو تو پنڈت نہرو اس کی مخالفت کریں گے ۔ لیکن اس صورت میں ہندوستان کو بڑی مشکل پیش آئیگی ۔ لیکن برما کی صورت میں شبہ ہے کہ گھر کے اندر کے بھیدی برابر اس کی تائید کرنے لگیں گے ۔ اور ہندوستان انتہائی خطرناک صورت میں مبتلا ہوجائیگا ۔ خدا نہ کرے کہ ایسی نوبت آئے ۔ لیکن متحدہ محاذ کی باتیں ایسی باتیں ہیں جنہیں ہمارے ہندوستان کے بعض خاص سیاسی نظریہ رکھنے والے مانتے ہیں وہ اس طرح کا ہے کہ خود ہمارے لیڈر پنڈت نہرو اس معاملہ کی تعبیر نہیں کرسکتے اور اس قسم کا سیاسی مسلک رکھنے والوں سے کوئی متحدہ محاذ ہم نہیں بناسکتے ۔ یہ ہمارے اس پوتر لیڈر کی رائے ہے جس کا کوئی مقابلہ نہیں کرسکتا ۔ اس پیکٹ کے پیچھے کئی باتیں انوالو (Involve) ہیں جو ڈیولپ ہونے والی ہیں جن کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے ۔ چنانچہ یہاں امریکہ کے پیکٹ کے سلسلے میں شبہ کیا گیا ہے کہ ممکن ہے اس سے ایک فرقہ وارانہ

فضاء پیدا ہوجائے - کیونکہ فرقہ وارت دن بدن بڑھتی جاری ہے لیکن یہ سمجھنا کہ ایسے موقع پر ہندوستان کا کوئی مسلمان پاکستان کی تائید کریگا یہ بہت بڑی بھول ہے - چنانچہ متعدد موقعوں پر مسلمانوں نے یہ بتایا ہے کہ جب ہندوستان کی آزادی کا سوال آئیگا تو ہم اس کے لئے اپنے خون کا آخری قطرہ بہانے کے لئے بھی تیار ہیں - اس لئے میں کہوں گا کہ ہمیں فرقہ وارت کا اتنا ڈر نہیں جتنا کہ ہندوستان کی آزادی ور امن کی راہ میں ہندوستان کے اندر کے ایسے لوگوں سے ہے جو ایسے خیالات رکھنے والے لوگ ہیں کہ........

श्री. व्ही. डी. देशपांडे :—मुझे अिस चीज को वाजे करना है कि मैंने अपनी तकरीर में मुसलमानों की तरफ किसी तरह का अिशारा नहीं किया था। मेरा अिशारा खासकर हिंदुमहा सभा की तरफ था जिसको हमारी सिक्युलर पॉलिसी पसंद नहीं है और जो अखंड भारत का नारा लगाती है। मेरा मतलब था कि अुनको अिस मौके से अेनकरेजमेंट मिलेगा और हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमान जमातों मे फूट या मतभेद पैदा करने के लिये अिस मौके का अुपयोग करेंगे। मेरा कहने का यह कभी मंशा नही था कि यहां के मुसलमान पाकिस्तान की अिमदाद करेंगे।

شری لکشمن کونڈا - بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ کم از کم مسلمانوں پر تو اعتماد رکھتے ہیں - اور کسی رزرویشن کے بغیر ان پر اعتماد رکھتے ہیں - لیکن ہندو مہا سبھا کی کوئی قوت نہیں ہے - وہ کیا اکسپلائیٹ کرسکتی ہے - اکسپلائیٹ تو دوسری پارٹیاں کرسکتی ہیں - اس کی گنجائش ہے - ہندوستان ہی میں جو خطرہ ہے اس کو مجھے صاف الفاظ میں رکھنا ہے - پنڈت نہرو نے یہ کہا ہے کہ ہم کسی بیرونی ملک کی فوجی قوت کی بناء پر اپنی آزادی اور امن کو برقرار نہیں رکھ سکتے - یدی اس اصول کو سارے لوگ مانتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کی شکتی بہت بڑی ہے اور وہ کسی قسم کے بھی حالات کا مقابلہ کرسکتا ہے - لیکن مجھے اس کا ضرور افسوس ہے کہ ایسے حالات پیدا ہونے کے باوجود بھی آج ہندوستان کے کم سے کم بڑے سیاسی ادارے یا عوام کے نمائندے کہلائے جانے والے لوگ ایک پلیٹ فارم پر نہ آسکے - کیوں کہ ان میں ایک دوسرے پر اعتماد پیدا نہ ہوسکا - میرا ہی نہیں بلکہ پنڈت نہرو کا بھی اعتماد پیدا نہ ہوسکا جن کی نیترتو میں آج ہم ایک کٹھن سمسیا کو حل کرنے کے لئے آگے بڑھ رہے ہیں - اس لئے ضروری ہے کہ محض بھاشنوں کے دوارا نہیں بلکہ عمل کے ذریعہ بتادیں کہ ہم خطرہ خواہ شمال مشرق سے آئے یا شمال مغرب سے کہیں سے بھی آئے ہم ڈٹ کر ان کا مقابلہ کریں گے - اور ہم گاندھی جی کے مارگ پر چل کر کریں گے - جمہوریت کی بڑی بڑی باتیں تو کی جاتی ہیں - لیکن جب دوسرا وقت آتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ کوئی جمہوریت ہی نہیں ہے - کم از کم اس نوبت پر تو یہ تسلیم کیا گیا کہ ہندوستان جمہوری ملک ہے - مجھے وشواس ہے کہ اسی جمہوریت کی بناء پر ہم کسی بھی خطرہ کا مقابلہ اچھی طرح کرسکتے ہیں -

میں نے اصل ریزولیوشن پر جو امنڈمنٹس پیش کئے ہیں ان میں خاص اہمیت

رکھنے والی چند باتیں مضمر ھیں ۔ اصل ریزولیوشن میں یہ دیا گیا ھے کہ اسکا امکان ھے کہ امریکہ دوسری جنگ کے لئے پاکستان کو اڈہ بنائے گا ۔ میں عرض کرونگا کہ کیوں اسی حد تک رائے قائم کی جائے ۔ یہ کیوں نہ سمجھا جائے کہ پاکستان خود اپنی طرف سے جنگ کریگا ۔ جب کہ وہ اپنے ملک کی آزادی کے سلسلے میں یہ کہتا ھے کہ اس سے ھمارے ملک کی آزادی اس فوجی معاھدہ کی بناء پر برقرار رھے گی ۔ پاکستان کیلئے اپنی آزادی اور امن کی خاطر معاھدہ کرنا ذرا بےمعنی بات ھے ۔ بلکہ یہ ان کا سوچا سمجھا ہوا منصوبہ ھے ۔ اس کے لئے نہ صرف امریکہ بلکہ پاکستان بھی مساوی ذمہ دار ھے ۔ اور یہ خطرہ ھندوستان کے سر پر منڈلا رھا ھے ۔ اس لئے میں نے ریزولیوشن سے جو الفاظ "محض امریکہ اڈے قائم کرے" کے ھیں اس کو نکال دئے ھیں ۔ تاکہ دونوں مساوی ذمہ داری کے ساتھ اس مسئلہ کو سوچیں ۔ بلاشبہ ھم آج پاکستان کے ساتھ دوستانہ تعلقات رکھنا چاھتے ھیں ۔ چنانچہ دوسرے پیراگراف میں پہلے ھی محرک نے کہا ھے کہ پاکستان کے ساتھ دوستانہ تعلقات ھیں لیکن ان دوستانہ تعلقات کے باوجود اپنی آزادی کی خاطر سکیورٹی میژرس لینا پڑتا ھے تو کیا نہ لئے جائیں اس کے لئے ریزولیوشن میں گنجائش نہیں ھے ۔ چنانچہ میں نے اس کی گنجائش پیدا کی ھے ۔ آزادی کی حفاظت اور امن کی خاطر حکومت جو مناسب کارروائی اختیار کرسکتی ھے عمل میں لائے ۔ خواہ اس حفاظتی کارروائی میں ھمارے دوستانہ تعلقات پاکستان اور امریکہ سے بالکل ھی کیوں نہ ختم ھوجائیں ۔ اگر ھماری آزادی ختم ھوتی ھے تو ھمیں ایسے تعلقات کی کوئی ضرورت نہیں ۔ ھم کو آزادی اور امن کی ضرورت ھے ۔ اسی مفہوم کو میں نے یہاں صاف الفاظ میں رکھا ھے ۔ مجھے امید ھے کہ محرک صاحب بھی اس کی اھمیت کو سمجھتے ھوے اس ترمیم کو مان لیں گے ۔

اس کے علاوہ اصل ریزولیوشن میں یہ کہا گیا ھے کہ ملٹری الائینس پیکٹ اور الائینس میں بڑا فرق ھے ۔ میرے پاس ایسا کوئی مواد نہیں ھے کہ جس کے تحت ھم الائینس سے ایسا پریزمپشن (Presumption) یا رائے قائم کرسکتے ھیں ۔ دونوں کا ملٹری الائینس ھوگا ۔ آپ یہ تو تسلیم کرتے ھیں کہ امریکہ سے پاکستان کو فوجی امداد دی جائےگی ۔ جو آگے ملٹری الائینس کی صورت اختیار کرے گی ۔ یہی میں سمجھتا ھوں ۔ اس لحاظ سے پہلے فقرہ کو میں نے تبدیل کر کے دوسرے الفاظ میں رکھا ھے اس کے لئے مجھے ترمیم پیش کرنی پڑی ۔ ان حالات میں جو آج ملک کے سامنے ھیں ایسا معاھدہ جس سے یہ خاص صورت پیدا ھو تو نہ صرف اس ایوان سے بلکہ ھر جگہ سے اس بارے میں عوام کے صحیح جذبات دنیا پر ھمیں ظاھر کرنا ھے ۔ اور اس کے ذریعہ ھندوستان کے سارے عوام کو اس جانب توجہ دلانی ھے ۔ یہاں سے باھر جانے کے بعد عملی طور پر ان کو لیڈ (Lead) کرنا ھے ۔ مجھے یقین ھے کہ اس قرارداد کے محرک صاحب بھی ایسی کوئی صورت نکالیں گے جس سے باقی سیاسی پارٹیوں کے لوگ یا لیڈرس یا ورکررس کے دلوں میں ایک خاص سیاسی مسلک رکھنے والوں کے تعلق سے جو شبہ ھے وہ عملی طور پر دور ھوجائے ۔

ہم دیکھتے ہیں کہ یہ شبہات بہت ہی معقول قسم کے ہیں ۔ محض وہم پرمبنی نہیں ہیں ۔ جس طرح کہ امریکہ کے لائبریریز موجود ہیں کیا کام ہورہا ہے ۔کلچرل کام ہوتا ہے ۔ ان کا پیسہ بہتا ہے ۔ ویسے ہی دوسرے ممالک سے بھی ڈائرکٹلی یا انڈائرکٹلی ایجنٹس کے ذریعہ سے ایسے کاروبار یہاں پر جاری ہیں جس کو چیک کرنے کی ضرورت ہے ۔ اس کو پنڈت نہرو نے حال ہی میں پیپسو کی تقریر میں کہا ہے ۔ ہم ان چیزوں کو نظر انداز نہیں کرسکتے ۔ اگر فی الواقعی اس پاک امریکن پیاکٹ کی بنیاد پر وہ ہمارے تصفیہ سے بڑھکر اندرونی طور پر کچھ کرنا چاہتے ہیں تو میں کہونگا اور پرزور الفاظ میں کہونگا کہ وہ ملک کے ساتھ بڑی غداری ہوگی ۔ اگر فی الواقعی پاک امریکن معاہدہ سے ایک بڑا خطرہ محسوس ہوتا ہے اور اس خطرہ کے لئے ہمیں تیار ہونا چاہئے تو اس معاہدہ کی جو اسپرٹ ہے جیسا کہ ہم محسوس کرتے ہیں کہ ایک خاص قوت ہماری طرف بڑھ رہی ہے ۔ دنیا کا کوئی ملک بھی چاہے یہ قوت اختیار کرنا چاہے خواہ ہماری پڑوسی ملک کی جانب سے بھی یا خود ہمارے ملک کے اندر سے ایسی قوت استعمال کی جائے ہم ایک مضبوط محاذ قائم کر کے آگے بڑھ سکتے ہیں ۔ ہم ہی اس کے ذمہ دار ہیں اس لئے اس جانب توجہ کرنا بھی ہمارا فرض ہے ۔ میں امید کرتا ہوں کہ پنڈت جواہر لعل نہرو کی قیادت میں ایک طرف بغیر فاسیزم کے اثر میں آئے اور دوسری سامراجیت کی قوتوں کے چنگل میں پھنسے جس آزادی اور امن کے قیام کی طرف آج ہندوستان بڑھ رہا ہے اگر سچ مچ آزادی کے خواہاں ہیں ۔ امن و امان کے خواہ ہیں تو ان کو بغیر کسی ریزرویشن کے پنڈت جی کے نقش قدم پر چلنا ہوگا صرف اس مسئلہ کی حدتک اتفاق کیا گیا اور دوسرے مسائل میں اختلاف ہوتو ایسا نہیں ہوسکتا کیونکہ آج کے مسائل انٹرلنکڈ (Inter-linked) ہیں۔ ایک مسئلہ کو ایک درشٹی سے اور دوسرے مسئلہ کی دوسری درشٹی سے نہیں دیکھا جاسکتا ۔ ہم آج کل یہ کرتے ہیں کہ ایک مسئلہ کی تائید کریں اور دوسرے مسئلہ میں چارگالیاں دیدیں تو اس سے صحیح حالات امن اور آزادی کو بر قرار رکھنے کیلئے پیدا نہیں ہوسکتے بلکہ یہ ہماری امن اور آزادی کے لئے ایک بڑا خطرہ ہوگا ۔ میں آج اس خطرہ کی طرف ایوان کو توجہ دلانا چاہتا ہوں ۔ اس کے پیچھے بھی میں آنریبل ممبرس کی درشٹی کو لیجانا چاہتا ہوں ۔ اس لحاظ سے ہمارے سامنے جو ریزولیوشن ہے اس میں اس اسپرٹ کو پورا کرنے والے الفاظ ہاؤز کے سامنے ترمیم کی شکل میں پیش کیا ہوں ۔ اگر سچ مچ اس پیاکٹ کے پیچھے جو اسپرٹ ہے جس کے اطراف و اکناف پھیلنے کا امکان باہر کے ممالک سے بڑھکر اندر کے ایلیمنٹ (Element) سے ہے اور اس کو دور کرنے کے لئے سکیوریٹی میژرس (Security Measures) لیتے ہیں تو وہ لوگ گورنمنٹ کا ساتھ دیں گے اور یہ نہ کہا جائیگا کہ یہ بل نہو وہ بل نہ ہو ۔ یہ ہوسکتا ہے کہ سکیوریٹی کے نام سے اتفاق سے بے گناہ زد میں آجائیں وہ پس جائیں لیکن ان کیو گریٹر انٹرسٹ کے نام پر پسنا ہی چاہئے ۔ اس لحاظ سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم آج مسائل پر سوچتے ہیں تو ایک مسئلہ پر ایک ڈھنگ سے نہ سوچیں

اور دوسرے مسئلہ پر دوسرے ڈھنگ سے نہ سوچیں - بلکہ سارے مسائل کو مشترکہ طور پر سوچیں اور ڈیموکریٹک کنونشنس (Democratic conventions) کو آگے بڑھائیں - یہ رجحان ہے تو مجھے امید ہے کہ میری ترمیمات کو سوور صاحب خود تسلیم کرلیں گے - کیونکہ دنیا میں ہم کو ایک اہم ترین فرض انجام دینا ہے - امن اور آزادی کے فرض کو انجام دیکر ہمیشہ جمہوریت کا جھنڈا لہرانا ہے اسقدر کہتے ہوئے میں سوور صاحب سے پھر ایک بار اپیل کرونگا کہ وہ میری ترمیمات کو مان لیں -

श्री. अंकुशराव व्यंकटराव घारे:—अध्यक्ष महोदय ,जो रेजोल्यूशन बहस के लिये आया है असके अूपर लीडर ऑफ अपोजिशन की जो अभी तकरीर हुअी है वह काफी मसायल पर रोशनी डालती है। हम जानते हैं कि अमेरिका की तरफ से जितने पैक्टस होते हैं वह असकी अेक्सपेन्शनिस्ट पालिसी की वजह से होते हैं। अनकी यह पॉलिसी है कि अशिया के लोगों को अेशिया के लोगों के साथ ही लडा कर अपना व्यापार बढाना, यही पालिसी अनके तरफ से कोरिया में भी अेख्तियार की गअी थी। पाक-अमेरिकन पॅक्ट असी का अेक नमुना है। हमारी बदकिस्मती से कश्मीर का मसला अेक अैसा मसला है जिसकी वजह से अमेरिका को हिंदुस्तान में कोरिया का, रिपीटीशन करने के लिये अेक अच्छा बहाना मिल गया है। लेकिन यह जानना पडेगा कि अमेरिकन मदद आती है तो वह किसी के गले में जबर्दस्ती अतारी नहीं जा सकती। अगर कोअी मुल्क अमेरिकन मदद लेना नहीं चाहता तो अमेरिका बाम्बरों से असको अिमदाद नहीं पहूंचाता। सही मानों में गलती है अनलोगों की जो अैसी अेड अेक्सेप्ट करते हैं। पंडित नेहरू ने यह बयान किया है, कि हमारे दिल में यह बात कभी नही आअी कि पाकिस्तान की टेरीटरी पर हम अग्रेशन करें, और आज अैसा कोअी मुल्क नजर नहीं आता जो पाकिस्तान पर हमला कर सकेगा, क्योंकि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के जो नेचरल बेरियर्स हैं अनको देखते हुअे किसी को बाहर से खतरा नहीं दिखाअी देता। अगर यह कहा जाय कि हिंदुस्तान से धोखा हो सकता है तो सारी दुनिया जानती है कि हमारी पालिसी कितनी साफ है, और हम किसी भी मुल्क पर अेग्रेशन करने पर तुले हुअे नहीं हैं। फिर भी अिन सारे वाक्यात की रोशनी में यह पॅक्ट किया गया है, और पाकिस्तान ने अपनी अिन्सानियत को बेचकर, भीख मांग कर, अमेरिका की अिमदाद अपने मुल्क में लाअी है। जैसे हमारे यहां अेच. अी. अेच. दि निजाम के वक्त रेसीडेन्ट रखा जाता था, और ब्रिटिश फौज रखी जाती थी और कहा जाता था कि वह निजाम के प्रोटेक्शन के लिये रखी गअी है। लेकिन दरअसल वह ब्रिटिशों की खुद की पावर प्रोटेक्शन के लिये रखी जाती थी। अिसी प्रकार पाकिस्तान में जो अमेरिकन मदद आयेगी वह दरअसल अमेरिका के मुनाफे के लिये लाअी जायगी। लेकिन अिमदाद देते हुअे आयसेनहोवरने यह भी डिक्लेर किया था कि अिस अिमदाद का हम अेग्रेसिव्ह पर्पज के लिये अपयोग नहीं होने देंगे। लेकिन ये सब बातें दोचार हजार मील की दूरी पर न्युयार्क में बैठकर की जा रही हैं। अनका असर कुछ नहीं हो सकता। अगर कल अॅग्रेशन होगया, तो कल आयसेनहोवर यहां आकर असको रोक नहीं सकते। अिसलिये जो अमेरिकन अेड ली गअी है, वह कश्मीर के मसले को हल करने के लिये ली गअी है। अब कश्मीर का मसला प्लेबिसाअिट से हल होने वाला नहीं है। अिसलिये हमको कश्मीर के सवाल की तरफ अभी से लडाअी के नुक्तेनजर से देखना

पडेगा। हम चाहें या न चाहें दोचार साल के अंदर हम अेक लांग ड्रान बॅटलमें घुसेंगे। अिसलिये हमको यह समझना चाहिये कि अपोजीशन पार्टी के लोग कहते हैं, या पंडत जवाहरलाल नेहरू अेक सर्क्यूलर भेजते है कांग्रेस के लोगों को कि अिसके खिलाफ लोगों में राय कायम करना चाहिये वह की जाय तो अुससे कुछ फायदा होनेवाला नहीं है। फिर अिस मसले को किस तरह से सोचना चाहिये। अिसको कम्युनल अप्रोच से बिलकुल नही सोचना चाहिये। हम को अिस तरीके से सोचना चाहिये और तैयारी करनी चाहिये कि अगर हमारे अूपर कोअी अग्रेशन करता है तो अुसके दांत खट्टे बनजायें। अिसके लिये प्रॅक्टिकल तरीका यह हो सकता है कि हमारे डिफेन्स की कूव्वतें पूरी तरह से मजबूत होने कि जरूरत है। भारत सरकार के डिफेन्स डिपार्टमेंट के डेप्यूटी मिनिस्टर ने बजेट के डिसकशन का जवाब देते हुअे कहा था कि अिस मसले पर हम अच्छी तरह से सोंच रहे है। और अिसके लिये सब डिपार्टमेंटस को अच्छी तरह से आर्गनाअिज करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अुसके पहले हमारे डिफेन्स मिनिस्टर श्री बलदेव सिंग ने कहा था कि टेरी-टोरियल आर्मी या अेन. सीं. सी. की तरह अेक लाअिन ऑफ डिफेन्स कायम करनेवाले हैं। लेकिन आज तक हमारे मुल्क में अिस दृष्टि से कोअी प्रोग्रेस नहीं किया गया है। प्रॅक्टिकल पाअिंट ऑफ व्हयू से मैं कहना चाहता हूं कि हमारे मुल्क को आर्गनाअिज करने के लिये हमारे यंग मेंन को मिली-टरी ट्रेनिंग देने की जरूरत है। अिसलिये स्कूल्स और कॉलेजेस के नौजवानों को कम्पलसरी मिली-टरी ट्रेनिंग देना जरूरी है। बद किस्मती से हमारे नेताओं को सिर्फ तक्रिरें करने की आदत होगअी है। लेकिन अुनकी मुंह की तोपों से यह अेग्रेशन रूकनेवाला नहीं है। पार्लियामेंट जवाहरलाल नेहरू ने अेक तकरीर की थीं कि अिस पॅक्ट की वजह से हमको जरा भी घबराने की जरू-रत नही है। बात सही है लेकिन अिस के बारे में हमको काम्प्लेसेंट भी रहने की जरूरत नहीं है। पंडित नेहरू को मैं कदर की नजर से देखता हूं, लेकिन अुनको प्लान्स बनाने की आदत हो गअी है। बडे बडे प्लान्स करने की अुनको आदत होगअी है। और हमारे दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश में सचमुच जो प्लान कॅरी आअुट करने की ताकत रखनेवाले व्यक्ति सरदार पटेल थे वे आज नहीं रहे हैं। मेरा कहना यही है कि प्रॅक्टिकल नज़र से अिस सवाल की तरफ देखने की जरूरत है। अिसलिये मैंनें यह अमेंडमेंट पेश की है। शायद यह कहा जायगा कि जनरल मास सपोर्ट हासिल करने के लिये यह रेजोल्यूशन लाया गया है। अिससे हम जनरल सपोरट जरूर अेक्सप्रेस कर रहे हैं, लेकिन सपोर्ट के साथ साथ अिस बात पर भी हम अपना अटेन्शन फोकस करना चाहते हैं कि अिस वक्त हमारे देश को किस किस डायरेक्शन में ले जाना जरूरी है। अिसलिये मैंनें यह अमेंडमेंट मुव्ह की है। हम देखते हैं कि आजकल हायस्कूल्स और कॉलेजेस में हमारे स्टूडंटस पढते हैं, लेकिन वे नहीं जानते कि डिसिप्लीन क्या चीज होती है। आज हमारे स्टूडंटस बिल्कुल अिनडिसिप्लिन्ड हैं। अुनमें सिर्फ डिसिप्लिन लाने के बहाने से नहीं लेकिन हमारे मुल्क का रिजर्व्हड फोर्स बिल्ड अप करने के लिये ट्रेन्ड परसोनेल को किसी भी वक्त फराहम करने के लिये, और फिजीकल फिटनेस के अेक खास स्टेज पर अुनको लाने के लिये हमें अुनको मिलीटरी ट्रेनिंग देने की जरूरत है। अिसके लिये जिस तरह से रेग्यूलर आर्मी के मेंटेनन्स के लिये खर्च किया जाता है अुसी तरह से अिस ट्रेनिंग के लिये किया जाना चाहिये। अिसके लिये ट्यूटर्स रखने चाहिये। अिसके लिये हमें ज्यादा अेक्सपेंडीचर भी करना पडेगा, तो अुसको हमें बर्दाश्त करना पडेगा। मैं आशा करता हूं कि मेरी अमेंडमेंट को हाअुस तसलीम करेगा।

Shri Syed Akhtar Hussain rose in his seat....

مسٹر ڈپٹی اسپیکر۔ آپ پندرہ منٹ تقریر کیجئے تو مناسب ہے۔

شری سیاد اختر حسین (جنگاؤں) جناب اسپیکر صاحب۔ پندرہ منٹ بہت کم وقت ہے اگر اس مسئلہ پر مجھے کم از کم آدھا گھنٹہ تقریر کرنے کی اجازت دی جائے مناسب ہے۔

امریکہ اور پاکستان کا فوجی امداد کا باہمی معاہدہ آج اس ایوان میں زیر بحث آیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ سارے ہندوستان میں پارلیمنٹ کو چھوڑ کر یہ پہلی مثال ہے۔ مجھے امید ہے کہ اس مثال سے پورے ہندوستان کی الگ الگ ریاستوں کو نہ صرف ہم سبق دے سکتے ہیں بلکہ ان کی رہنمائی بھی کرسکتے ہیں تاکہ اس قومی اہمیت کے سوال کو وہ بھی اٹھائیں اور ایک متحدہ آواز بلند کریں۔ لیکن قبل اس کے کہ میں اس مسئلہ پر اپنے خیالات کا اظہار کروں دو چار باتیں عرض کرنا ضروری ہے۔

آج سے چند ماہ پہلے کے حالات کی جانب میں اشارہ نہیں کروں گا۔ لیکن حال میں جو تبدیلی آئی ہے اور پنڈت جواہر لال نہرو نے جس طریقے اور جس ڈھنگ سے سوچنا شروع کیا ہے اس کا اثر یہ ہے کہ پورے ملک میں یہ سمجھا جارہا ہے کہ اب وقت آگیا ہے اور اس بات کی ضرورت ہے کہ تمام پارٹیاں مل کر ایک متحدہ محاذ بنائیں اور اس کیمپین (Campaign) کو آگے بڑھائیں۔ کانگریس نے اس سے قبل جو گشتیاں جاری کی ہیں ان کے متعلق ایوان کے سب نمائندے جانتے ہیں لیکن حال میں جو تبدیلی آئی ہے۔ جس کی جانب میں اشارہ کررہا ہوں وہ یہ ہے کہ دو تین روز قبل حیدرآباد پردیش کانگریس کے صدر شری کے۔ وی۔ رنگا ریڈی نے ملک کی مختلف سیاسی جماعتوں کے نمائندوں کو بلایا تھا کہ اس سوال پر غور کیا جائے اور ممکن ہو تو ایک متحدہ محاذ بنایا جائے۔ اس محفل میں امن سوال پر مختلف لوگوں کے مختلف نقاط نظر میں ایک ہم آہنگی محسوس ہورہی تھی اور یہ سمجھا جارہا تھا کہ اس طریقہ سے کانگریس ۔ اپوزیشن کی تمام پارٹیاں اور دوسری سیاسی ۔ سماجی اور معاشی تنظیمیں مل کر اس قومی مسئلہ کو آگے بڑھا سکتی ہیں۔ لیکن مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ابھی اس ایوان میں ایک آنریبل ممبر نے اس سوال پر جن خیالات کا اظہار کیا ہے وہ نہ صرف یہ کہ انٹی نیشنل خیالات ہیں بلکہ میں یہ کہنے پر تیار ہوں کہ اگر وہ اپنے ان ہی خیالات کو ان ہی محسوسات کو ان ہی نظریوں کو ہندوستان کے وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو کے پاس بھیجیں تو وہ بھی اس کو قبول کرنے کے لئے تیار نہیں ہوں گے ۔ دوسرے الفاظ میں جن خیالات کا اظہار کیا گیا ہے وہ ہندوستان کی موجودہ خارجی پالیسی جو امن کے سلسلہ میں ہے اس کے خلاف پڑتے ہیں اور پاکستان امریکن پیکٹ کے سلسلہ میں بھی جو پالیسی ہندوستان سرکار کی ہے اس کے خلاف پڑتے ہیں۔ کیونکہ پنڈت جواہرلال نہرو نے یہ صاف صاف کہا اور دوسری

پارٹیوں نے بھی انہیں یہ یقین دلایا ھے کہ یہ ایک قومی مسلہ ھے اس پر متحدہ طور پر آواز اٹھا سکتے ھیں۔ اس میں کسی پارٹی یا کسی الگ سیاسی نقطہ نظر کا تصور نہیں آسکتا ۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ چیز بھی سامنے رکھی گئی ھے کہ بہت سی پارٹیاں اور لوگ اس مسئلہ کو اکسپلائٹ کریں گے ۔ یہ جو اندیشہ ظاھر کیا گیا ھے وہ تو پنڈت جواھر لال نہرو کے ذھن میں بھی موجود نہیں ھے جس کا اشارہ ابھی میرے محترم دوست نے کیا ھے ۔ میں اس آنریبل ایوان کے سامنے صاف الفاظ میں یہ چیز رکھنا چاھتا ھوں کہ آج دنیا کے حالات تیزی سے بدل رھے ھیں۔ پچھلی بڑی لڑائی کے بعد جو تبدیلیاں آئیں اور پچھلے چھ سات سال کے دوران میں ھندوستان کی جو خارجی پالیسی رھی اور ھندوستان کی مختلف سیاسی جماعتوں نے جس طریقہ سے ھندوستان کی امن اور جمہوریت کی خارجی پالیسی کی تائید کی اس کے بعد پھر اس طریقہ سے ان پارٹیوں کے متعلق شکوک اور بے اعتمادی ظاھر کرنا خود اس بات کی دلیل ھے کہ کانگریس کے اندر آج بھی ایسے عناصر موجود ھیں جو وسیع نقطے نظر سے نہیں سوچنا چاھتے ۔ اور آج اس مسئلہ کو اتنی اھمیت دینے کے لئے تیار نہیں ھیں جتنی اھمیت کا مستحق وہ مسئلہ ھے اس کو دوسرے ڈائورشن میں لیجانا چاھتے ھیں۔ وہ وھی سمت ھے جس کی جانب امریکی سامراج آج ھندوستان کو لیجانا چاھتا ھے ۔ وہ چاھتا ھے کہ ھندوستان کے اندر ایسے عناصر باقی رھیں جو اس مسلہ کو اس طریقہ سے پیش کر کے آپس میں پھوٹ پیدا کرنے کوشش کریں ۔ اور رجعت پسند اور فرقہ پرست عناصر کو حاوی رکھیں اور ایسی فضاء پیدا کریں جس کے تحت پنڈت نہرو کی پالیسی کو ناکام بنایا جائے ۔ مجھے اندیشہ ھے کہ ان ھی احساسات کو ۔ ان ھی نظریات کو لیکر چلنے کی کوشش کی گئی ھے ۔ تاکہ امریکی سامراج اس سازش میں کامیاب ھوجائے اور اگر کامیاب نہ بھی ھو تو کم از کم اس کو تقویت تو حاصل ھو جائے ۔ اس لئے میں ان ترمیمات کی مخالفت کرتے ھوئے اپنے آنریبل دوست سے یہ عرض کروں گا کہ وہ اپنی ترمیمات کو واپس لے لیں چونکہ وہ خود ھندوستان کی خارجی پالیسی اور پنڈت نہرو کے منشاء کے خلاف ھیں اور اس وقت ھمارے سامنے جو سوال ھے اس کو نظر انداز کرنے کے برابر ھے۔ یہ خیالات ایسے خطرناک رجحان کا پتہ دیتے ھیں جس سے ھمارے ملک کے بڑھتے ھوئے اتحاد کیلئے خطرہ پیدا ھو جاتا ھے ۔ اس نقطے نظر اور اس رجحان کو چھوڑنا ضروری ھے ۔

اس کے بعد میں ایوان کے سامنے پس منظر کے طور پر چند بین الاقوامی حالات کی جانب اشارہ کروں گا ۔ اس لئے کہ جب تک اون کو نہ سمجھا جائے اس مسئلہ کے خدوخال کو سمجھنے میں مشکل پیش آئے گی۔ پچھلی بڑی لڑائی کے بعد سے دنیا کے اندر ایک بڑی سامراجی طاقت کی حیثیت سے امریکہ کا حکمران طبقہ سامنے آیا ھے ۔ اس نے پچھلے آٹھ نو سال میں ساری دنیا میں اپنے فوجی اڈے قائم کرنے کی کوشش کی ھے ۔ مشرق بعید میں ۔ مشرق وسطی میں ۔ یورپ اور مغربی ممالک میں اور خود برطانیہ میں (اون پر اپنے چھوٹے بھائی کی حیثیت سے دباؤ ڈال کر) فوجی اڈے قائم کئے ۔ یہ عمل

خود اوس کے ارادوں کی دلیل ہے اور اوس سے حقیقتاً کوئی بھی انکار نہیں کرسکتا ۔ میں اس سلسلہ میں خود ایک امریکی اخبار کے اعداد و شمار آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں ۔ ''یو۔ یس ۔ نیوز اینڈ ورلڈ رپورٹ،، نے اپنی ۲۰ ۔ڈسمبرسنہ ۵۳ع کی اشاعت میں ایک مضمون شائع کیا ہے جس میں اوس نے بتایا ہے کہ آج کمیونسٹ ممالک کو چھوڑکر دنیا کے ۶۳ ملکوں کی سر زمین پر امریکہ کے فوجی اڈے قائم ہیں ۔ یہ حقیقت اوسی اخبار کی زبان سے ہم سن رہے ہیں جو وہاں کا ایک نیم سرکاری اخبار سمجھا جاتاہے ۔ اس نے یہ بتایا ہےکہ ان اڈوں پر دس لاکھ امریکی سپاہی ۔ اور دوسرے امریکی مبصرین اور اکسپرٹس کی حیثیت سے موجود ہیں ۔ اس نے یہ بھی بتایا ہے کہ پچھلی لڑائی کےوقت ان اڈوں کی تعداد (۳۰) تھی ۔ اس کے معنے یہ ہیں کہ امریکہ کی اگریسیو پالیسی اور جارحانہ اقدام مسلسل آگے بڑھتا جا رہا ہے ۔ چند سالوں کے اندر ہی اوس نے صرف اپنے فوجی اڈوں کا جال اس قدر پھیلادیا بلکہ دنیا کے آزاد اور جمہوری ممالک کو بھی اپنے گھیرے میں لیتا جارہا ہے تاکہ اپنی جنگی معیشت برقرار رکھی جاسکے ۔ اپنی منڈیاں بڑھائی جاسکیں ۔ اپنے کاروبار اور منافع کو بڑھایا جاسکے ۔ اپنےتسلط کو برقرار رکھا جائے اور اوس کو تقویت پہنچائی جائے۔وہ تیسری عالمی جنگ شروع کر کے جنگی فضا کو باقی رکھکر اپنے ناپاک منصوبوں کو پورا کرنا چاہتا ہے ۔ اگر کسی گوشہ سے بھی یہ کہا جائے کہ سوویٹ روس جنگ چاہتا ہے یا چین جنگ چاہتا ہے تووہ غلط ہے ۔ فاشسیت اور امپریلسٹ طاقتیں ہی اس کی گنہگار ہیں ہندوستان کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں ۔ اور کانگریس کے اندر بھی جو ایماندار عناصر اور دوسری پارٹیوں کے لوگ اور ساری دنیا کے آزادی پسند اور امن پسندوست لوگوں کی زبان سے کبھی ہمارے یہ سننے میں نہیں آیا کہ سوویٹ روس یا چین جنگ چاہتے ہیں ۔ پنڈت سندر لال جی ۔ جے ۔ سی کمار اپا ، سیف الدین کچلو اور دوسرے بہت سارے لوگ جو پچھلے چند سالوں میں روس اور چائنا ہوآئے ہیں انہوں نے صاف صاف الفاظ میں کہا ہے کہ روس میں ایک بھی ایسا شخص نہیں ملیگا جو جنگ چاہتا ہو۔ وہ لوگ امن کے خواہاں ہیں ۔ وہ ملک اپنے تعمیری کاموں میں مصروف ہے ۔ یہی حال چین کا بھی ہے ۔ معقول طور پر بات سمجھ میں آنے والی ہے ۔ کیوں کہ پچھلی بڑی لڑائی میں سب سے زیادہ نقصان سوویٹ روس نے اٹھایا ہے ۔ اب وہاں کے لوگ اپنے ملک کی نئی تعمیر میں لگے ہوے ہیں ۔ اوس ڈھانچے کو جو ٹوٹ گیا ہے ۔ جو شکست ہوگیا ہے بنانے میں مصروف ہیں وہ لوگ کس طرح جنگ کے متعلق سوچ بھی سکتے ہیں۔

اس کے متعلق نظریاتی بحث بھی کی جائے تو اس کے ثبوت میں ہمیں کوئی دلیل نہیں ملتی ۔ اگر ہم حالات کا جائزہ لیں اور دنیا کے نقشہ پر نظر ڈالیں تو معلوم ہوگا کہ چین اور روس میں جنگی حالات نظر نہیں آتے ۔ اس کے برخلاف امریکہ نے خود وہاں کے اخبار کے بیان کے مطابق دنیا کے ۶۳ ممالک میں اپنے فوجی اڈے قائم کئے ہیں ۔ دوسری بڑی لڑائی میں جن ملکوں کو غلام بنایا گیا وہاں فوجی اڈے

قائم کئے - مشرق کے بعض ملکوں میں بھی یہی حال ہے۔ جاپان سے امریکہ نے حال ہی میں فوجی معاہدہ کیا ہے اور وہاں بھی فوجی اڈے قائم کئے ہیں - یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایشیا کے اندر امریکہ کے کیا منصوبے ہیں - فارموسا میں چیانگ کائی شیک کو باقی رکھکر جس طرح سے اس کی مدد کی جارہی ہے یہ اس کی دوسری دلیل ہے۔ اسی طرح مشرق بعید کے دوسرے ملکوں کو جس طرح سے امریکہ کی مدد مل رہی ہے اس کے بارے میں تمام لوگ جانتے ہیں -اخباروں میں روزانہ خبریں آتی ہیں - حال ہی کا واقعہ ہے کہ امریکہ کے بمبار ہوائی جہاز انڈوچینا کی لڑائی میں مصروف دیکھے گئے۔ پنڈت نہرو چاہتے ہیں کہ انڈوچینا کے اندر امن قائم ہو اور وہاں جنگ بند ہوجائے لیکن دوسری طرف امریکی فوجی بمبار وہاں اپنی کارروائیوں میں مصروف نظر آتے ہیں - اسی طرح سے مشرق بعید اور مشرق وسطی میں اور خود برطانیہ میں بھی جو امریکی سامراج کا چھوٹا بھائی ہے اس کے فوجی اڈے قائم ہیں برطانیہ کے جہاں جہاں اثرات تھے وہاں سے اس کو نکال کر خود اپنا تسلط قائم کررہا ہے۔ ترکی کے ساتھ جس طرح اس نے فوجی معاہدہ کیا۔ مصر میں جس طرح گڑبڑ پیدا کرنے کی کوشش کی - ایران میں جس طرح ڈاکٹر مصدق کی حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا یہ سب چیزیں اس کے جارحانہ عزائم کی دلیل ہیں - ان ممالک کے بعد اب پاکستان میں وہ آرہا ہے۔ پاکستان اور امریکہ کا فوجی معاہدہ ہورہا ہے۔ اس کے پیچھے کونسی کوشش کام کررہی ہے۔ امریکی سامراج کی جانب سے اون ملکوں کے خلاف جن کی سرحدیں پاکستان سے ملتی ہیں ایک گھیرا ڈالنے کی کوشش کیجارہی ہے۔ جب ہم اس واقعہ پر نظر ڈالتے ہیں تو اوس کوشش کے خدوخال صاف صاف نظر آجاتے ہیں - پاکستان کی سرحد ایک طرف سویٹ روس اور دوسری طرف ہندوستان سے ملی ہوئی ہیں - اس موقف سے فائدہ اٹھاکر امریکہ یہ کوشش کررہا ہے کہ واشنگٹن سے لاهور تک ایک ایسا خط کھینچا جائے کہ جنگ کی صورت میں روس اور چین پر بمباری کیجاسکے - چونکہ ہندوستانی عوام - ہندوستانی حکومت امریکہ کے آگے جھکنے کے لئے تیار نہیں ہیں - امریکہ کی غلامی کو وہ قبول نہیں کرتے اس لئے اوس پر اس طرح سے دباؤ ڈالنے کی کوشش کیجارہی ہے۔ وہ رجعت پسند اور فرقہ پرست عناصر جو اس خام خیالی میں مبتلا ہیں کہ سیاسی پارٹیاں اس کو اکسپلائٹ کرینگے۔ اور اندرونی طورپر بغاوت پیدا کرکے یہاں کی جمہوری حکومت کا تختہ الٹ کر ہندوستان میں اپنا تسلط قائم کرینگی - ہندوستان سے قریب اور اس کی سرحدوں سے ملے ہوئے جو دوسرے ممالک مثلاً سیلون انڈوچینا - ملایا وغیرہ ہیں اون پر مغربی سامراج کا تسلط پہلے سے ہی قائم ہے۔ اس سامراج کے خلاف جب ایک متحدہ محاذ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے تو اس قسم کے اندیشے اور شبہات پیش کئے جاتے ہیں جس طرح سے کہ ابھی پیش کئے گئے ہیں - ایک متحدہ محاذ بناکر جب اس خطرناک طاقت کے بڑھتے ہوئے سیلاب کو روکنے کی کوشش کیجارہی ہے تو مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ اس قسم کی باتیں بعض گوشوں

سے کی جارہی ہیں - لیکن اس قسم کی باتیں آج کامیاب نہیں ہوسکتیں - ہندوستان کی بیدار جنتا اور ہندوستان کی بیدار قیادت اس قسم کی باتوں کو قبول نہیں کرسکتی -

پنڈت جواہر لعل نہرو نے پاک امریکی معاہدہ کے خلاف اپنی آواز بلند کی اور اس سلسلے میں جو تقریریں پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ سے باہر انہوں نے کی ہیں انکا ہندوستان کے ہر گوشے میں خیر مقدم کیا گیا ہے۔ سوویٹ روس اور چین پر امریکہ کی طرف سے جو ڈورے ڈالنے کی کوشش کی جارہی ہے وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جنگ کی آگ کو امریکہ بھڑکانا چاہتا ہے۔ اس بارے میں ہندوستان کے عوام پنڈت جواہر لعل نہرو کی پالیسی سے بالکل متفق ہیں - یہی نہیں بلکہ سوویٹ روس کے وزیراعظم نے بھی پنڈت جواہرلعل نہرو کی پالیسی کا خیر مقدم کیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ پنڈت نہرو امن کی خاطر بہت بڑا پارٹ پلے (Part play) کررہے ہیں - ایک طرف تو وہ ممالک ہیں جو امن پسند ممالک کے ساتھ دینے کے لئے آگے بڑھ رہے ہیں اور دوسری طرف کچھ اس قسم کی باتیں کی جارہی ہیں جن سے اون پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کیجارہی ہے۔ اس موقعہ پر میں اس مسئلہ کے دو ایک پہلوؤں پر روشنی ڈالنے کی کوشش کرونگا - اس لئے کہ وقت کم ہے۔ اس مختصر سے وقت میں مسائل کے پورے پھیلاؤ کو سمیٹا نہیں جاسکتا - یہ کہا گیا ہے کہ آئندہ ہندوستان اور پاکستان کے تعلقات کس طرح کے رہینگے - میں واضح لفظوں میں صاف طور پر اعلان کرونگا کہ ہندوستان کے عوام ہندوستان کے جمہور پسند طبقات پاکستان کی آزادی اور پاکستان کی خوشحالی اور سلامتی کے خلاف نہیں ہیں۔ اس چھوٹے سے نازک فرق کو ہمیں محسوس کرنا چاہئے کہ ہمارے احتجاج کا رخ پاکستانیوں کی طرف نہیں بلکہ پاکستان کے اون حکمرانوں کے خلاف ہے جو امریکی سازش میں پھنس گئے ہیں اور اس کی غلامی کا طوق اپنے گلے میں ڈال رہے ہیں - ہم تو یہ چاہتے ہیں کے پاکستان سے ہمارے تعلقات ترقی کریں ثقافتی معاشی اور تجارتی تعلقات ترقی کریں خود پاکستان کے عوام اس امریکی امداد کے خلاف ہیں - ان کے احتجاج کی آواز کہیں کمزور اور کہیں طاقتور ہے - میں مغربی پاکستان کے بعض اخبارت کا ذکر کرونگا - امروز اور پاکستان ٹائمس (Pakistan Times) جو وہاں کے طاقتور اخبارات ہیں - (Bell rung) میں نے درخواست کی تھی کہ مجھے کچھ زیادہ وقت دیاجائے اور یہ سمجھکر کہ میری درخواست قبول کی گئی اپنی تقریر کو اس لحاظ سے آگے بڑھارہا ہوں - ....

مسٹر ڈپٹی اسپیکر - (۳۰) منٹ ہونے کےلئے (۳) منٹ باقی ہیں -

سیداختر حسین - میں عرض کروں گا کہ پاکستان میں بھی اس معاہدہ کےخلاف احتجاج ہورہا ہے۔ مغربی پاکستان میں کم ہو رہا ہے اور مشرقی پاکستان میں زیادہ - ہندوستان اور پاکستان کے عوام کا احتجاج اس بات کی دلیل ہے کہ یہ دونوں اپنے ہمسایہ ملکوں

کے ساتھ دوستانہ تعلقات رکھنے اور امن قائم رکھنے کی جدو جہد کرر ہے ہیں ۔ اور اس معاہدہ کے خطرناک اثرات کا احساس رکھتے ہیں ۔ آیزن ہور نے صدارت کی کرسی پر آنے کے بعد اعلان کیا تھا کہ ایشیائی والوں کو ایشیائی والوں سے لڑاؤ ۔ امریکی سامراج ایشیائی کی سرحدوں پر جنگ کی آگ بھڑکا کر یہاں کے لوگوں کو ایندھن کی طرح استعمال کرنا چاہتا ہے ۔

ان خطرناک مقاصد کو عوام پیش نظر رکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اختلافات کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہے گی ۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں متحدہ طور پر آگے بڑھکر اس سازش کے تختہ کو الٹ دینا چاہئے ۔ اور اگر ہم متحدہ طورپر آگے بڑھیں تو اس سازش کو ناکام بناسکتے ہیں ۔ صرف یہ کہکر ہم خاموش ہوجائیں کہ پنڈت جواہر لعل نہرو اس سازش کو ناکام بنانے کے لئے کوشش کررہے ہیں تو یہ مقصد حاصل ہونے والا نہیں ہے ۔ اگر ہم پورے ملک کو اس مسئلہ پر متحد نہ کرسکیں تو صرف پنڈت جواہرلعل نہرو کے احتجاج سے کام چلنے والا نہیں ہے ۔ سرد جنگ ہندوستان کی سرحدوں پر آگئی ہے ۔ ہندوستان میں بھی سازشیں ہورہی ہیں ۔ یہاں امریکنس ہر جگہ پھیلے ہوئے ہیں ۔ ہمارے مدرسوں میں ۔ ہمارے کھیتوں میں ہمارے کارخانوں میں ہمارے بازاروں میں اور ہمارے دفتروں میں ٹیکنیکل اڈوائیزرس کی صورت میں اور مختلف روپ میں اخبارات کے مطالعہ سے معلوم ہوگا کہ وہ اپنے فلموں کے ذریعہ اپنی کتابوں اور لائبریریوں کے ذریعہ اور دوسرے ذرائع اور اپنی مشنریز کے ذریعہ کمیونیزم کے خلاف اور پنڈت جواہر لعل نہرو کی پالیسی کے خلاف عوام کو ابھاررہے ہیں اور پروپیگنڈہ کررہے ہیں ۔ یہ نہایت خطرناک چیز ہے ۔ اور ہمارا داخلی اور گھریلو خطرہ ہے جو بڑھتا جارہا ہے ۔ اس کے انسداد کیلئے متحدہ طور پر آگے بڑھنا چاہئے ۔ لیکن یہ ہمارا متحدہ محاذ پاکستان کے خلاف نہیں ہوگا ۔ پاکستان کے عوام کے خلاف نہیں ہوگا بلکہ پاکستان کے اون حکمرانوں کے خلاف ہے جو امریکی جال میں پھنس گئے ہیں اور پورے مشرق بعید کو اس جال میں گرفتار کررہے ہیں ۔ میں ایوان سے اپیل کرونگا کہ اس اہم مسئلہ پر تنگ نظری کے ساتھ نہ سوچا جائے اگر ایسا کیا گیا اور اسکو وسیع حدود میں لاکر دیکھنے کی کوشش نہ کیگئی جیسا کہ سوچے جانے کی وہ مستحق ہے اور پنڈت جواہرلعل نہرو کی پالیسی ہمارے پیش نظر نہ رہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سوال پر جس اہمیت کے ساتھ غور کیا جانا چاہئے نہ کرسکینگے ۔ اگر ہم خوابوں کی تعبیر میں الجھہ جائیں اور آنے والے اندیشوں کو نظرانداز کردیں تو یہ ہمارے لئے ناقابل تلافی نقصان ہوگا ۔ چاہئیے کہ کانگریس پارٹی متحدہ طریقہ پر کمپین (Campaign) چلائے اور سب ایک نقطۂ پر متحد ہوجائیں اور اس میں انتشار آنے نہ پائے اور کسی گوشے سے انتشار پیدا کرنے کی کوشش نہ کی جائے تو ہم ضرور اپنے مقصد میں کامیاب ہوسکتے ہیں ۔ میں چند اقتباسات ہاؤز کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں لیکن وقت کم ہے اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ

دوسرے لوگ اس مسئلہ کے سلسلے میں اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔....

श्री. व्ही. डी. देशपांडे :—मुझे आप से अपील करना है कि करीब १० लोगों की जानिब से रेजोल्यूशन हाउस के सामने आया है, और अभी जिन्होंने तकरीर की है वे अुसमेंसे अेक है। अुनको अपने ख्यालात को रखने का मोका दिया जाय तो बहतर होगा, क्योंकि रेजोल्युशन आज खतम होने वाला नहीं है। अगले नॉन-ऑफिशीयल डे पर भी यह चलने वाला है। अिसलिये जिन्होंने रेजोल्यूशन रखा है अुनको ज्यादा वक्त दिया जाय। हालांकि मुहरकीन टाअिम का खयाल रखेंगे।

مسٹرڈپٹی اسپیکر۔ جملہ ۱۰ محرکین ہیں۔ ان سب کے لئے وقت دیا جائے تو دقت ہوگی ۔

श्री. व्ही. डी. देशपांडे :—लेकिन सब मुहरकीन आधे घंटे तक तकरीर करने वाले नहीं ह

مسٹرڈپٹی‌اسپیکر۔ جو جو محرکین تقریر فرمانا چاھیں انہیں کافی وقت نہ دیا جائے تو ڈسکشن کی اسپرٹ فوت ہوجائیگی ۔

Shri V.B. Raju : Mr. Speaker, Sir, I would like to submit that the Leader of the Opposition and the Leader of the House should hereafter try to draw up a panel of names of Speakers from both sides, so that there may not be a confusion like this. The Mover of the resolution himself has, in my opinion, taken about 40 minutes, and if the Members of the Opposition themselves want to speak all the day, the Members on this side will not have an opportunity to speak at all. Let us try to fix the time-limit of 15 minutes for each Member and try to complete the speech.

The Chief Minister (Shri B. Ramkrishna Rao) : I would like to suggest, Sir, that this is a very important matter and I am sure hon. Members on both sides will have a desire to speak and express their views. I would request you to give them consideration and allow them to speak, of course fixing the time-limit. I understand that on this side of the House there are a number of Members who want to speak on this resolution. I feel that probably on the other side also there will be a number of Members who will be wanting to speak. I have absolutely no objection if you give them enough time to express their views.

Mr. Deputy Speaker : I think, if many members derire to speak, it is better to fix the time limit at 15 minutes and not more than that.

श्री. नरेंद्र (कारवान) : अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव अमेरिका और पाकिस्तान के बीच मुआहदे के संबंध में हाअुस के सामने आया है अुसके जरिये से हैदराबाद की तारीख में और हैदराबाद की असेंब्ली की तारीख में यह पहला मौका हमने बहाल किया है जिसके अूपर हम न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि हिंदुस्तान के बाहर के मुल्कों के बारे में अपने खियालात का अिजहार कर सकते हैं। मुझे अिस सवाल की तरफ देखने से वह कहावत याद आती है कि तारीख अपने को दोहराती है और यह मसला भी अुसी मानों में बिल्कुल सहीं मालूम होता है। मुगल बादशाहों के जमाने में जहांगीर ने अेक बडी तारीखी गलती की थी और वह यह थी कि ब्रिटिश लोगोंको अुन्होंने हिंदुस्तान में तिजारत करने का मौका दिया। आज पाकिस्तान दूसरी अेक बहुत बडी गलती दोहरा रहा है कि वह अेशिया के अंदर अमेरिका को फौजी अड्डा दे रहा है। अखबारात में अिस मुआहदे के बारे में जो खबरें आअी हैं अुनसे मालूम होता है कि यह दूसरी गलती दुयनिया की तारीक में हो रही है कि अेशिया के अंदर साम्राजियत को आगे बढने के लिये मौका दिया जा रहा है। अिस सवाल की तरफ देखने से बहुत सारी पुरानी बातें याद आती हैं। आप सब पर यह वाजे है कि १९१४ के पहले जंग के मौके पर आम तौर पर अमेरिका की पालिसी तिजारती पालिसी रही। अुसका यहीं मकसद रहा कि दुनिया के मार्कटों में अपने कारखाने में बनाअी हुअी चीजें फराहम करें और सरमाया जमा करें। अिस तरह अमेरिका ने अुस वक्त लडाअी में अपने आपको शरीक नहीं किया, और अिस पॉलिसी को लेकर पहले जंग के मौके पर अुसने बिल्कुल अलहदा रहना मुनासिब समझा। अुसमें तमाम दुनिया के अंदर अपने कारखानोंसे बनने वालीं हथियार सप्लाय कर के दुनिया की लडाअी को अपने आंखों से देखते हुअे अपने मुल्क को दौलत से मालामाल बनाने की पालिसी अेख्तियार की, लेकिन हालात बदलने लगे, जमाने ने करवट बदली, दो भिन्न विचार-धाराअें दुनियाके अंदर काम करने लगीं तो अुसका नतीजा यह हुआ कि दूसरी बडी लडाअी हमारे सामने आअी। मैं समझता हूं कि दूसरी लडाअी दो खियालात की टक्कर थी। साम्राजियत और डिक्टेटरशिप (Dictatorship) के दरमियान की वह अेक बहुत बडी लडाअी थी। अुसमें साम्राजियत ने डिक्टेटरशिप का मुकाबला किया, लेकिन अुस वक्त अेक अव्वाम का मुत्तहिदा महाज कायम हुआ। दुनिया के लोगों ने महसूस किया कि अगर हम सब मुत्तफिकैं होकर डिक्टेटरशिप का मुकाबला नहीं करते तो बहुत मुमकिन था कि सारी दुनिया में हिटलर का फैसीजम (Fascism) और अुसका राज कायम होजाता और अिन्सानियत और जमहूरियत का जो अेक गहरा ताल्लुक है वह खतम होजाता। अिस मौके पर अमेरिका अेक साम्राजियत के तौर पर अुनमें शामिल हुआ और अुसने हिटलर के जंग का मुकाबिला किया। अुसके बाद से अमेरिका की दुनिया के अंदर जो कोशिशें रहीं अुनकी तरफ सिर्फ अिशारा कर देना मैं अिस वक्त जरूरी समझता हूं। जब लडाअी यूरोप से निकलकर अेशिया की तरफ बढी तो जापानी फौजें रंगून तक आकर पहूंची, और अिस तरह से डिक्टेटरशिप ने अेक बहुत बडे अिलाके पर अपना अेख्तदार जमा लिया तो अुसका नतीजा यह निकला कि रूस, अमेरिका, अिग्लंड और फ्रान्स की फौजें दुनिया में कुछ जर्मनी की तरफ और कुछ अेशिया की तरफ अिस तरह से बंट गअीं। नतीजतन जापान को अेशिया में हार खानी पडी और वह खास तौर से अमेरिका की वजह से। तबसे लेकर आज तक अमेरिका ने अेशिया के अंदर अपने सियासी मकसदों को पूरा करने के लिये अनेक चालबाजियां कीं। जापान अुस वक्त दो हिस्सों में बांटा गया। जापान के अंदर अुसने

काफी कोशिश की। जापान आखिर असके कब्जे से निकल गया है। कोरिया का भी वही हाल हुआ। जिस तरह से अमरिका का जो अिरादा था कि अेशिया मे अपना अड्डा कायम करे वह पूरी तरह से सफल न हो सका। अमेरिका का मुकाबला करनेवाली दूसरी कुवत दुनिया में रूस की थी जो चाहती थी कि अपनी विचारधारा का अेशिया के अंदर फैलाव हो । मै यह कहन चाहता था कि पाकिस्तान और अमेरिका का यह जो मुआहदा है, वह अमेरिका की अेशिया में अपने फौजी अड्डे बनाने की कोशिश का अेक जुज है। अिन खियालात की ताअीद वजीरे आजम पाकिस्तान के अुस बयान से होती है जो अुन्होने कलकत्ते के डमडम हवाअी अड्डे पर लकाके वजीरे आजम से मुलाकात के वक्त अखबारवालो के सामने दिया था। अुन्होने कहा था कि अमेरिका और पाकिस्तान के बीच जो मुआहदा हो रहा है वह तीन बातों को सामने रखकर किया जा रहा है। सब से पहली बात कश्मीर का मसला है, दूसरी बात हमारी हिफाजत का सवाल है और तीसरी बात अशिया मे बढती हुअी कम्युनिस्टो की ताकत है। अिन बातों को पेशेनजर रखते हुअे पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ मुआहदा करना जरूरी समझा। मे अिस मुआहदे को दो गरजमदों के बीच का मुआहदा समझता हूं। अेक तरफ अमेरिका को अेशिया के अदर कदम जमाने के लिये जगह चाहिये और दूसरी तरफ पाकिस्तान का जो मआशी ढांचा बुरी तरह अुखड चुका है, अुसको पाकिस्तान सम्हालना चाहता है। पाकिस्तान की अेख्तदार सियासी जमाअत मुस्लिम लीग जो आज कराची में अपना अेख्तियार जमाय हुअ है वह मशरीकी पाकिस्तान के अंदर मार खा चुकी है। मशरीकी पाकिस्तान के अंदर जो अभी चुनाव लडे गये वे अिसी बुनियाद पर लडे गये कि अमेरिका और पाकिस्तान के बीच मुआहदा किया जाय या न किया जाय।

Shri B. D. Deshmukh (Chairman) in the Chair

मशरीकी पाकिस्तान की मुस्लिम लीग के खिलाफ वहां की अव्वाम ने अेक युनायटेड फरंट कायम किया। अुसका यही नारा था कि यह मुआहदा अेशिया की आजादी और अेशिया की अव्वाम के लिये खतरा है और अिनसानियत को बहुत बुरी तरहसे नीचे गिरानेवाला है। अिन्ही जजबात को लेकर मशरीकी पाकिस्तान की अव्वाम ने अिलेक्शन की लडाअी लडी और अुसने कराची की बरसरे अेखतेदार पार्टी के लोगों की आंखे खोल दी। अुन्होंने बताया कि अिस मुआहदे के खिलाफ स्वयं पाकिस्तान की जनता है। मेरे कहने का मंशा यह था की अमेरिका ने अपने अेक खास सियासी मकसद को लेकर अेशिया में आगे बढने की कोशिश की है और जापान के अंदर जब अुसको पूरी शिकस्त हुअी तो अुसने चायना के अंदर भी अपने कदम बढाये। अभी अभी अेक ऑनरेबल मेंबर ने अखबारात से कुछ आंकडे पेश करते हुअे बताया कि लडाअी के पहले, दरमियान में और बाद में अमेरिका के दुनिया में किन जगहों पर कितने अड्डे है, अुसी तरह से मै हवाला देकर बतला सकता हूं कि दुनिया की दूसरी जंग खतम होने के बाद चायना की सरकार को जो अुस वक्त अेक नेशनलिस्ट सरकार कहलाती थी, अुसको ८० करोड डालर की मदद दी गअी। ८० करोड डालर के हथियार अुस वक्त की चीनी सरकार को अमेरिकाने सप्लाय किये थे और वह भी अिसी अिरादे से कि अुन हथियारों के बल पर चायना जैसे अेशिया की बहुत बडी ताकत पर वह कब्जा हासिल कर सकेंगे। चीन जो अेशिया का दरवाजा कहलाता है अुसको हासिल करके हम आसानी से अेशिया में अपने पैर फैला सकेंगें। मगर वहां के बदलते हुअे हालात और वहां की अव्वाम के जजबात चाहे वह किसी भी पार्टी के हों, कोअी भी गवर्नमेंट अुन्होंने वहां कायम की हो अुससे हमें

यहां पर बहस नहीं है लेकिन यह कहने पर मैं अपने आपको मजबूर हूं कि अमेरिका के हथियार खुद अमेरिका के मौत के लिये कारण हुअे और आखिर में चायना से अुनके पैर पूरी तरह से अुखड गये। अिसके बाद अमेरिका की सियासी पार्टियों ने समझा कि अेक बहुत बडा मुल्क हमारे हाथ से निकल गया। अब हमें अेशिया के दूसरे किसी मुल्क में कोशिश करनी चाहिये और अपने को मजबूत बनाना चाहिये। अिस दृष्टि से अुन्होंने दूसरी कोशिश हिंदुस्तान में करनी चाहि। अुस वक्त मुझे अुस जमाने की याद दिलाने की जरूरत नहीं है कि जब हिंदुस्तान में अजनास की हालत बहुत खराब थी और हमें दूसरे मुल्कों से अनाज लाना पडता था वह भी अिसी अिरादे से कि चाहे रुपया कितना ही लगे लेकिन हम अपने मुल्क के किसी आदमी को अनाज की कमी की वजह से मरने नहीं देंगे। फिर चाहे हमारी तरक्की रूक जाय, यह जो हम में जजबात थे अुनकी वजह से हमें अमेरिका से अनाज मंगवाना पडा। अुस वक्त अमेरिका ने गेहूं वगैरा अनाज देने के बारे में कुछ पाबंदियां आयद करने की कोशिश की, अुस सिलसिले में पार्लिमेंट में तकरीर करते हुअे हिंदुस्तान के वजीरे आजम पंडित जवहरलाल नेहरू ने पाबंदियों के साथ अिस तरह की अनाज की अिमदाद को लेने से अिन्कार किया। अुन्होंने कहा कि पाबंदियों के साथ रोटी खाकर जिंदा रहने के बजाय बिना रोटी के हिंदुस्तान में अगर आदमी मरते हैं तो मैं अुन्हें मरते हुअे देखना ही पसंद करूंगा, लेकिन पाबंदियों की रोटी खाकर गुलामी की जिंदगी बसर करना न मैं खुद चाहता हूं और न मेरा मुल्क चाहता है। हिंदुस्तान की पूरी अव्वाम के जजबात की यह तकरीर अेक नजीर थी। अुस वक्त अमेरिका ने समझा कि अिस तरह से हिंदुस्तान पर पाबंदियां डालने से काम चलनेवाला नहीं है तो अुन्हों ने दूसरी चाल चली। हिंदुस्तान के वजीरे आजम पंडित नेहरू को अमेरिका बुलाकर अुनका शानदार अिस्तकबाल किया। चमकीले और रंगीले तरीकों से अपनी सियासी चालों के अंदर हिंदुस्तान के वजीरे आजम को अपनी तरफ खींचने की कोशिश की लेकिन अुसमें भी वह नाकामयाब हुअे। यह अमेरिका के लिये दूसरी नाकामयाबी थी। अुसकी तीसरी नाकामयाबी कश्मीर के अंदर हुअी। कश्मीर अिस वक्त दो हिस्सों में बांटा गया है और वहां क्या चल रहा है वह आप सब पर वाजे है। कश्मीर में अुन्होंने बहुत धुम मचाअी। दो तीन महीने पहले मुझे कश्मीर जाने का मौका हुआ था। वहां की बरसरे अेक्तेदार पार्टी के अच्छे से अच्छे लोगों से मुलाकात करने का मौका मिला। अुन्होंने बताया कि अमेरिका ने वहां अिस बात की कोशिश की थी कि कश्मीर की अव्वाम में हिंदुस्तान के खिलाफ किसी तरह से जजबात पैदा कर के कश्मीर के लोग आजाद रहें और अपना अेक अलाहिदा स्टेट बनायें। अुस वक्त के कश्मीर के वजीरे आजम शेख अब्दुल्ला के साथ अुन्होंने अपने संबंध प्रस्थापित किये और अुनके के साथ अिस तरह का अेक मुआहदा तकमील पानेवाला ही था कि वह राजफाश हुआ और वहां की अव्वाम ने शेख अब्दुल्ला को अुनकी जगह से निकाल कर अपने भरोसे के दूसरे लोगों के हाथमें हुकूमत की बागडोर सोंपी। अमेरिका की यह तीसरी नाकामयाबी थी जो अेशिया के अंदर अुसने अपने पैर फैलाने के लिये की थी। आज कश्मीर का अेक बडा सवाल दुनिया के सामने है। कश्मीर में अिस तरह से नाकामयाबी होने के बाद अुन्होंने सोंचा कि किसी न किसी तरह से अेशिया के अंदर हमारे फौजी अड्डे कायम होने चाहियें। हम देखते हैं कि पाकिस्तान की अव्वाम में मजहबी जजबात का बहुत ज्यादा असर है। मैंने यह पहले ही बताया कि आज पाकिस्तान का मआशी ढांचा बुरी तरह से बिगड चुका है। अनाज मिलने वहां मुश्किल है, बेकारी बढ गअी है, मकानात का मसला अभी हल नहीं हुआ है। अैसी हालत में पाकिस्तान की अव्वाम में मौजूदा हुकूमत के खिलाफ जबर्दस्त नाराजी

फैल रही थी और वहां की हुकूमत के लिये अेक जबर्दस्त खतरा पैदा हो गया था। अुससे बचने के लिये पाकिस्तान की अव्वाम के मजहबी खियालात का फायदा अुठाकर अुसका ख्याल हुकूमत की तरफ से हटा कर किसी और चीज की तरफ दिलाने की कोशिश की गअी है, लेकिन अिसका नतीजा क्या हुआ वह पूर्व पाकिस्तान में अभी अभी जो चुनाव हुअे, अुनसे जाहीर होता है। मैं यह कह रहा था कि अमेरिका सोंच रही थी कि किसी तरह से अेशिया में फौजी अड्डे तैयार करने चाहिये, और पाकिस्तान के अंदरूनी हालात से अुसने फायदा अुठाया। पाकिस्तान को अेक अड्डा बनाया गया और पाकिस्तान ने भी अुसको कुबूल किया। अिसके साथ साथ हमको अखबारात के जरिये से मालूम हुआ है कि टर्की (Turkey) और पाकिस्तान के बीच में भी मुआहदा हुआ है और अमेरिका और टर्की के बीच में अेक मुआहदा हुआ है। अिस तरह से अमेरिका टर्की से लेकर पाकिस्तान तक अेक लाअिन खींचना चाहता है जिससे अेशिया के अंदर वह अपने फौजी अड्डे कायम कर सके और साम्राजियत को फैला सके। अिसके बाद आपको मालूम है कि पाकिस्तान के वजीरे आजम ने अैलान किया था कि अमेरिका और पाकिस्तान के बीच का मुआहदा अेक अंदरूनी मामला है, अुसमें हिंदुस्तान या और किसी भी मुल्क को दखल देने का अख्तियार नही है। अिसमें कोअी शक नहीं कि यह पाकिस्तान का अेक अंदरूनी मसला है और पंडित जवाहरलालजी भी अिसको मानते हैं, लेकिन अेक पडोसी मुल्क की हैसीयत से यह जरूरी हो जाता है कि अुसके अंदरूनी मामले में जो अहम तबदीलियां हो रही हैं अुसका असर हमारे अूपर और दुनिया के अूपर क्या होनेवाला है, क्योंकि आज के विज्ञान के अंदर बढी हुअी दुनिया बहुत छोटी हो गअी है। आपको मालूम होगा कि अेबीसीनिया पर जब अिटली ने हमला किया था तो वह मसला फौरन लीग ऑफ नेशन्स के सामने आया था। अुसी तरह से जब जापान और मैन्चूरिया के बीच में झगडा चल रहा था तो अेक पडोसी देश के नाते अुस वक्त हिंदुस्तान की अंग्रेजी हुकूमत ने बर्मा रोड को बंद किया और अिसीलिये कि वहां की लडाअी यहां तक न आ जाय। आज के विज्ञान के कारण दुनिया बहुत छोटी हो गअी है। अेक जगह कहीं कुछ हुआ तो अुसके असरात सारी दुनिया पर होने लगे हैं। अैसी हालत में दुनिया आज जमहुरियत की तरफ जा रही है। जमहूरियत और अिन्सानियत के बीच गहरे ताल्लुकात ह। अिसलिये जमहूरियत पर भरोसा रखनेवाले दुनिया के लोगों को सज्जग रहना पडता है कि अगर किसी मुल्क के अंदरूनी मामले का असर जमहूरियत पर बूरी तरह से होनेवाला है तो अुसकी तरफ दुनिया का ख्याल खींचे, और अगर जमहूरियत पर तेज रफ्तार से कहीं हमला होने के अिमकानात मालूम हो रहे हों तो अुनको रोकने की कोशिश करें, अिसी लिहाज से आज हिंदुस्तान ने अिस पाक-अमेरिका मुआहदे की मुखालिफत की है। अिसमें शक नहीं कि यह पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। कोअी भी मुल्क अपने देश की आजादी के लिहाज से किसी दूसरे मुल्क के साथ मुआहदा करने के लिये आजाद होता है। लेकिन अेशिया के बिरादरीन मुल्कों का यह फर्ज हो जाता है कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामले में अगर अिन्कलाबी तबदिली आ रही हो और अुससे दूसरे मुल्कों को खतरा पैदा होता हो तो अुसकी मुखालिफत करें क्योंकि यह कहा जाता है कि पडोसी मुल्क सब से पहला दुष्मन बन सकता है। अिस चीज को मद्देनजर रखते हुअे हिंदुस्तान की हुकूमत ने यह जरूरी समझा कि पाकिस्तान के अंदर पैदा हुअी अिस बैनूल अव्वामी तबदीलियों के खिलाफ आवाज बुलंद की जाय, अगर कोअी यह कहे कि झोंपडी के अंदर की बिजली को बंद करके मैं अपनी झोंपडी की हिफाजत करना चाहता हूं तो वह अेक बहुत बडी गलती कर रहा है। झोंपडी के अंदर की बिजली बंद करने

के माने झोंपडी की हिफाजत करना नहीं है बल्कि अुसको जलाकर खाक करने की तदाबीर अेख्त्यार करना है। अमेरिका और पाकिस्तान के बीच का यह मुआहदा अच्छे ख्यालात से बनाया गया होता तो अुसकी मुखालिफत करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन असली बात अलग है। अिसीलिये हिंदुस्तान के वजीरे आजम ने जो आज अेशिया के अमन का पैगम्बर है, दुनियाकी अिन्सानियत जो आज तबाही की तरफ जा रही है अुसको बचानेकी जो कोशिश कर रहा है, अुसने अेशियाके लोगोंको तबाही से बचनेके लिये यह आवाज अुठाअी है। अुसका मनशा यह नहीं है कि पाकिस्तान की अव्वाम के साथ अच्छे जजबात पैदा न किये जायें, बल्कि मैं यह कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान में जो आंतरराष्ट्रीय हालात पैदा हो गये हैं, अुनके बारे में पाकिस्तान की अव्वामको जागृत करने के लिये हिंदुस्तान अपना अेक सही फर्ज अदा कर रहा है, और अिस फर्ज को अदा करनेके लिये ही हिंदुस्तान की हुकूमत ने हिंदुस्तानकी असेंब्लियों के जरियेसे अिस सवाल को अव्वामके सामने रखा है। मुझे खुशी है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की पालिसी के खिलाफ अिस मुआहदे के होने से दो घंटे पहले तक सियासी जमातों की तरफसे हिंदुस्तान में बहुत मुखालिफत होती रही। लोग कहते थे कि जवाहरलाल नेहरू की सियासी पालिसी बहुत खराब है, दुनिया के दूसरे ममालिक से अलग रहकर आज की दुनिया के पालिटिक्स में हम अपनी आजादी को कैसे कायम रख सकते हैं। अभी अभी अेक ऑनरेबल मेंबर ने यह कहा कि हिंदुस्तानके अंदर फौजी ट्रेनिंग का अिन्तजाम किया जाना चाहिये। मैं कहूंगा कि दुनिया का कोअी भी मुल्क अपनी फौजी ताकत को बढाकर अपने मुल्क की हिफाजत नहीं कर सकता। हमने देखा है कि ८० करोड डालर का सामान चीन को दिया गया लेकिन नेशनलिस्ट सरकार वहां न अपने को कायम रख सकी न अमेरिका अपना अिरादा पूरा कर सका बल्कि अमेरिका ने खुद अपने हाथोंसे वहां अपनी कबर खुदवाली। आज पाकिस्तान को भी अिसी तरहकी अिमदाद दी जा रही है लेकिन अुसका नतीजा वही होनेवाला है जो हमने चायना में देखा। अिसलिये हमको किसी से हथियार की अिमदाद नहीं लेना है। आपको मालूम होगा कि अभी अभी कलकत्तेके चेंबर आफ कामर्स की मीटिंग में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कम्यूनिटी प्रोजेक्टस और दीगर स्कीम्सके बारे में कहा कि अिसके बाद अगर हमको अमेरिकासे या दूसरे किसी मुल्कसे अिमदाद न मिले तोभी हमें अुसकी परवाह नहीं, चाहे हमारे तरक्की रुक जाय लेकिन अिस तरह की अिमदाद लेकर अमेरिकाके जजबात को हिंदुस्तान में बढने का मौका हम नहीं देंगे और अपनी आजादी को साम्राजियतके हाथ बेचना कभी पसंद नहीं करेंगे। अिसलिये आज हम देख रहे हैं कि हिंदुस्तान की तमाम सियासी जमातें अिस मौके पर मुत्तफिक हो गअी हैं। अिसलिये अिसी मौके पर अपोजीशन पार्टी के मेंबरों पर मैं सही तौर पर यह वाजे करना चाहता हूं कि अगर आप सचमुच अिससे मुत्तफिक हैं और आप समझते हैं कि मुल्क अेक संकट की परिस्थिति से गुजर रहा है तो आपके वह रोजमर्रा के हडताल, वह शोरगुल वह नारेबाजी अेकदम खतम कर दीजिये और वह अुस वक्त तक खतम कर दीजिये जिस वक्त तक हम यह न समझें कि हमारा मुल्क अब खतरे से बाहर हो गया है। अुसके बाद फिर हम अपने अपने ख्यालात को लेकर मैदान में आयेंगे और अपना अपना काम करते रहेंगे। यही मौका है, जब कि हम अेक होकर अपने मुल्क की हिफाजत कर सकते हैं। मुझे अुम्मीद है कि हिंदुस्तान के लोग ही नहीं बल्कि पूरे दुनियाके लोग अिस पाक-अमेरिका मुआहदे के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करेंगे और मुझे यह भी अुम्मीद है कि पाकिस्तान का यह मुआहदा अुसी तरह से खतम होगा जिस तरह से चीन और अमेरिका का मुआहदा खतम हुआ और जिस तरह से चीन में अमेरिका ने

अपनी कबर खुदवा ली अुसी तरह से अेक दिन पाकिस्तान में भी वह भी अपनी कबर खुदवा लेगा। अिन चंद अल्फाज के साथ मैं अपनी तकरीर खतम करता हूं।

Shri V. B. Raju: Mr. Speaker, Sir, The purpose of this resolution is not to make.....

شری داجی شنکر (عادل آباد) - یہ بہت اہم رزولیوشن ہے اس لئے یا تو تلگو میں بولنے کی اجازت دی جائے یا اردو میں بولیں - تلگو میں بھی کہیں تو ایوان کے بہت سے لوگ سمجھ سکتے ہیں -

مسٹر چیرمن :- میں سمجھتا ہوں کہ مسئلہ کی انٹر نیشنل اہمیت کے لحاظ سے انگریزی میں تقریر کرنا اچھا ہوگا -

شری داجی شنکر - اردو میں بولنے پر بھی سمجھ سکتے ہیں -

Shri V. B. Raju: Our purpose is not to make any particular nation target of our discussion and create prejudice. We are not discussing on this resolution with a view to make either America or Pakistan the target; but by raising our voice we want to dissuade the Governments of those two countries from doing, what we consider, a wrong thing.

The modern state, as it is constituted, is becoming centralised in its structure and dictatorial in its outlook. It has become very undependable and as such we want to appeal to the democratic elements both in America and Pakistan to compel their Governments to withdraw from the proposed pact or alliance, and, on the other hand, to see that the World Governments would sit around a table and find out a way to prevent any war taking place in the world. That, as I understand, is the main purpose of our resolution.

From this House, I would like to point out to the Peoples of America,—if our message could reach them or if this cry should reach them—that for more than hundred years they have actually adopted the same policy as Pandit Nehru has been adopting during these seven years. It has been said by their respected Ex-Presidents and by the President too that they do not like to entangle themselves into unnecessary cliques or into world confusion. The famous Jefferson, on his assumption of the Presidentship, had said: "Friendship with all nations and entangling alliances with none". Similarly, President Washington had declared "Europe as a set of primary interests which to us have a very remote interest. It must be unwise to ask to implicate ourselves". Today, Our Pandit Nehru too is saying the same thing:

" Friendship with all nations of the world and no joining with any entangling cliques ". Pandit Nehru's approach is gradually being realised by certain elements in America. The Ex-Administrator of Marshal Plan Administration has said, in connection with the transaction of giving wheat to India wherein the Americans wanted some sort of returns out of that bargain, that only immature Americans would like to make Indian school-children salute the U.S. Flag each day as the price of the wheat to India. Mr. Paul Haffman reiterated the same when he said : " By giving Indians wheat, you cannot expect the Indian Children salute the American Flag. If you want to purchase it like that, you are in a Fool's Paradise ". This is not an Indian's saying; it is an American himself saying this. The present President has said that America should be understood from its history, not from stray pages from History. I would like the President himself to read the American history and know what better America can do in the context than India as placed today. That is all what I would like to appeal to the Americans from the floor of this House.

Indians feel today, and the public opinion as represented by Pandit Nehru is, that India, particularly the Asiatic nations, should not be involved in a war. The anxiety of America, as it appears to us, is to shift the war theatre from Europe to Asia. I have gone through certain books of eminent people wherein it has been recorded that America wants to fight Russia on the Asian soil; that America would prefer to throw the atom bomb on Peiking then on Moscow ; and that America is interested in racialism as a home problem. When big people say about America in those terms, we begin to suspect the approach that America has taken towards Pakistan.

I would ask, what does Pakistan gain by entangling itself in the international confusion ? Why is it that Pakistan is cutting adrift from the Asian-African Block ? Why is it that America is trying to break the Arab-League by forming associations with Turkey, Iraq and Pakisthan ? What necessity has arisen today for Pakistan to go away from the main current ? Certainly I feel and I am even afraid that the people of Pakistan are not fully informed of all these developments ; I am further afraid that because of certain unemployment situation in Pakistan and also because of the economic unstability in Pakistan people are

simply made to believe that there are certain elements in India which are not sure of Pakistan's existence. I would like to appeal to the people of Pakistan and impress upon them that we in India,—all the three main political parties in India—believe that Pakistan is a reality. If Pakistan wants to join India in a federal way, it is for Pakistan to voluntarily do it and India, on its own accord, will never think of compelling Pakistan to join India. Pakistan is a making of India with her own hands, whether we liked it or not. Situated as we then were, we had to do it and it was history that compelled us to do it. The three important events that happened after world war II were the division of three countries; Germany, Korea and India. While there was voluntary division in India, Germany and Korea have been divided against the wishes of the people and that is the reason why those countries are going to be new causes for another World War. The results that emerged from the second World War have again become causes for a Third World War. But it shall not be the case with regard to India. Pakistan is the area which we have created: it is not because of America saying so or Russia asking us. We have created Pakistan with our own hands and the people of Pakistan should be convinced of our *bona fides*. We do not want to compel Pakistan to join us. Pakistan has itself got an economic interest by associating with India, particularly in regard to natural resources and canal waters. Canal waters is a very important problem—More than tanks, jeeps and other equipment, water and wheat are important to Pakistan. Pakistan people are not being educated on these lines. It is a pity.

I will now go a step further and say that mere platitudes or mere appeals or mere shedding of tears are not in themselves going to deter America in its plan for aggression. America is not interested in India; it is not interested in Pakistan: America is interested more in filling a particular vaccum. When we turn the pages of our History we find that in Asia there were three empires: the British the Dutch and the French. The Britishers by leaving India and Pakistan have created a vaccum and the British losing its hold in the middle-east have created a vaccum. The Dutch has left Indonesia and the French in spite of 55 per cent of more of war expenses being met by America has not been able to make any headway in Indo-China. That being the case, America wants to assume the role or fill the gap by itself. It is to be taken as

a practical reality. America does not like Asia uniting or the researgent nationalism in Asiatics. The fundamental tussel is between the industrial powers of the world and the powers of backward economy. The industrial powers of Europe had kept America; kept Asia; kept Africa and Australia, under their grip and had prospered so much that America itself had to struggle to come out of the grip of the European powers. What America did earlier, Asia is doing now. Let America recall its own history. Peoples of America had struggled to get out of the grip of the industrial powers: Asiatics are doing the same thing. From Turkey to Japan all the countries in Asia, all the nations of Asia, are struggling to come out of the grip of the European industrial powers. In this process, America is not helping us. America is placing before us a bogey of communism. Whether communism or no communism, whether capitalism or super-capitalism, one thing is certain that no one Nation today can exploit other nations. We have to believe that national integrity is the only real way of keeping peace in the wrold. How these nations have been created artificially is not a point for consideration now, but we accept certain geographical boundaries or certain Governments as realities and accept their integrity sand Sovereignty. As long as Soviet Russia and America do not respect this national integrity, both will be hated by the peoples of the world. We differ from Soviet also on this point. They also uphold the theory of "peace through strength." Let us not take sides when we argue here. We are Indians first. The signs of a cold war are coming nearer to the boundaries of India. We should speak as Indians with higher objectives that war should be averted once and for all. If we take sides with Soviet or America in this House and begin to argue, we do not have a true picture.

Scientific technology is being applied to war. Whether it is rightly applied or wrongly applied, the fact is--it is being applied. Soviet, America and some others want to take advantage by applying this scientific technology to war and they say "Peace Through Strength", whereas we say "Peace through Understanding." It is through collaboration. Misunderstanding or wrong understanding creates suspicion; suspicion creates fear; fear compels to armaments; armament takes to military action; military action or war brings degeneration. That is how the process takes place. Therefore, I wish there should be proper understanding between the different nations of the world and let there be

"Peace Through Understanding." The fundamentals of Pandit Nehru's policy are no entanglements in any cliques of the world and friendship with all nations. But why did America differ with India on this point? America also says that there should be peace; it also says there should be no entanglements in cliques. But then what is her present policy due to? We have to go to the root cause. Firstly, America did not like India speaking in favour of New China. America never expected that Pandit Nehru would be such an independent and firm personality who could call a spade a spade. Indias, speaking in favour of China for its inclusion in the United Nations Organization has not been very happy to America. The second thing is that India did not like that Macarthur should be given power to enter into North Korea. Thirdly, India did not like signing the Japanese peace treaty as per the draft prepared by America. On these three points, America has become dissatisfied.

We must now go to the root cause and find out what America wants us to do. I think America and India has both misunderstood each other. Without taking much time of the House, in a minute or two I say about a parable in this connection. One person had been to the philosopher Voltaire and said to him:" So and so is a good philospoher." Immediately, Voltaire said ' Yes, I know he is a fine man, a big man." But that person thereupon said: "But when I said to him that you are a good man, he called you a bad man. But how is it you call him a good man." Then Voltaire said: "We might have both misunderstood each other." I do not know if I am clear about the subtlety here. What Voltaire said was that the other person must be a scoundrel and 'I must be a gentleman.' That is how we might have misunderstood each other. America seems to have thought that India in its predicament or in the context of her present economic poverty will surrender its wider interests. We too might have misunderstood that America has good intentions to uphold our Democarcy. Otherwise, 7 years of friendship would not have ended like this. I am glad at least today we have understood each other. Though India does not want leadership of the Asian-African countries, the small nations in Asia and Africa do look to India for succour. America obviously does not like this and it is to remove India from this position that America is trying to set up Pakistan against India. Certainly, America is doing the greatest disservice to the freedom of ours. We do not want any nation to come and fall on our shoulders. We fought for Indonesia; We raised our voice for

Africa, Tunisia and South Korea and North Korea; wherever there was aggression we raised our voice. If America wants to belittle India or bring down India or coerce India, it is going to do a great mistake.

Lastly, I would say, let us not mix our home politics with the foreign politics. We will be committing a great mistake if we associate our home politics with foreign affairs. Let us see England and learn: whatever be their Home differences, in foreign policy matters, all the political parties come together. That is British Democracy. There is nothing wrong in copying some good elements of the British democracy. Therefore, let us see that we do not mix our home politics with foreign affairs and let us all follow one leader in facing this crisis. It is a great crisis and should our apprehensions come true, it is going to be the greatest disaster to the world.

శ్రీ జె. అనందరావు, (సిర్‌సిల్లా--జనరల్)

స్పీకర్, సర్,

గౌరవ సభ్యులు చాలమంది ఈ తీర్మానంపై ఉపన్యసించారు. ఈ తీర్మానం మనందరి సమిష్టి ప్రయోజనాలకు సంబంధించినది కాబట్టి దీనిలో ఎలాంటి భేదాలు లేకుండా ఉండాల ని తీర్మానం ప్రతిపాదించినవారియుక్క ఉద్దేశం

مسٹر چیرمن - آپ ہندی میں تقریر کریں -

شری جے- آنند راؤ- مسٹر اسپیکر سر- مجھے بڑی خوشی ہے کہ یہ ریزولیوشن یہاں لایا گیا اور اس پر بہت سے لوگوں نے اپنے متفقہ خیالات ظاہر کئے - لیکن اس کے ساتھ ساتھ چند ممبروں نے جو ریزرویشنس کئے ہیں ان پر دکھ بھی ہوتا ہے - اس قسم کے ریزرویشنس رکھنے سے کہ آئندہ فلاں قوتیں جارحانہ اقدامات کرنے والی ہیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا - ریزرویشنس کرتے وقت اس جانب کوئی توجہ نہیں دی گئی - انہوں نے اس چیز کو کنسیڈر (Consider) نہیں کیا کہ اندرونی اختلافات ہوسکتے ہیں - دیش کی بھلائی کے لئے مختلف نظریات ہوسکتے ہیں - ملک کی خوشحالی کے متعلق نظریات میں اختلاف ہوسکتا ہے - معاشی خوشحالی کے جو تصورات اور جو معیار ہم رکھتے ہیں اس میں اختلافات ہوسکتے ہیں - لیکن اس کے باوجود ہم بھی پیٹریاٹ (Patriot) ہیں ہم بھی محب وطن ہیں - اختلافات کے باوجود جب کوئی اگریشن (Aggression) ہم پر ہو تو سب کے سب ایک ہوکر اس کا مقابلہ کرسکتے ہیں - ٹریژری بنچس کے ایک آنریبل ممبر نے اس چیز کا اظہار کیا ہے کہ برٹش ڈیمو کریسی کی یہ شاندار روایات ہیں کہ جب بدیشی حملہ آور

"Peace Through Understanding." The fundamentals of Pandit Nehru's policy are no entanglements in any cliques of the world and friendship with all nations. But why did America differ with India on this point ? America also says that there should be peace ; it also says there should be no entanglements in cliques. But then what is her present policy due to ? We have to go to the root cause. Firstly, America did not like India speaking in favour of New China. America never expected that Pandit Nehru would be such an independent and firm personality who could call a spade a spade. Indias, speaking in favour of China for its inclusion in the United Nations Organization has not been very happy to America. The second thing is that India did not like that Macarthur should be given power to enter into North Korea. Thirdly, India did not like signing the Japanese peace treaty as per the draft prepared by America. On these three points, America has become dissatisfied.

We must now go to the root cause and find out what America wants us to do. I think America and India has both misunderstood each other. Without taking much time of the House, in a minute or two I say about a parable in this connection. One person had been to the philosopher Voltaire and said to him :" So and so is a good philospoher." Immediately, Voltaire said ' Yes, I know he is a fine man, a big man." But that person thereupon said : "But when I said to him that you are a good man, he called you a bad man. But how is it you call him a good man." Then Voltaire said : "We might have both misunderstood each other." I do not know if I am clear about the subtlety here. What Voltaire said was that the other person must be a scoundrel and 'I must be a gentleman.' That is how we might have misunderstood each other. America seems to have thought that India in its predicament or in the context of her present economic poverty will surrender its wider interests. We too might have misunderstood that America has good intentions to uphold our Democarcy. Otherwise, 7 years of friendship would not have ended like this. I am glad at least today we have understood each other. Though India does not want leadership of the Asian-African countries, the small nations in Asia and Africa do look to India for succour. America obviously does not like this and it is to remove India from this position that America is trying to set up Pakistan against India. Certainly, America is doing the greatest disservice to the freedom of ours. We do not want any nation to come and fall on our shoulders. We fought for Indonesia ; We raised our voice for

Africa, Tunisia and South Korea and North Korea ; wherever there was aggression we raised our voice. If America wants to belittle India or bring down India or coerce India, it is going to do a great mistake.

Lastly, I would say, let us not mix our home politics with the foreign politics. We will be committing a great mistake if we associate our home politics with foreign affairs. Let us see England and learn : whatever be their Home differences, in foreign policy matters, all the political parties come together. That is British Democracy. There is nothing wrong in copying some good elements of the British democracy. Therefore, let us see that we do not mix our home politics with foreign affairs and let us all follow one leader in facing this crisis. It is a great crisis and should our apprehensions come true, it is going to be the greatest disaster to the world.

శ్రీ జె. అనందరావు, (సిర్సిల్లా--జనరల్)

స్పీకర్, సర్,

గౌరవ సభ్యులు చాలమంది ఈ తీర్మానంపై ఉపన్యసించారు. ఈ తీర్మానం మనందరి సమిష్టి ప్రయోజనాలకు సంబంధించినది కాబట్టి దీనిలో ఎలాంటి భేదాలు లేకుండా ఉండాలని తీర్మానం ప్రతిపాదించినవారియొక్క ఉద్దేశం

مسٹر چیرمن - آپ هندی میں تقریر کریں -

شری جے- آنند راؤ- مسٹر اسپیکر سر- مجھے بڑی خوشی ہے کہ یہ ریزولیوشن یہاں لایا گیا اور اس پر بہت سے لوگوں نے اپنے متفقہ خیالات ظاہر کئے - لیکن اس کے ساتھ ساتھ چند ممبروں نے جو ریزرویشنس کئے ہیں ان پر دکھ بھی ہوتا ہے - اس قسم کے ریزرویشنس رکھنے سے کہ آئندہ فلاں قوتیں جارحانہ اقدامات کرنے والی ہیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا - ریزرویشنس کرتے وقت اس جانب کوئی توجہ نہیں دی گئی - انہوں نے اس چیز کو کنسیڈر (Consider) نہیں کیا کہ اندرونی اختلافات ہوسکتے ہیں - دیش کی بھلائی کے لئے مختلف نظریات ہوسکتے ہیں - ملک کی خوشحالی کے متعلق نظریات میں اختلاف ہوسکتا ہے - معاشی خوشحالی کے جو تصورات اور جو معیار ہم رکھتے ہیں اس میں اختلافات ہوسکتے ہیں - لیکن اس کے باوجود ہم بھی پیٹریاٹ (Patriot) ہیں ہم بھی محب وطن ہیں - اختلافات کے باوجود جب کوئی اگریشن (Aggression) ہم پر ہو تو سب کے سب ایک ہوکر اس کا مقابلہ کرسکتے ہیں - ٹریژری بنچس کے ایک آنریبل ممبر نے اس چیز کا اظہار کیا ہے کہ برٹش ڈیمو کریسی کی یہ شاندار روایات ہیں کہ جب بدیشی حملہ آور

آتے ھیں تو اختلافات کے باوجود تمام پارٹیاں ایک ھو جاتی ھیں۔ جب ھم وھاں کی پارلیمنٹ کے نمونے اختیار کررھے ھیں تو اس سلسلہ میں بھی اختیار کرنا چاھیئے۔ جو اعلی قسم کی ڈیموکریسی کی مثال انہوں نے دی ھے اس کے لئے میں انہیں مبارک باد دیتا ھوں کہ وہ اس قسم کا جذبہ رکھتے ھیں۔ ایسے ھی جذبہ سے ھم کام کریں تو ھماری جمہوریت آگے بڑھ سکتی ھے۔ ھم ایکتا کے ساتھ ایسے دیشوں کا مقابلہ کرسکتے ھیں جو ھم پر حملہ کرنا چاھتے ھیں۔ جو لوگ فرقہ پرستی کی آڑ لیکر ملک کو غلام بنانا چاھتے ان کو کبھی اس کا موقع نہیں دینا چاھیئے۔

امریکہ کی جو پالیسی حال میں ظاھر ھوئی وہ کوئی انسیڈینٹل (Incidental) یا اتفاق نہیں ھے۔ بلکہ اس کے پیچھے پوری دنیا کو غلام بنانے کا منصوبہ ھے۔ یہی نہیں بلکہ جیسا کہ ایک آنریبل ممبر نے کہا سوویٹ روس اور چائینا پر حملہ کرکے اون کو ختم کرنا ھے۔ میں اون دیشوں کی وکالت کرنے کے لئے نہیں کھڑا ھوا ھوں۔ آج دنیا میں دو گروپس بن گئے ھیں ایک سامراجی اور دوسرے سوشلسٹ۔ امریکہ جو سامراجی گروپ سے تعلق رکھتا ھے وہ اس انداز سے دیکھ رھا ھے کہ دوسروں کو غلام بنا کر اونکی معاشی مدد کرکے اون کو لوٹا جائے۔ لیکن اس میں ناکام ھورھا ھے۔ آج اوس کو اپنا مال کھپت کرنے کے لئے مارکٹ کی ضرورت ھے۔ کیونکہ جو دائرہ اوس کے مال کی کھپت کے لئے تھا وہ کم ھوتا جارھا ھے۔ چائینا ایک بہت بڑا ملک ھے وہ اس کے ھاتھ سے نکل گیا اسی طرح سے سوویٹ رشیا اور دیگر مشرقی ممالک میں اوس کے لئے کوئی جگہ باقی نہیں رھی۔ اس وجہ سے وہ ھندوستان اور پاکستان میں اڈے جانے کی کوشش کررھا ھے۔ اون کو معاشی مدد دیکر۔ اونکی خوشی حالی کی باتیں کر کے۔ وھاں کی انڈسٹریز کو ڈیولپ کرنے کے نام پر میٹھی میٹھی باتیں کرکے اون کو ھمیشہ کے لئے کچل کر رکھدینا چاھتا ھے۔ کوریا کی جنگ ختم ھونے کے بعد اوس کے جنگی ساز و سامان کے کھپت کیلیئے کوئی مارکٹ نہیں مل رھا ھے۔ اس کے علاوہ آج امریکہ جیسے سرمایہ دار ملکوں میں بھی بیروزگاری کا مسئلہ شروع ھوگیا ان امپلائمنٹ کا مسئلہ شروع ھوگیا ھے۔ بہت سے لوگ بیروزگار بنتے جارھے ھیں۔ اس لئے اپنے کارخانوں کو چالو رکھنے کے لئے اپنے مال کی کھپت کرنے کے لئے اپنے ملک کی اکنامک کرائسس (Economic cricis) کو دور کرنے کے لئے وہ مجبور ھے کہ کسی نہ کسی طرح دوسرے ملکوں میں مستقل طور پر اپنا سکہ بٹھائے۔ اس پر ھمیں خاص طور پر غور کرنا چاھیئے۔ آنریبل موور آف دی ریزولیوشن نے اکنامک ریلیشنس کے تعلق سے ایک سینٹنس جو پہلے رکھا گیا تھا بعد میں نے اوس کو وتھ ڈرا کرلیا۔ میں یہ نہیں کہنا چاھتا کہ اوس کو ویسا ھی رکھنا چاھئے تھا۔ لیکن اون کا منشا یہ ھوگا کہ اکنامک تعلق رکھنے پر بھی یہ نتیجہ نکلیگا امریکہ ھم کو غلام بنالیگا۔ کمیونٹی پراجکٹ کے نام پر انڈسٹریز کے نام پر جو پیسے دئے جارھے ھیں اوسکے نتیجے کے طور پر کمیونٹی پراجکٹ ڈولپمنٹ کے نام پر امریکہ کے اسپائز (Spies) اور

ایجنٹ یہاں آجائینگے اور تعلیم یافتہ طبقہ میں پرچار کرینگے - انڈسٹریز کو ڈولپمنٹ کرنے کے بہانے - پیداوار میں اضافہ کرنے کے بہانے وہ یہاں گھس آئینگے - اور اون حملہ آوروں کو موقع ملیگا کہ یہاں کے بہت سے لوگوں کو اپنے ایجنٹ کے طور پر استعمال کریں - جس طرح کہ ماضی میں سامراج یہاں آیا تھا اوسی طرح اب بھی آنا چاھتا ھے - اس سے ھم کو آگاہ ھوجانا چاھئے - کیونکہ اس سے پہلے بھی دو سو سال قبل ایسا ھی ھوا تھا - ھم دوسو سال کی غلامی کے بعد آزادی کی جنگ لڑ کر آزادی حاصل کئے ھیں اوس زمانے میں جب برٹش آئے تھے انہوں نے بھی ایسا ھی کہا تھا کہ ھم تجارت کیلئے آئے ھیں - وہ لوگ اوس وقت تاجروں کے بھیس میں آئے تھے اوس وقت بھی ایسا ھی معلوم ھوتا تھا کہ ھمارے ھندستانی بھائیوں کو کہ یہ لوگ حکومت کرنے کے لئے نہیں آئے ھیں - ھمارے سامنے پچھلی ھسٹری موجود ھے کہ کس طرح ھوتے ھوتے یہ تاجر حکمران طبقہ بنگئے - اسی طرح سے آج جو امریکن ایڈ (American aid) دیجارھی ھے اور جو ملٹری اکسپرٹس آرھے ھیں اونکے پیچھے سامراجی مقصد مضمر ھے - لیکن آج یہ مقصد کامیاب نہیں ھوسکتا کیونکہ آج ھمارے عوام بیدار ھوچکے ھیں - انہوں نے لڑائی لڑ کر آزادی حاصل کی ھے - امریکی سامراج یہ تو نہیں کہہ رھا ھے کہ وہ ھماری آزادی کو لے لیگا لیکن ایک الگ طریقہ سے وہ یہاں آنا چاھتا ھے - کیونکہ اکنامک امداد کی وجہ سے اسکو کئی گوناگوں سہولتیں حاصل رھینگی - وہ کسی نہ کسی طرح سے کسی نہ کسی ڈھنگ سے یہاں آجائیگا - رپورٹ میں جن اکنامک رشتوں کا ذکر کیا گیا ھے اوسمیں زھر چھپا ھوا ھے - ھم کو اس سے آگاہ ھوجانا چاھئے - جیسا کہ میں نے اس سے پہلے عرض کیا ھے یہ تمام باتیں ھونے والی ھیں -

مسٹر چیرمن - ھم اب اڈجورن ھوتے ھیں - پیر کے دن ۲-۳۰ پر پھر ملینگے -

***The House then adjourned till Half Past Two of the Clock on Monday, the 22nd March* 1954.**
